जबलपुर बुधवार 12 अगस्त 2026 > शक संवत 1948, श्रावण कृष्ण पक्ष अमावस्या
वर्ष 32 अंक 46 मूल्य ₹ 3.00 > पेज 12 > आर.एन.आई. पंजीयन नम्बर 64561/96
www.swatantramat.com

अब हर रोज दर्पण ⏩ 3

स्वतंत्र मत

स्वतंत्र मत में विज्ञापन देने के लिए 9589920250 पर कॉल करें * स्वतंत्र मत का अंक प्राप्त करने के लिए 9301359695 पर कॉल करें।

मौसम
अधिकतम तापमान 27.0°C
न्यूनतम तापमान 23.6°C
सूर्योदय - 5.46 | सूर्यास्त - 6.45

रामकली बनीं महिला विभाग जिलाध्यक्ष ... ⏩ 5

स्कूलों में लड़कियों को पीरियड्स और ... ⏩ 7

15 अगस्त को सिंगरौली जिले में शुष्क दिवस घोषित ... ⏩ 8

'वंदे मातरम' को भी मिला 'राष्ट्रगान' जैसा कानूनी संरक्षण

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक को दी मंजूरी

नई दिल्ली

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को एक विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसके तहत जानबूझकर राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' के गायन में बाधा डालना या उसे रोकना अपराध माना जाएगा। सरकार के एक बयान में कहा गया है कि इसे वही कानूनी सुरक्षा मिलेगी जो अभी राष्ट्रीय गान को हासिल है। राष्ट्रपति की सहमति से राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026, कानून बन गया है। लोकसभा ने 30 जुलाई को विधेयक पारित किया था, जबकि राज्यसभा ने इसे एक दिन पहले ही मंजूरी दे दी थी। इस विधेयक के अंतर्गत वंदे मातरम को राष्ट्रगान 'जन गण मन' के समान दर्जा दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह में पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम गाया जाएगा। इससे पहले, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम के तहत जानबूझकर राष्ट्रगान (जन गण मन) गाने से रोकना या ऐसे गायन में लगे किसी भी सभा में अशांति पैदा करना प्रतिबंधित था। इन अपराधों के लिए अधिकतम तीन साल की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती थी, जबकि दूसरी और उसके बाद की हर सजा के लिए कम से कम एक साल की कैद का प्रावधान था। पूर्ववर्ती

कानून में राष्ट्रगान को समान संरक्षण प्रदान नहीं किया गया था। इस वर्ष की शुरुआत में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया था कि जब राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत एक साथ बजाए जाएं तो वंदे मातरम के सभी छह श्लोक पहले गाए जाएं। 28 जनवरी के एक आदेश में, गृह मंत्रालय ने राष्ट्रगान गाने के लिए प्रोटोकॉल का पहला सेट जारी किया, जिसमें निर्देश दिया गया कि इसके छह छंद, जिनकी अवधि 3 मिनट और 10 सेकंड है, राष्ट्रपति के आगमन, राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राज्यपालों के भाषण जैसे आधिकारिक समारोहों में गाए जाएंगे।

बिल में क्या कहा गया था?

बिल में कहा गया था, अभी वंदे मातरम के गायन के अपमान को रोकने के लिए कोई खास कानूनी प्रावधान नहीं है, जबकि इसे राष्ट्रीय गीत का सम्मान प्राप्त है। इसलिए, किसी व्यक्ति को जानबूझकर राष्ट्रीय गीत गाने से रोकने या ऐसे गायन में लगी किसी सभा में बाधा डालने से रोकने के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 3 में संशोधन करके राष्ट्रीय गीत को भी इसके दायरे में लाने का प्रस्ताव है, ताकि ऐसे कार्यों को दंडनीय बनाया जा सके। विधेयक में आगे कहा गया है कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने 24 जनवरी, 1950 को कहा था कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित गीत वंदे मातरम, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी, को राष्ट्रगान जन गण मन के समान सम्मान दिया जाएगा और उसे उसके बराबर दर्जा प्राप्त होगा।

अब सिर्फ 7 घंटे में पहुंचेंगे छत्तीसगढ़

मप्र के आठ जिलों से गुजरेगा 15 हजार करोड़ का नया एक्सप्रेस-वे

भोपाल (स्वतंत्र मत)

मध्यप्रदेश सरकार ने जबलपुर-भोपाल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और जबलपुर-मंडला-छत्तीसगढ़ सीमा 6-लेन मार्ग परियोजना को हरी झंडी दे दी है। इस घोषणा के साथ ही अब रायपुर और भोपाल की दूरी कम हो जाएगी। बता दें कि अभी तक रायपुर से भोपाल पहुंचने में 14 से 15 घंटे लग जाते हैं। वहीं अब घटकर यह सफर 6 से 7 घंटे होने वाला है। मध्यप्रदेश सरकार के ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का फायदा छत्तीसगढ़ के तीन शहरों का मिलने वाला है। बता दें कि सरकार ने इन दो प्रोजेक्ट के लिए 15000 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के तहत छत्तीसगढ़ के कवर्धा, बेमेतरा, सिमगा से रायपुर शहर जुड़ेगा। वहीं मध्यप्रदेश में यह

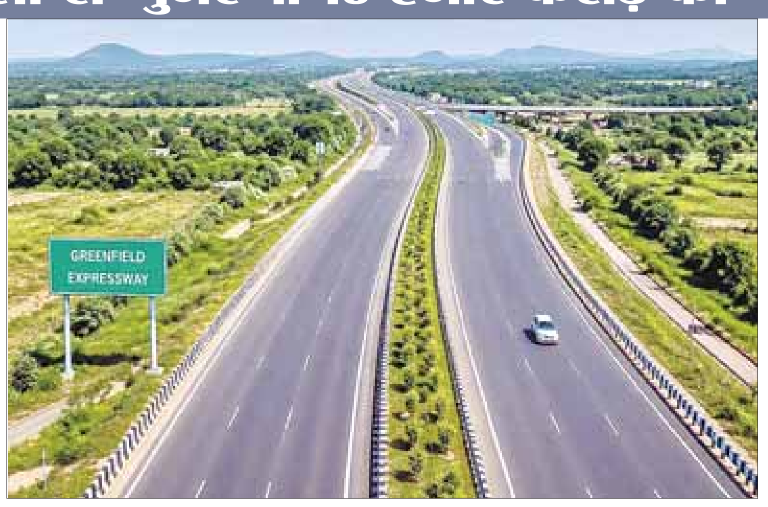

ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भोपाल, सागर, दमोह, जबलपुर, मंडला से होते हुए छत्तीसगढ़ में एंट्री होगी। जिससे भोपाल और रायपुर के बीच कनेक्टिविटी और मजबूत हो जाएगी। बता दें कि यह पूरा इंटर-स्टेट कॉरिडोर मध्य भारत की सबसे बड़ी लाइफलाइन बनने जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे पर वाहनों की अधिकतम गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। वर्तमान में भोपाल से जबलपुर की दूरी 320 किलोमीटर है, जो इस ग्रीनफील्ड राजमार्ग के निर्माण के बाद घटकर 255 किलोमीटर रह जाएगी। इसके चलते दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय छह से सात घंटे से कम होकर ढाई से तीन घंटे रह जाएगा। इसके अलावा जबलपुर से छत्तीसगढ़ सीमा तक चिल्पी घाट के रास्ते छह-लेन सड़क सुधार के लिए 2,500 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे जबलपुर और रायपुर के बीच का सफर भी सात से आठ घंटे के बजाय साढ़े तीन से चार घंटे में पूरा होगा।

6-लेन एक्सप्रेसवे में बदलेगा हाईवे

मध्य प्रदेश सरकार ने जबलपुर से छत्तीसगढ़ सीमा चिल्पी घाट से होते हुए रायपुर तक जाने वाले इस हाईवे को 6-लेन एक्सप्रेसवे में बदला जाएगा। यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को आपस में जोड़ने वाला सबसे मुख्य व्यापारिक रूट है। यह प्रोजेक्ट भोपाल-जबलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का ही हिस्सा है, जिसे आगे तक विस्तार करने का प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश सरकार ने पास कर दिया है। इस एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रतिघंटे तक रहेगी। जिससे समय की बचत होगी।

व्यापार और पर्यटन को मिलेगी नई रफ्तार

यह महा-कॉरिडोर दोनों राज्यों के प्रमुख व्यापारिक मार्गों को सीधे जोड़ेगा। मध्य प्रदेश के भोपाल, जबलपुर, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, दमोह, सागर, डिंडोरी और मंडला के साथ-साथ छत्तीसगढ़ के रायपुर, कवर्धा, बेमेतरा और सिमगा जैसे शहरों को इस परियोजना का सीधा लाभ पहुंचेगा। राज्य सरकार की 5,500 करोड़ रुपये की टाइगर कॉरिडोर योजना के तहत यह मार्ग कान्हा, बांधवगढ़ और पन्ना राष्ट्रीय उद्यानों को भी आपस में जोड़ेगा। इससे पर्यटकों के लिए इन मुख्य अभ्यारण्यों तक पहुंचना आसान हो जाएगा।

कम हो जाएगी जबलपुर-रायपुर की दूरी

इसके अलावा मध्यप्रदेश सरकार के ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण हो जाने के बाद जबलपुर से रायपुर की दूरी भी बहुत कम हो जाएगी। गौरतलब है कि अभी जबलपुर से रायपुर पहुंचने में 7 से 8 घंटे लग जाते हैं वहीं प्रस्तावित 6-लेन कॉरिडोर बनने के बाद यह यात्रा समय मात्र 3.5 से 4 घंटे का रह जाएगा। इससे लोगों राहत मिलेगी। बता दें कि इस प्रोजेक्ट से दोनों शहरों के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही छत्तीसगढ़ आने वाले पर्यटकों को भी लाभ होगा।

20 हेक्टेयर भूमि पर बनाया जाएगा नेशनल सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट

केबिनेट ने रानी दुर्गावती और रानी अवन्ती बाई पुरस्कार राशि बढ़ाने का लिया फैसला

भोपाल (स्वतंत्र मत)

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। मंत्रि-परिषद ने किसान कल्याण वर्ष में किसानों को बड़ी सौगात देते हुए भारत सरकार के अंतर्गत गठित उपक्रम नेशनल सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए सीहोर जिले की इछावर तहसील के गांव भाउखेड़ी में 20 हेक्टेयर भूमि स्थायी पट्टे पर आवंटित किये जाने का निर्णय लिया है। प्रदेश के सर्वांगीण विकास, जन-स्वास्थ्य सुदृढ़ीकरण, बुनियादी ढांचे के विस्तार और महिला सशक्तिकरण को गति देने के लिए 47 हजार 990 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है। इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 28,083.47 करोड़ रुपये और आयुष्मान भारत योजना के लिए 12 हजार 123 करोड़ 81 लाख रुपये शामिल हैं। मंत्रि-परिषद ने भोपाल को मेट्रोपोलिटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की दिशा में ठोस पहल करते हुए भोपाल-विदिशा मार्ग के 2-लेन से 4-लेन उन्नयन एवं निर्माण के लिए 1757.57 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है। मंत्रि-परिषद ने भोपाल बायपास को 6-लेन बनाने के दृष्टिगत भोपाल बायपास- टोल टैक्स शुल्क संग्रहण की अनुमति 2031 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रि-परिषद ने स्थानीय मजदूरों और क्षेत्र के रहवासियों को लाभांश वितरण के लिए वन विभाग द्वारा संचालित संयुक्त वन प्रबंध समितियों को लाभांश का प्रदाय योजना के तहत वर्ष 2030-31 तक निरंतर रखे जाने की 918 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है। मंत्रि-परिषद ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए हर तरह की परिस्थितियों में समाज सेवा करने वाली महिलाओं के लिए रानी दुर्गावती राज्य स्तरीय पुरस्कार की राशि भी 2 लाख रुपये करने की स्वीकृति दी है और रानी अवंती बाई राज्य स्तरीय वीरता पुरस्कार की राशि को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने की मंजूरी दी है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय को वेतन भत्तों मानदेय आदि के लिए ब्लाक ग्राण्ट योजना के आगामी 05 वर्षो वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक निरंतर संचालन के लिए 795 करोड़ 59 लाख रूपये की स्वीकृति दी है।

चीफ इंजीनियर 50 हजार की रिश्वत लेते पकड़ाया

रीवा। रीवा लोकायुक्त की टीम ने मंगलवार को लोक निर्माण विभाग, संभाग रीवा में कार्रवाई की। टीम ने प्रभारी मुख्य अभियंता (चीफ इंजीनियर) कैलाश कुमार लच्छे को 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा। उनके अशासकीय सहयोगी धर्मवीर भारती को भी पकड़ा गया। कार्रवाई सिविल लाइन स्थित शासकीय आवास में अटल पार्क के सामने हुई। लोकायुक्त पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता सोनू सिंह की फर्म निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच करती है। आरोप है कि फर्म को लोक निर्माण विभाग में काम दिलाने के बदले कैलाश कुमार लच्छे हर महीने एक लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे थे।

पन्ना की खदान में मिला 50 लाख का हीरा

पन्ना। पन्ना जिले की एक खदान में 16.96 कैरेट का जेम क्वालिटी हीरा मिला है। एक्सपर्ट्स ने इसकी अनुमानित कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा बताई है। हीरे को सरकारी दफ्तर में जमा करा दिया गया है। इसे अगली नीलामी में रखा जाएगा। इससे मिली रकम रॉयल्टी और टैक्स काटने के बाद खदान मालिकों को दी जाएगी। खदान में 7 साझेदार- अखिलेश पाल, संतोष कुशवाहा, शर्मन पाल, अरुण रावत, हेमचंद्र पाल, जमुना पाल और हीरालाल कुशवाहा हैं। अखिलेश ने करीब दो साल पहले अपने खेत में हीरा खदान के लिए पट्टा लिया था। मंगलवार को बारिश के बाद खदान से निकले मलबे का जायजा लेने पहुंचे तो मिट्टी के ढेर में पानी से धुलकर चमकता हीरा दिखा।

डेरा मुखी की 10 साल की सजा बरकरार

चंडीगढ़। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने करीब 26 साल पुराने रेप के मामले में निचली अदालत से दोषी ठहराए गए डेरा प्रमुख बाबा धनवंत सिंह की 10 साल की कठोर कैद की सजा को बरकरार रखा है। इसके साथ ही पीड़िता को 6 लाख रुपए मुआवजा देने के भी आदेश दिए। कोर्ट ने कहा- पीड़िता को आरोपी के हाथों यौन शोषण का सदमा झेलना पड़ा। इसके बाद उसे लंबे समय तक न्याय की तलाश करनी पड़ी।

शिवसेना के धनुष-बाण पर घमासान

उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को घेरा

नई दिल्ली। शिवसेना के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर चल रहे विवाद में उद्धव ठाकरे गुट ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी। शिवसेना (यूबीटी) की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि विधानसभा में किसी गुट का अलग होना अपने आप में राजनीतिक पार्टी के विभाजन का सबूत नहीं है। उनके मुताबिक, चुनाव आयोग ने इसी आधार पर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना माना और 'धनुष-बाण' चुनाव चिह्न दिया। यह फैसला कानूनन गलत है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना भी शामिल हैं। मंगलवार को अंतिम सुनवाई के तीसरे दिन कपिल सिब्बल ने उद्धव गुट की ओर से अपनी दलीलें रखीं। उद्धव गुट ने 2024 में सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की थीं। इनमें चुनाव आयोग के 17 फरवरी 2023 के फैसले को चुनौती दी गई है। आयोग ने इस फैसले में शिंदे गुट को मूल शिवसेना माना था और उसे 'धनुष-बाण' चुनाव चिह्न दिया था। सिब्बल ने कहा कि केवल विधायी दल में विभाजन के आधार पर राजनीतिक पार्टी में विभाजन नहीं माना जा सकता। उन्होंने संविधान की दसवीं अनुसूची के पुराने प्रावधान का हवाला दिया।

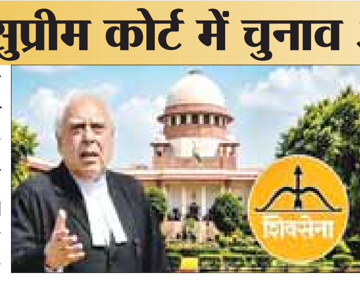

विद्यार्थियों के मामले में गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार: बिरला

नई दिल्ली (वार्ता)। लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को कहा कि सरकार विद्यार्थियों के मामले में सदन में चर्चा और गृह मंत्री के जवाब को लेकर सहमत है तथा इस मुद्दे पर सदन की कार्यवाही बाधित नहीं की जानी चाहिए। प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे कि 20 जुलाई को राजधानी में पुलिस कार्रवाई की जवाबदेही तय की जाये और इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह सदन में बयान दें। समाजवादी पार्टी के सदस्य अयोध्या के राममंदिर में चढ़ावा चोरी

की जांच की मांग को लेकर नारे लगाते हुए शोरगुल करने लगे। बिरला ने कहा कि सरकार और विपक्ष दोनों को मिलकर सहमति बनानी चाहिए। सदन की कार्यवाही चलनी चाहिए। विपक्ष की जो प्रमुख मांग है कि विद्यार्थियों के मामले में गृह मंत्री जवाब दें या चर्चा में भाग लें, सरकार ने इस पर सहमति जतायी है। कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजीजू ने स्पष्ट रूप से कहा है कि गृह मंत्री विद्यार्थियों के मामले में जवाब देने को तैयार हैं। बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण होता है, वह व्यक्तिगत रूप से भी कई बार आग्रह कर चुके हैं कि प्रश्नकाल की कार्यवाही बाधित न की जाये। इसमें सदस्य जनता के हितों से जुड़े सवाल पूछते हैं और सरकार तथा कार्यपालिका की जवाबदेही निर्धारित की जाती है।

इसरो को नासा ने भेजा औपचारिक न्योता

चांद पर एक साथ बसने की तैयारी में भारत-अमेरिका

नई दिल्ली

भारत और अमेरिका ने अंतरिक्ष क्षेत्र में अपने सहयोग को नई ऊंचाई देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को अपने मून बेस प्रोग्राम में शामिल होने का औपचारिक न्योता दिया है। यह पहल चंद्र अन्वेषण, अंतरिक्ष विज्ञान और मानव अंतरिक्ष उड़ान के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत कर सकती है। यह प्रस्ताव भारत-अमेरिका नागरिक अंतरिक्ष संयुक्त कार्य समूह (सीएसजेडब्ल्यूजी) की बेंगलूरू स्थित इसरो मुख्यालय में हुई 9वीं बैठक के दौरान सामने आया। बैठक में दोनों देशों ने नागरिक और वाणिज्यिक अंतरिक्ष सहयोग के साथ-साथ भविष्य के विज्ञान और मानव अंतरिक्ष उड़ान से जुड़ी तकनीकों पर भी चर्चा की। अमेरिकी दूतावास के मुताबिक, दोनों पक्षों ने आर्टिमिस समझौते के तहत खुले वैज्ञानिक

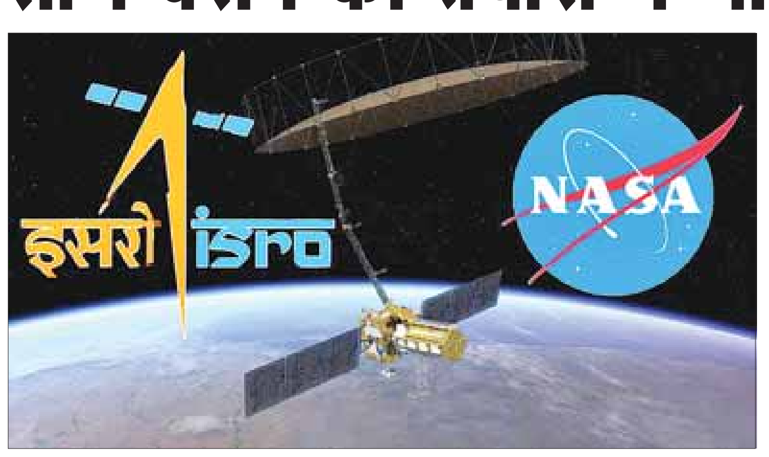

डाटा साझा करने पर सहयोग आगे बढ़ाने की दिशा में भी सहमति जताई। नासा का मून बेस कार्यक्रम चंद्रमा पर स्थायी और दीर्घकालिक मानव उपस्थिति की दिशा में अमेरिका की बड़ी योजनाओं का हिस्सा है। नासा के मुताबिक, अमेरिका चंद्रमा पर एक सतत लूनर आउटपोस्ट स्थापित करने की दिशा में काम कर रहा है। इस योजना के तहत अंतरराष्ट्रीय साझेदारों को भी शामिल किया जा रहा है। ऐसे में इस कार्यक्रम में इसरो की संभावित भागीदारी भारत के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारत ने चंद्रयान-3 के जरिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के पास सफल सॉफ्ट लैंडिंग कर अपनी तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन किया था। अब भारत-अमेरिका का यह सहयोग चंद्रमा पर भविष्य के वैज्ञानिक और मानव मिशनों के लिए नई संभावनाएं खोल सकता है।

बेंगलूरू में हुई अहम बैठक

भारत-अमेरिका नागरिक अंतरिक्ष संयुक्त कार्य समूह की बैठक के शुरुआती सत्र को इसरो के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉ. वी. नारायणन तथा भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने संबोधित किया। दोनों ने भारत और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष सहयोग को और व्यापक बनाने की जरूरत पर जोर दिया। बैठक की सह-अध्यक्षता भारत की ओर से यूआर राव सैटेलाइट सेंटर के निदेशक एम. शंकरन ने की। अमेरिकी पक्ष की ओर से अमेरिकी विदेश विभाग और नासा के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

छिंदवाड़ा में बड़ा विमान हादसा टला नकुलनाथ-हरीश चौधरी सुरक्षित

छिंदवाड़ा (स्वतंत्र मत)। छिंदवाड़ा एयर स्ट्रिप पर मंगलवार सुबह बड़ा विमान हादसा टल गया। पूर्व सांसद नकुलनाथ और मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी को लेकर भोपाल के लिए उड़ान भरने वाला विमान इंजन में तकनीकी खराबी आने के कारण उड़ान नहीं भर सका। घटना के समय दोनों नेता विमान में सवार थे। जानकारी के अनुसार, नकुलनाथ और हरीश चौधरी को भोपाल में आयोजित कांग्रेस की बैठक में शामिल होना था। दोनों नेता मंगलवार सुबह छिंदवाड़ा एयर स्ट्रिप पहुंचे और विमान में सवार हुए। विमान को उड़ान के लिए तैयार किया गया और इंजन भी चालू हुआ। इसी दौरान विमान में तकनीकी खराबी सामने आई। विमान रनवे पर ही खड़ा रहा और उड़ान नहीं भर सका। इंजन में खराबी की जानकारी मिलते ही पायलट ने तत्काल विमान को उड़ाने का फैसला रोक दिया। इसके बाद नकुलनाथ और हरीश चौधरी समेत विमान में मौजूद स्टाफ को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। पायलट की सूझबूझ और समय रहते तकनीकी खराबी का पता चलने से बड़ा हादसा होने से बच गया। विमान के उड़ान भरने के बाद इंजन में खराबी आती तो स्थिति गंभीर हो सकती थी।

हत्या के समय अस्पताल में भर्ती था बेटा, फिर भी काटी 10 साल की जेल

हत्या के आरोप में आजीवन कारावास काट रहे पिता-पुत्र को मप्र हाईकोर्ट ने किया दोषमुक्त

जबलपुर (स्वतंत्र मत)। मप्र हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल व न्यायमूर्ति अवनींद्र कुमार सिंह की युगलपीठ ने हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे पिता और उसके दोनों बेटों को दोषमुक्त कर दिया। खास बात यह रही कि एक बेटा जितेंद्र यादव वारदात के समय झांसी के अस्पताल में भर्ती था, इसके बावजूद वह लगभग 10 साल 6 महीने जेल में रहा। हाईकोर्ट ने अपीलों पर सुनवाई करते हुए अभियोजन की कहानी में कई महत्वपूर्ण विसंगतियां पाईं। अभियोजन के अनुसार 13 नवंबर 2015 को राजेंद्र यादव अपने बेटों सत्येंद्र और जितेंद्र व 3 अज्ञात लोगों के साथ लाइसेंसी बंदूक, तलवार, फरसा और लाठी लेकर परमानंद यादव के घर पहुंचा था। आरोप था कि आरोपियों ने हमला किया, जिसमें परमानंद की मौत हो गई और परिवार के अन्य सदस्य घायल हुए। निवाड़ी की अदालत ने तीनों को विभिन्न धाराओं में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

बयानों में थे विरोधाभास

हाईकोर्ट ने पाया कि चार्जशीट में 3 अज्ञात आरोपियों के संबंध में धारा 173(8) के तहत आगे की जांच का उल्लेख नहीं था। ऐसे में धारा 147, 148, 302/149 और 323/149 के तहत आरोप तय किए जाने पर भी सवाल उठता है। इधर शिकायतकर्ता और अन्य गवाहों के बयानों में विरोधाभास थे। पांच घायल गवाहों की मेडिकल रिपोर्ट रिकार्ड में होने के बावजूद अभियोजन उन्हें कोर्ट में साबित नहीं कर सका। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के सामने कथित हथियार भी पेश नहीं किए गए। डॉक्टर ने जिरह में माना कि चोटों से यह राय नहीं दी गई थी कि मृत्यु हत्या के कारण हुई, चोट पत्थर या सड़क के गड्ढे में गिरने से भी संभव थी। जितेंद्र के अस्पताल में भर्ती होने की पुष्टि डॉक्टर, नर्स और वार्ड ब्वाय ने की।

सत्येंद्र के शरीर पर भी 3 चोटें मिली थीं। राजेंद्र ने घटना के समय खेत में सिंचाई करने की बात कही थी। कस्टडी रिपोर्ट के अनुसार सत्येंद्र 2 साल 10 महीने 5 दिन और राजेंद्र एक साल 8 माह 2 दिन जेल में रहे। जितेंद्र 10 साल 6 महीने से जेल में था। हाईकोर्ट ने तीनों को दोषमुक्त कर दिया और जितेंद्र को किसी अन्य मामले में जरूरत न होने पर रिहा करने का निर्देश दिया गया।

भारत सिंह यादव बने भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक

जबलपुर (स्वतंत्र मत)। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक हेमंत खंडेलवाल की सहमति से भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक किशन सिंह भटोल ने सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा की है। भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ में जबलपुर से वरिष्ठ नेता भारत सिंह यादव को प्रदेश सह संयोजक नियुक्त किया है। श्री भारत सिंह यादव पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रहें है साथ ही भाजपा संगठन के विभिन्न दायित्व का निर्वहन किया है। इनकी नियुक्ति पर मंत्री राकेश सिंह, राज्य सभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि, सांसद आशीष दुबे, भाजपा प्रदेश कोषाध्यक्ष अखिलेश जैन, जिला अध्यक्ष रत्नेश सोनकर, ग्रामीण अध्यक्ष राजकुमार पटेल आदि ने बधाइयां प्रेषित की हैं।

होटल मैनेजर पर जानलेवा हमला करने वाले बदमाश को पुलिस ने दबोचा

लॉर्डगंज थाना पुलिस की कार्यवाही, पिस्टल-कारतूस बरामद

जबलपुर (स्वतंत्र मत)। लॉर्डगंज थाना पुलिस ने होटल मैनेजर पर जानलेवा हमला करने के आरोपी 25 वर्षीय कुणाल पटेलको गिरफ्तार कर लिया है। बतां दें कि आरोपी कुणाल पटेल पर 5 हजार रुपए का इनाम घोषित था। वह जगदीश अखाड़ा क्षेत्र का निवासी है और कुख्यात छोटू चौबे गैंग का सक्रिय सदस्य बताया जाता है।

ये है पूरा मामला–जानकारी के अनुसार यह विवाद 26 जुलाई की रात शुरू हुआ था, जब कुणाल पटेल राइट टाउन स्थित अवलोकन इन होटल पहुंचा। उसने मैनेजर शिवम अग्रवाल पर लग्जरी कमरा देने का दबाव बनाया। मैनेजर ने कमरा खाली न होने और स्थानीय आईडी पर अकेले व्यक्ति को कमरा न देने के होटल के नियमों का हवाला दिया। इस पर कुणाल ने खुद को छोटू चौबे गैंग का सदस्य बताते हुए गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। अगले दिन, 27 जुलाई की रात मैनेजर शिवम अग्रवाल रानीताल फ्लाईओवर के पास बारिश से बचने के लिए खड़े थे। तभी कुणाल अपने साथी शनि के साथ वहां पहुंचा और पुरानी रंजिश के चलते जान से मारने की नीयत से उन पर तीन राउंड फायरिंग की। हालांकि, गोली मैनेजर को नहीं लगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए, जबलपुर के पुलिस अधीक्षक श्री सम्पत उपाध्याय (भा.पु.से.) ने आरोपी की गिरफ्तारी पर 5 हजार रुपए के इनाम की घोषणा की थी। एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया, जिसने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिरों की मदद से आरोपी की तलाश शुरू की। 10 अगस्त को मिली सटीक सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने रानीताल श्मशान घाट के पास दबिश दी और फरार इनामी बदमाश कुणाल पटेल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी कुणाल पटेल ने स्वीकार किया कि वारदात में इस्तेमाल की गई पिस्टल और कारतूस उसे गिरोह के सरगना छोटू चौबे ने दिए थे। कुणाल पटेल एक शातिर अपराधी है, जिसके खिलाफ रंगदारी, मारपीट, आर्म्स एक्ट और जुआ एक्ट के तहत कुल 6 गंभीर मामले दर्ज हैं। आरोपी को पकड़ने में लार्डगंज नवल आर्य थाना प्रभारी के नेतृत्व में उप निरीक्षक लेखराम नादोनिया, सउनि मनोज गोस्वामी, सउनि पुष्पराज परते, सउनि राजेश वर्मा, आरक्षक पंकज सनोडिया, हुलेश परस्ते, शुभम पटेल और रिषभ बर्मन की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

29 अगस्त को होगा संस्कारधानी समरसता कजलियां महोत्सव

जबलपुर (स्वतंत्र मत)। समरसता जैसे प्रमुख मानवीय और सामाजिक मूल्य की पहचान बन कर उभरे 'समरसता सेवा संगठन' द्वारा चौथे वर्ष भी संस्कारधानी जबलपुर में पूज्य संतों के सानिध्य में कजलियां महोत्सव का आयोजन आगामी 29 अगस्त को अपरान्ह 2 बजे से हनुमानताल सरोवर में किया जा रहा है। समरसता सेवा संगठन के कजलियां मिलन महोत्सव की विराटता को देखते हुए 12 दिन तक विविध विषयों की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। समारोह का श्रीगणेश सावन माह के तृतीय सोमवार 17 अगस्त को आद्य शंकराचार्य चौक स्थित समन्वय सेवा केन्द्र में भगवान भोलेनाथ के रुद्राभिषेक और कजलियां पात्र वितरण से होने जा रहा है। तदाशय की जानकारी समरसता सेवा संगठन के अध्यक्ष पवन पांडे, सचिव मनोज सेठ ने पत्रकार वार्ता में दी। इस अवसर पर पं रोहित दुबे, महाकौशल चेम्बर ऑफ़ कॉमर्स के अध्यक्ष रवि गुप्ता, अग्रवाल सभा के पूर्व अध्यक्ष कैलाश अग्रवाल बब्बा, सुरेश सराफ, पूर्व सचिव उज्जवल पचौरी उपस्थित रहे।

कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए अभय प्रताप सिंह

जबलपुर (स्वतंत्र मत)। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के समक्ष एवं जिला कांग्रेस कमेटी (ग्रामीण) के अध्यक्ष संजय यादव की सहमति से अभय प्रताप सिंह को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। इस अवसर पर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष सोनू दुबे, नेक नारायण सिंह, प्रमोद पटेल, रामेश्वर गिरी, दुर्जन पटेल, ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप पटेल, पणजी जैन सहित कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कांग्रेस प्रवक्ता विवेक यादव ने अभय प्रताप सिंह का कांग्रेस परिवार में स्वागत करते हुए कहा कि उनके कांग्रेस में शामिल होने से संगठन को मजबूती मिलेगी तथा कांग्रेस की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने में नई ऊर्जा मिलेगी।

प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थान ने भव्य तिरंगा यात्रा निकाली

जबलपुर (स्वतंत्र मत)। प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थान जबलपुर द्वारा मंगलवार को 'हर घर तिरंगा' अभियान के अंतर्गत भव्य तिरंगा यात्रा रैली का आयोजन किया गया। सर्व धर्म प्रार्थना सभा के उपरांत संस्थान परिसर से शिक्षक समूह एवं छात्राध्यापक समूह अनुशासित एवं पंक्तिबद्ध होकर तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। तिरंगा यात्रा संस्थान परिसर से प्रारंभ होकर कलेक्टर कार्यालय के सामने मुख्य मार्ग, हाईकोर्ट, कार्यालय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय तथा राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, शिक्षा मनोविज्ञान एवं संदर्शन महाविद्यालय के मार्ग से होते हुए पुनः संस्थान परिसर पहुंची। कार्यक्रम में छात्राध्यापक समूह द्वारा राष्ट्रभक्ति एवं तिरंगा अभियान से संबंधित पोस्टर तैयार किए गए। अभियान के अंतर्गत 470 छात्राध्यापकों द्वारा डॉ.प्रमोद श्रीवास्तव के पहल एवं मार्गदर्शन में संस्कृति मंत्रालय की वेवसाईट पर सेल्फी अपलोड कर तथा अपने-अपने समूहों में इसे बृहद संख्या में प्रसारित कर इस अभियान के प्रति अपना जुड़ाव प्रदर्शित किया। कार्यक्रम में संस्थान की प्राचार्यएफ. इक्का, संजीव अग्रवाल, ज्योत्सना दुबे, ललिता सप्रा, अर्चना दुबे आदि उपस्थित रहे।

रावेन्द्र कुमार वर्मा बने टंग ऑफ वार के प्रभारी

जबलपुर (स्वतंत्र मत)। एमपी पावर मैनेजमट कंपनी की केन्द्रीय क्रीड़ा एवं कला परिषद के महासचिव फिरोज कुमार मेश्राम ने जनसंपर्क अधिकारी कार्यालय में कार्यरत रावेन्द्र कुमार वर्मा को रस्साकशी (टंग ऑफ वार) खेल का प्रभारी नियुक्त किया है। यह नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगी। केन्द्रीय क्रीड़ा एवं कला परिषद के महासचिव फिरोज कुमार मेश्राम ने रावेन्द्र कुमार वर्मा को नई जिम्मेदारी मिलने पर शुभकामनाएं दी। रावेन्द्र कुमार वर्मा फुटबॉल, तैराकी और टग ऑफ वार के उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं। वे पिछले 15 वर्षों से अखिल भारतीय विद्युत क्रीहा नियंत्रण मंडन की टंग ऑफ बार प्रतियोगिता में एमपी पावर टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

दीवार में छेद कर ग्रहस्थी का सामान ले उड़े चोर

जबलपुर (स्वतंत्र मत)। खितौला थाने में लल्लूलाल कोल उम्र 51 वर्ष निवासी लखराम मोहल्ला ने रिपोर्ट दर्ज कर बताया कि वह अपने परिवार के साथ मजदूरी करने के लिये इंदौर जाता है। विगत दिवस जब वह अपने घर पहुंचा तो उसके घर का ताला खोलकर अंदर जाकर देखा दीवार में छेद था तथा कमरे का ताला भी टूटा हुआ था। अंदर जाकर देखा तो वीडियोकान कम्पनी की टीवी, होम थियेटर, 4 नग पीतल की थाली, कांसे की 7 थाली, 2 नग कासे के लोटा, 1 पीतल का हंडा, 1 तबेला, 1 प्रेस, चांदी का सिक्का, आलमारी में रखे नगदी 900 रूपये गायब थे। पुलिस ने मामले को जांच में लिया है।

प्रसंग सुरमाला अवार्ड में हुई 41 गीतों की नॉनस्टॉप प्रस्तुति

जबलपुर (स्वतंत्र मत)। रोशन तुम्हीं से दुनिया, आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, सुनो सजना पपीहे ने, सजनवा बैरी हो गए हमार, वह मेरी सह खुबां जैसे मनभावन गीतों ने सभागार में उपस्थित श्रोताओं का दिल जीत लिया इस प्रकार संस्था द्वारा आयोजित प्रसंग सुरमाला अवार्ड आयोजन में नगर के प्रतिष्ठित गायक कलाकारों ने शानदार 41 गीतों की नॉनस्टॉप प्रस्तुति की। जिसमें चयनित पांच अर्चना गोस्वामी, पीडी दीक्षित, जेपी चौहान, विनय कुमार, लखन राही को उत्कृष्ट गायन के लिए प्रसंग सुरमाला अवार्ड से सम्मानित किया गया। आयोजन में निर्णायक की भूमिका ख्यातिलब्ध कवि सलिल परोहा सलिल एवं सतीश पाठक ने निभाई। अन्य गायक कलाकारों में विवेक त्रिपाठी, विपिन जैन,संजय मिश्रा, प्रशांत पाठक, टिम्मी पाजी,विजय कुमार, सुधीर श्रीवास्तव, संदीप बनोधा,मानिक चक्रवर्ती, चंद्रकांत पुरोहित, कमलेश सोनी, नम्रता जैन, गुरविंदर सिंह, राजेश अग्रवाल, आनंद साहू ,सुशील श्रीवास्तव, चंद्रशेखर, अश्विनी कुमार, सलिल तिवारी,माया पांडे ने शानदार गीतों की प्रस्तुति दी। तत्पश्चात हितकारिणी कन्या विद्यालय की प्राचार्या प्रीति पाठक खुरासिया के निर्देशन में विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा शानदार तिरंगा नृत्य प्रस्तुत किया। इस अवसर पर डा.सुधीर तिवारी, मृगेंद्र नारायण सिंह, अर्चना मलैया, निर्मला तिवारी आदि ने बच्चों को संस्था की ओर से प्रशस्ति पत्र मिष्ठान एवं पारितोषिक वितरित किए गए साथ ही प्राचार्य का मानपत्र, शाल श्रीफल से अभिनंदन किया गया।

हास्य सम्राट केके नायकर ने अपनी प्रस्तुति से दर्शकों को खूब हंसाया। संस्था के संस्थापक इंजी.विनोद नयन की परिकल्पना के अनुसार इस आयोजन में नवाचार किया गया जिसमें कोई उद्घोषक नहीं था। आयोजन को सफल बनाने में डॉ.मकबूल अली, बसंत कुमार शर्मा, डॉ.रानू रूही, डॉ.विनीता पाण्डेय विनीत का सहयोग रहा। संयोजन जी.व्ही.अग्रवाल ने किया।

फर्जी तरीके से बेची जमीन, पीड़ित ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार

जबलपुर (स्वतंत्र मत)। जमीन धोखाधड़ी के मामले को लेकर पीड़ितों ने एडिशनल एसपी आयुष जाखड़ को ज्ञापन सौंपकर मामले में व्यापक जांच और कड़ी कार्यवाही की मांग की। पीड़ित नीरज सोनी ने आरोप लगाया कि उन्होंने मनीष त्रिपाठी से प्लॉट खरीदा था, लेकिन खरीद के करीब एक महीने बाद उस पर बुलडोजर चला दिया गया और बाद में जमीन सरकारी होने की बात सामने आई। उनका कहना है कि वर्ष 2022 में पकड़े गए आरोपी ने अपने बयान में कथित तौर पर कई अन्य लोगों के शामिल होने और उनके कहने पर काम करने की जानकारी दी थी, बावजूद इसके अब तक उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ितों ने मांग की कि आरोपी को रिमांड पर लेकर उसके पुराने बयानों के आधार पर अन्य आरोपियों की पहचान की जाए और धोखाधड़ी की रकम की रिकवरी कराई जाए। वहीं संदीप जैन ने आरोप लगाया कि वर्ष 2009 में जिस व्यक्ति की मौत हो चुकी है, उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी वर्ष 2019 में इस्तेमाल कर करमेता क्षेत्र में जमीन की बिक्री की गई। उन्होंने कहा कि केवल एक आरोपी की गिरफ्तारी से न्याय नहीं मिलेगा। दूसरी ओर, एडिशनल एसपी आयुष जाखड़ ने शिकायतकर्ताओं को मामले की गंभीरता से जांच कराने का आश्वासन दिया। पुलिस अधिकारी के अनुसार, शिकायत में जमीन को पहले भी 14-15 लोगों को कथित तौर पर फर्जी तरीके से बेचे जाने की बात सामने आई है। मामले में एफआईआर दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है और पुलिस अब दस्तावेजों, रजिस्ट्रियों व उपलब्ध साक्ष्यों की जांच कर अन्य संलिप्त लोगों के खिलाफ भी कार्यवाही की दिशा में आगे बढ़ेगी।

अभा कायस्थ महासभा ने मनाया हरियाली महोत्सव

जबलपुर (स्वतंत्र मत)। पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढावा देने के उद्देश्य से खुदीराम बोस जी की पुण्य तिथि पर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा द्वारा पौधारोपण किया गया। प्रकृति का संतुलन बनाये रखने के लिये वृक्षारोपण आज के समय की सबसे बडी जरूरत है पेड न सिर्फ हमे ऑक्सीजन देते है बल्कि भावी पीढी को एक स्वस्थ वातावरण भी प्रदान करते है, पौधा लगाना ही काफी नहीं बल्कि एक मॉ की तरह उसकी देखभाल और सुरक्षा करना भी हमारा कर्तव्य होता है। उक्त आशय के उद्गार अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष चमन श्रीवास्तव ने व्यक्त किये। मुख्य अतिथि के रूप में मेघा पॅवार एवं समाजसेवी डिम्पी विश्वकर्मा ने भी पौधोपण किया। इस अवसर पर प्रदेश महांमत्री सुनील श्रीवास्तव, युवा जिला अध्यक्ष विवेक खरे, महिला जिलाध्यक्ष शिखा श्रीवास्तव, जिला महामंत्री अमिश्री खरे, जिला वरिष्ठ अध्यक्ष डॉ सोनल खरे आदि उपस्थित रहे।

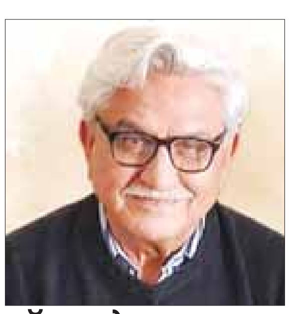

डॉ. मनोज पाराशर का निधन

जबलपुर (स्वतंत्र मत)। मेडिकल कॉलेज के पूर्व विभागाध्यक्ष (मेडिसिन) एवं सुख सागर मेडिकल कॉलेज के पूर्व डीन डॉ. मनोज पाराशर का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे विगत कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। डॉ. पाराशर अपने छात्र जीवन में सदैव गोल्ड मेडलिस्ट रहे एवं उनके पढ़ाए हुए छात्र देश-विदेश में अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दे रहे हैं। डॉ. पाराशर की दोनों पुत्रियों अमेरिका में सफल डॉक्टर हैं। अंतिम यात्रा 13 अगस्त गुरुवार को जय नगर स्थित आवास से दोपहर 1 बजे ग्वारीघाट मुक्तिधाम को प्रस्थान करेगी।

जनसुनवाई में पहुंची 81 शिकायतें

जबलपुर । आम जनता की शिकायतों एवं समस्याओ के त्वरित निराकरण हेतु मंगलवारपुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस कप्तान सम्पत उपाध्याय द्वारा जन सुनवाई की गयी। जन सुनवाई मे 81 शिकायतें प्राप्त हुईं।

बलिदान स्थल से विरासत पथ तक, बाइकर्स ने जाना गोंडवाना

विश्व आदिवासी दिवस पर हुआ अनूठा बाइक एक्सपीडिशन और हेरिटेज वॉक

जबलपुर (स्वतंत्र मत)। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जबलपुर स्थित राजा शंकर शाह एवं कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान स्थल से मंडला के रामनगर स्थित चौगान तक 18 बाइकर्स ने बाइक एक्सपीडिशन किया।

बारिश के बीच वन आच्छादित मार्ग से गुजरते हुए बाइकर्स ने गोंडकालीन विरासत, ग्रामीण संस्कृति और आदिवासी आतिथ्य का अनुभव किया। रविवार सुबह राजा शंकर शाह-कुंवर रघुनाथ शाह संग्रहालय से मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड के साहसिक गतिविधि के संयुक्त संचालक डॉ. एसके श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर रविशंकर राय, एमपीटी के क्षेत्रीय प्रबंधक अनूप शर्मा मार्केटिंग हेड योगेंद्र रिछारिया, तरुण मिश्र, पर्यटन प्रबंधक सहित अधिकारियों ने फ्लैग ऑफ कर रैली को रवाना किया। आयोजन मप्र टूरिज्म बोर्ड, जबलपुर पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद तथा होम स्टे ऑनर्स वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में हुआ।

आदिवासी सत्कार से परिचित हुए युवा

बाइकर्स मंडला स्थित एमपीटी रिजॉर्ट पहुंचे, जहां लंच के बाद जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद मंडला के सीईओ कपिल तिवारी ने रैली को रवाना किया। टीम रामनगर के मोती महल पहुंची, जहां पर्यटन सखियों ने चावल-हल्दी से तिलक लगाकर स्वागत किया। इसके बाद बाइकर्स ने गोंडकालीन विरासत का भ्रमण किया और चौगान के निकट ग्रामीण संस्कृति आधारित होम स्टे में रात्रि विश्राम किया। सोमवार को बाइकर्स ने काला पहाड़ में हेरिटेज वॉक किया और आदिवासी व्यंजनों का स्वाद लेने के बाद जबलपुर लौटे। स्मार्ट सिटी कार्यालय में प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिह्न प्रदान किए गए। होम स्टे ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष शरद दीक्षित ने बताया कि आयोजन का उद्देश्य आदिवासी गौरव, संस्कृति और स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को जन-जन तक पहुंचाने के साथ हेरिटेज एवं इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है।

जीईसी छात्राओं ने प्रस्तुत किया बिहू

जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्राओं तानिया बारमाटे, रुति उइके, मासूम हर्दे और शिवानी टेकाम ने असमी लोकनृत्य बिहू की प्रस्तुति दी। प्रस्तुति संघ संयोजक अजय कुमार माझी के मार्गदर्शन में हुई। रैली रवाना होने से पहले प्रतिभागियों ने 'जय सेवा, जय जोहार' का जयघोष किया और राजा शंकर शाह एवं कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान को नमन किया।

कानून की जानकारी हर नागरिक के लिए जरूरी

किसी भी सभ्य, लोकतांत्रिक और संगठित समाज की सफलता केवल आर्थिक विकास या तकनीकी प्रगति से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से भी होती है कि उसके नागरिक कानून के प्रति कितने जागरूक, जिम्मेदार और अनुशासित हैं। विधिक ज्ञान केवल अधिवक्ताओं, न्यायाधीशों या कानून के विद्यार्थियों तक सीमित नहीं होना चाहिए। प्रत्येक छात्र, शिक्षक, अभिभावक और नागरिक के लिए कानून की सामान्य जानकारी आवश्यक है।

आज का छात्र, कल का जिम्मेदार नागरिक

आज का छात्र ही कल का मतदाता, प्रशासक, वैज्ञानिक, शिक्षक, न्यायाधीश, अधिवक्ता, जनप्रतिनिधि या उद्यमी बनेगा। यदि उसे प्रारंभ से संविधान, कानून, नागरिक अधिकारों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की संतुलित जानकारी मिले, तो वह जीवन में अधिक जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ निर्णय ले सकेगा।

'कानून की अनभिज्ञता' बहाना नहीं

विधि का एक सामान्य सिद्धांत है, कानून की अनभिज्ञता किसी के लिए बहाना नहीं हो सकती। अर्थात प्रत्येक नागरिक से अपेक्षा की जाती है कि वह कानून के अनुरूप आचरण करे। किसी कानून के उल्लंघन के बाद केवल यह कहना कि उसे कानून की जानकारी नहीं थी, व्यक्ति को कानूनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करता।

अधिकारों के साथ कर्तव्यों की समझ

नागरिकों को अपने अधिकारों की जानकारी होना जितना जरूरी है, उतना ही आवश्यक अपने कानूनी दायित्वों और सीमाओं को समझना भी है। विधिक मर्यादा का उल्लंघन करने पर दंडात्मक या अन्य कानूनी परिणाम हो सकते हैं। जागरूक नागरिक वही है जो अधिकारों का उपयोग करते हुए कानून और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का भी पालन करे।

न्यायपालिका, संविधान की संरक्षक

सर्वोच्च न्यायालय संविधान की सर्वोच्चता, कानून के शासन और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। न्यायपालिका के माध्यम से नागरिकों को न्याय प्राप्त करने का संवैधानिक मार्ग मिलता है। यह व्यवस्था नागरिक अधिकारों की सुरक्षा और विधि के शासन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है।

स्कूलों से शुरू हो विधिक शिक्षा

शिक्षकों और अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि बच्चों और युवाओं में कानून के प्रति सम्मान, अनुशासन और जागरूकता विकसित करें। विद्यालयों और महाविद्यालयों में संविधान, नागरिक कर्तव्यों, साइबर कानून, यातायात नियम, महिला एवं बाल संरक्षण तथा पर्यावरण संबंधी कानूनों की बुनियादी जानकारी दी जानी चाहिए।

कानून का ज्ञान, मजबूत लोकतंत्र की पहचान

आज आवश्यकता है कि विधिक शिक्षा को केवल एक विषय न मानकर जीवनोपयोगी ज्ञान के रूप में देखा जाए। जब परिवार, विद्यालय और समाज मिलकर कानून के प्रति सम्मान और जागरूकता का वातावरण बनाएंगे, तभी ऐसा भारत निर्मित होगा जहां अधिकार और कर्तव्य में संतुलन, न्याय के प्रति सम्मान और कानून के प्रति जिम्मेदारी कायम रहेगी। यही जागरूक नागरिक और मजबूत लोकतंत्र की पहचान है।

रोहिणी प्रसाद तिवारी
एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट

कृषि से डिजिटल कनेक्टिविटी तक

भारत की सामाजिक-आर्थिक संरचना में गांवों की भूमिका हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। देश की बड़ी आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और कृषि, श्रम, हस्तशिल्प तथा लघु उद्योगों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को मजबूती देती है। हालांकि स्वतंत्रता के समय ग्रामीण भारत गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और खाद्यान्न संकट जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा था। आज वही गांव सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल सुविधाओं के विस्तार के साथ बदलाव की नई कहानी

लिख रहे हैं।

कृषि, खाद्यान्न संकट से आत्मनिर्भरता तक

आजादी से पहले भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर थी, लेकिन जमींदारी जैसी व्यवस्थाओं, सिंचाई की कमी, पारंपरिक तकनीक और कम उत्पादकता ने किसानों की स्थिति कमजोर कर रखी थी। अकाल और भुखमरी ग्रामीण जीवन की बड़ी समस्याएं थीं। स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार, सिंचाई परियोजनाओं, हरित क्रांति, कृषि मशीनीकरण और नई तकनीकों ने कृषि का स्वरूप बदला। आज भारत खाद्यान्न उत्पादन में दुनिया के प्रमुख देशों में शामिल है और कृषि अब भी करोड़ों ग्रामीण परिवारों की आजीविका का आधार है।

शिक्षा, निरक्षरता से डिजिटल शिक्षा तक

औपनिवेशिक दौर में आम जनता और विशेषकर ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। स्वतंत्रता के समय साक्षरता का स्तर बेहद कम था। आज स्कूलों के विस्तार, सर्व शिक्षा अभियान, डिजिटल माध्यमों और विभिन्न सरकारी योजनाओं ने ग्रामीण शिक्षा की तस्वीर बदली है। हालांकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और डिजिटल संसाधनों तक समान पहुंच अभी भी बड़ी चुनौती है।

स्वास्थ्य, सीमित सुविधाओं से बेहतर पहुंच तक

कभी ग्रामीण भारत सामान्य बीमारियों और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से जूझता था। आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, आयुष्मान भारत, टेलीमेडिसिन और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार ने दूरदराज के क्षेत्रों में उपचार की संभावनाएं बढ़ाई हैं। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि भी स्वास्थ्य क्षेत्र में हुई प्रगति को दर्शाती है।

सड़क और कनेक्टिविटी से विकास की रफ्तार

ग्रामीण विकास में सड़कें और परिवहन महत्वपूर्ण आधार हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सहित विभिन्न प्रयासों से गांवों को शहरों, बाजारों, स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों से जोड़ने का काम हुआ है। सड़क के साथ-साथ मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट ने ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल दुनिया से जोड़ दिया है।

लघु उद्योग, गांवों में रोजगार की नई राह

कृषि के साथ हस्तशिल्प, हथकरघा, खाद्य प्रसंस्करण और एमएसएमई ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों और छोटे उद्यमों ने विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर बढ़ाए हैं।

विकास की अगली मंजिल

ग्रामीण भारत ने अभाव से अवसर तक लंबी यात्रा तय की है, लेकिन मंजिल अभी बाकी है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, किसानों की आय, रोजगार, महिला सशक्तीकरण और डिजिटल समानता पर निरंतर काम जरूरी है। गांवों का मजबूत होना केवल ग्रामीण विकास नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर और समावेशी भारत की आधारशिला ळें।

बेटी की सुरक्षा, सबकी जिम्मेदारी

बेटियों की सुरक्षा हर परिवार की प्राथमिकता है, लेकिन सुरक्षा का अर्थ उनकी स्वतंत्रता पर रोक लगाना नहीं होना चाहिए। आज की बदलती दुनिया में बेटियों को घर की चारदीवारी में सीमित रखने के बजाय उन्हें आत्मविश्वासी, सजग और परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम बनाना जरूरी है। समस्या बेटियों के बाहर निकलने में नहीं, बल्कि उन्हें दुनिया को समझने और सही निर्णय लेने के लिए तैयार न करने में है।

बेटियां जैसे-जैसे बड़ी होती हैं, उनकी समझ और जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। छोटी उम्र में उन्हें गुड टच-बैड टच, सुरक्षित और असुरक्षित व्यवहार तथा बिना झिझक 'नहीं' कहने के बारे में समझाना चाहिए। किशोरावस्था में आत्मरक्षा का बुनियादी प्रशिक्षण, ऑनलाइन और ऑफ लाइन खतरों की जानकारी तथा आपात स्थिति में मदद लेने की समझ देना जरूरी है।

बेटियों को घर से बाहर निकलते समय परिवार को अपनी जानकारी देने, जरूरी फोन नंबर याद रखने और किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सहायता लेने की आदत डालनी चाहिए। सुनसान स्थानों से बचना, अनजान लोगों पर तुरंत विश्वास न करना और खतरा महसूस होने पर तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचना भी सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

आपात स्थिति में 112 अखिल भारतीय आपातकालीन सहायता नंबर है। महिलाओं के लिए 181, बच्चों के लिए 1098 और साइबर अपराध की शिकायत के लिए 1930 पर सहायता ली जा सकती है। बेटियों को सोशल मीडिया पर निजी जानकारी साझा करने, अनजान लिंक खोलने और अपरिचित लोगों से ऑनलाइन संपर्क में सावधानी बरतने की जानकारी भी देनी चाहिए।

सबसे जरूरी है कि परिवार ऐसा माहौल बनाए जहां बेटियां अपनी परेशानी बिना डर और झिझक के बता सकें। सुरक्षा डर पैदा करके नहीं, बल्कि जागरूकता, आत्मविश्वास और सही प्रशिक्षण से मजबूत होती है।

अमोतिका टोप्पो

कक्षा दसवीं
हितकारिणी कन्या उ.मा. शाला, बीटी तिराहा, गढ़ा, जबलपुर।

न्यायपालिका, लोकतंत्र के संतुलन की मजबूत कड़ी

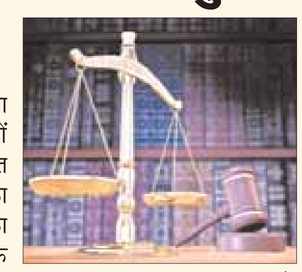

लोकतंत्र केवल चुनाव कराने की व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह संविधान, कानून, अधिकारों और संस्थाओं के बीच संतुलन पर आधारित शासन प्रणाली है। इस व्यवस्था में न्यायपालिका की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि शासन संविधान के अनुरूप चले और प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा हो। इसलिए स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका को लोकतंत्र की मजबूत आधारशिला माना जाता है। भारत में संविधान सर्वोच्च है और सरकार के सभी अंगों को उसके दायरे में रहकर काम करना होता है। न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करती है और आवश्यकता पड़ने पर ऐसे कानूनों या सरकारी निर्णयों की न्यायिक समीक्षा कर सकती है, जो संविधान के प्रावधानों के विपरीत हों। इससे सत्ता के मनमाने इस्तेमाल पर नियंत्रण बना रहता है और संवैधानिक व्यवस्था मजबूत होती है। लोकतंत्र में नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो न्यायपालिका उसके लिए न्याय का मार्ग खोलती है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की रिट संबंधी शक्तियां नागरिक अधिकारों की रक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम हैं।

लोकतंत्र में विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उनका क्रियान्वयन करती है और न्यायपालिका कानूनों की संवैधानिकता तथा विवादों पर निर्णय देती है। इन संस्थाओं के बीच शक्तियों का संतुलन लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाता है। न्यायपालिका का उद्देश्य सरकार चलाना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि शासन कानून और संविधान की सीमाओं में रहे।

हरियाली से सुरक्षित होगा भविष्य

पेड़ हैं तो जीवन है, पेड़ नहीं तो भविष्य नहीं। यह कथन आज पर्यावरणीय संकट के दौर में पूरी तरह सार्थक दिखाई देता है। पेड़-पौधे हमें छाया और फल देने के साथ शुद्ध वायु, जल संतुलन और स्वस्थ वातावरण प्रदान करते हैं। इसलिए पेड़ों को धरती के फेफड़े भी कहा जाता है।

पेड़ हैं प्रकृति के सच्चे प्रहरी

पेड़ वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो जीव-जगत के लिए अनिवार्य है। वे वर्षा चक्र को बनाए रखने, मिट्टी के कटाव को रोकने और भूजल स्तर को संतुलित रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जंगल वन्यजीवों और पक्षियों का प्राकृतिक आवास हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई जैव विविधता के लिए गंभीर खतरा बन रही है।

कटते पेड़, बढ़ती पर्यावरणीय चुनौतियां

तेजी से बढ़ता औद्योगीकरण, शहरीकरण और जनसंख्या विस्तार बड़े पैमाने पर वनों की कटाई का कारण बन रहे हैं। इसका असर प्रदूषण, बढ़ते तापमान, अनियमित वर्षा, सूखा और बाढ़ जैसी समस्याओं के रूप में सामने आ रहा है। जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने में वृक्षारोपण और वनों का

संरक्षण बेहद जरूरी है।

जीवन के लिए पेड़ों का अनमोल योगदान

पेड़ों से हमें फल, फूल, औषधियां, लकड़ी, कागज, रबर और गोंद जैसी अनेक उपयोगी वस्तुएं मिलती हैं। आयुर्वेद में अनेक औषधियां पेड़-पौधों से तैयार की जाती हैं। गांवों में आज भी पेड़ लोगों को छाया और विश्राम देते हैं, जबकि असंख्य पक्षी इन्हीं पर अपना घोंसला बनाते हैं। इस तरह पेड़ मानव सहित पूरे जीव-जगत के जीवन से जुड़े हैं।

सिर्फपौधा लगाएं नहीं, उसे बचाएं भी

वृक्षारोपण तभी सार्थक है जब लगाए गए पौधे को बड़ा होने तक सुरक्षित रखा जाए। प्रत्येक नागरिक कम से कम एक पेड़ लगाने और उसकी देखभाल करने का संकल्प ले सकता है। स्कूल, कॉलेज, सरकारी संस्थान और सामाजिक संगठन नियमित रूप से वृक्षारोपण अभियान चलाकर पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे सकते हैं।

बच्चों और युवाओं में पेड़ों के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी की भावना विकसित करना समय की जरूरत है। विद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा के साथ पौधरोपण, पौधों की देखभाल और प्रकृति संरक्षण से जुड़ी गतिविधियां कराई जानी चाहिए। छोटे-छोटे प्रयास मिलकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं।

एक पेड़, आने वाली पीढ़ियों के नाम

एक पेड़, एक जीवन केवल नारा नहीं, बल्कि भविष्य को सुरक्षित रखने का संकल्प है। यदि प्रत्येक व्यक्ति एक पेड़ लगाए और उसकी जिम्मेदारी निभाए, तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा, हरियाली और स्वस्थ वातावरण मिल सकता है। आइए, आज एक पेड़ लगाएं, उसे बचाएं और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं।

प्रभजोत कौर खम्भा

शिक्षक
हितकारिणी चिल्ड्रेन एकेडमी, देवताल, गढ़ा, जबलपुर।

शब्द पहेली - 8947

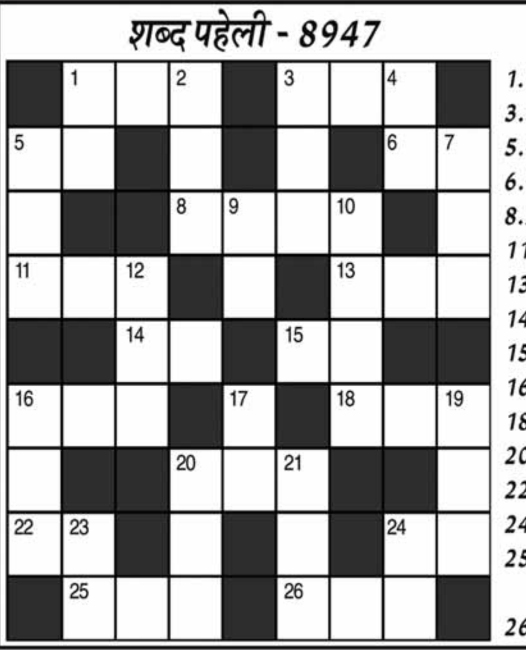

बाएँ से दाएँ

1. पाबंदी, संयम, पाश-3
3. मनुष्य, इंसान-3
5. शारीरिक ऊंचाई-2
6. नलका, टूंटी
8. प्रलय, महासंकट-4
11. दही से बना खाद्य पदार्थ-3
13. निर्माण, निर्मिती-3
14. हुनर, आर्ट-2
15. उम्मीद, आशा-2
16. खाना बनाना-3
18. असफल, अनुतीर्ण-3
20. आभास, भास-3
22. वध-2
24. जी, इच्छा, चित-2
25. सब्जी का सड़ना, बर्फ का पिघलना-3
26. याद करना-3

ऊपर से नीचे

1. हड़ताल, स्थिर, रुका हुआ-2
2. लवण -3
3. विश्राम, राहत-3
4. मछली, मत्स्य, राशि चक्र की एक राशि-2
5. बूंद-3
7. शरमाना-3
9. दोस्त, मित्र-2
10. बहुत प्यासा होना-4
12. एकटक निहारना-3
16. शरण, आश्रय-3
17. सम्मान-2
19. चिंतन-3
20. मकान, इमारत-3
21. कमी, थोड़ा-3
23. तज देना-2
24. इंकार, मनाही-2

शब्द पहेली -8946 का हल

न	भ		न	र	म		मा	त
म		शा	म		द	म		प
क	न	क		ज		ना	प	ना
	मा		ख	न	क		र	
रा	ज	दा	र		स	रो	व	र
	गा		ल	गा	म		रि	
र	ह	न		ल		मि	श	न
म		ख	त		पा	त्र		जा
ल	य		वा	च	क		ता	त

Jagrutidaur.com, Bangalore

गांव की गलियों में बाघ की दहाड़!

खैरलांजी के पांढरवानी गांव की गलियों में पहुंचा बाघ, वन विभाग ने बढ़ाई गस्त

बालाघाट(स्वतंत्र मत)

इन दिनों खैरलांजी क्षेत्र के उन गांवो मे बाघ को लेकर दहशत बनी हुई है, जो गांव जंगल के किनारे बसे है। खासकर ग्राम पंचायत मिरगपुर के पांढरवानी गांव के सतीटोला और बानाटोला के ग्रामीण जिंदगी और मौत के बीच सांस लें रहे है। क्योंकि पिछले तीन दिनों से इन गांव के आसपास लगातार बाघ का मूवमेंट बना हुआ है। हाल ही में गांव के नजदीक बाघ ने तीन मवेशियों और एक ग्रामीण पर हमला कर उसकी जान ले ली। जहाँ इस घटना के बाद पूरे गांव में भय का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि बाघ अब आदमखोर बन चूका है और वह जंगल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि गांव की गलियों में घुसकर घरो की चौखट तक पहुंच रहा है। क्योकि घरो के आसपास व खेतो में बाघ के पदचिन्ह स्पष्ठ रूप से देखे जा रहे है।

ग्रामीणो ने बताया कि 9 अगस्त को दोपहर करीब 12 बजे गांव का देवकराम वाघमारे मवेशी चराने करीब के जंगल की ओर गया था। लेकिन वह देर शाम तक घर नही लौटा। परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। 10 अगस्त की सुबह गांव के श्मशान घाट से लगे जंगल में उनकी लाश मिली और करीब में मवेशी भी मृत पड़े थे। जिससे बाघ द्वारा उनका शिकार किये जाने की आंशका जाहिर हुई और इससे जुडे साक्ष्य भी मौके पर मिले। इस घटना के बाद से ईलाके में बाघ का मुमेंट लगाातार देखा जा रहा है।

शाम का अंधेरा होते ही बाघ की दहाड़ सुनाई दे रही है। जिससे ग्रामीणों की नींद भी उड़ गई है। बाघ अब रिहायशी बस्ती मे भी घुसकर मूमेंट कर रहा है। जहां गांव की गलियों से लेकर खेतो तक बाघ के पंजे के निशान देखे जा रहे है। जिस स्थान पर बाघ के द्वारा मवेशीयो और ग्रामीण पर हमला किया गया था, वहाँ वन विभाग ने करीब 04 ट्रेप कैमरे लगाए थे, जहाँ उन कैमरे मे भी बाघ की तस्वीर कैद हुई है। 10 अगस्त की बीती रात और 11 अगस्त की तडके सुबह तक गांव के भीतर बाघ और उसके कुनबे की मौजूदगी बनी थी, जिससे ग्रामीणों की नींद उड़ गई है। अब ग्रामीण इतनी बड़ गई है कि शाम ढलते ही लोग घरों में कैद हो जाते है। बाघ के मुमेंट को परखने के बाद लोगो मे दहशत इतनी भर गई है कि ग्रामीण अब यही सोचकर घर से निकलने से कतरा रहे है कि कहीं बाघ का अगला शिकार वो खुद ना बन जायें।

लगातार हो रही घटनाओं और बाघ की मौजूदगी के बावजूद वन विभाग पर गंभीर नहीं होने के आरोप लग रहे है। ग्राम पांढरवानी निवासी खिलेन्द्र बिसेन ने वन विभाग से मांग की है कि बाघ को आबादी वाले क्षेत्र से दूर खदेड़ने के लिए तत्काल विशेष इंतजाम किए जाएं। इसके साथ ही यदि बाघ बार-बार गांव की सीमा में प्रवेश कर रहा है तो पिंजरा लगाकर उसका रेस्क्यू किया जाए। क्योकि जंगल के करीब बसे इस गांव में रात का सन्नाटा अब सुकून नहीं, बल्कि किसी अनहोनी की आशंका बन चुका है। फिलहाल वन विभाग की ओर से भरकस प्रयास किये जा रहे है कि बाघ के मुमेंट को कम किया जाये। इसे लेकर वन विभाग ने इलाके मे गस्ती बड़ा दी है और लोगो को अलर्ट रहने की हिदायत भी दी जा रही है।

इनका कहना हैं

ग्रामीण समन्वय बनाकर रखे। शाम के समय घर से ना निकले और जंगल की तरफ ना जाए। विभाग ने जगह जगह कैमरे लगाए है और बाघ के मूमेंट को ट्रेक किया जा रहा है। आगे कोई गंभीर घटना ना हो। इसे लेकर सभी को अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है। हम अगले दो-तीन दिन में स्थिति को सामान्य कर देगें। आवश्यक्ता पडी कि पिंजरा लगाकर रेस्क्यू भी किया जायेगा।

यशपाल मेहरा
एसडीओ, वन परिक्षेत्र कटंगी

आदिवासी अंचल में बीमारी से 9वीं मौत

बालाघाट(स्वतंत्र मत)। बिरसा विकासखंड की अडोरी पंचायत के बैगा बाहुल्य ग्रामो में आदिवासी बच्चो पर घातक बिमारी तमाम प्रयासो के बाद भी नियंत्रण के बाहर हो रही है और नतिजा यह निकल रहा है कि बच्चो की मौत का सिलसिला अब बढ रहा है। अब तक क्षेत्र के कुल 09 बच्चो की मौत हो चुकी है। जिससे पूरा ईलाका अब सहम चुका है और मासुमो की मौत का यह आकड़ा अब पूरे सिस्टम पर करारा तमाचा लगा रहा है। लगातार बच्चों की मौत से ग्रामीणों में अब मायुस है और दहशत में सिसक रहे है। पिछले लगभग 40 दिनो में अडोरी पंचायत के बोदांरी गांव में 04 बच्चे, कोहनीमोर में 02 बच्चे और कुंडेकसा गांव में 02 बच्चे की मौत हुई है। इसके अलावा गठिया गांव में भी एक मासुम बच्ची की मौत हो गई है। हाल ही में 10 अगस्त को रूपल पिता दशरथ धुर्वे की मौत हो गई। इसके अलावा ग्राम गठिया में भी 05 साल ही मंगली पिता सहरसिंह बैगा की मौत हो गई। जबकि इनकी अन्य तीन बहने भी बीमार बताई जा रही है। जबकि पूर्व रूपलाल पिता बिसरू धुर्वे निवासी बोंदारी की 16 जून 2026 को मौत हुई। उसके बाद 26 जून को कोहनीमोर निवासी शाहील पिता समरू धुर्वे ढाई वर्ष ने दम तोडा। अगले ही दिन 27 जून को उसकी बहन लमनीन पिता समरू धुर्वे उम्र 12 वर्ष ने भी तेज बुखार के चलते दम तोड दिया। अगले माह 22 जुलाई को कुंडेकसा निवासी प्रींति मरकाम उम्र 15 वर्ष की मौत हुइ। 26 जुलाई को बोंदारी निवासी पूजा पिता चमरू मरकाम उम्र ढाई वर्ष की मौत हो गई। स्वास्थ विभाग की जांच पड़ताल के दौरान भी बच्चो की मौत का सिलसिला नही रूका और 01 अगस्त को बोंदारी निवासी सचीन मरकाम तथा 06 अगस्त को कोंडेकसा निवासी अरविंद पिता चैतू धुर्वे उम्र 04 वर्ष की मौत हो गई। हाल ही में 10 अगस्त को रूपल पिता दशरथ धुर्वे की मौत हो गई। इसके अलावा ग्राम गठिया में भी 05 साल ही मंगली पिता सहरसिंह बैगा की मौत हो गई।

भ्रष्टाचार और मनमानी का अड्डा बन गया नगरपालिका मलाजखंड

बालाघाट(स्वतंत्र मत)। मलाजखंड नगरपालिका द्वारा विकास के नाम पर सरकारी फंड का दुरूपयोग किय जाने का मामला प्रकाश में आया है। जहां हाल ही में बनी पुलिया क्षतिग्रस्त बारिश के पानी के बहाव में क्षतिग्रस्त हो गई है। यहां नगरपालिका परिषद मलाजखंड के तकनीकी विभाग की कार्य-कुशलता समझने लायक है कि जुलाई में बनी पुलिया पहले बारिश की पहली फुहार भी नहीं झेल पाई। आरोप लग रहे है कि जानपुर रोड से सिनधुपे फार्म के बीच बनी पुलिया का निर्माण गुणवत्ताहीन था। जहां मुरूम से भरण किया गया, जो कि पहली बारिश में ही धूल गया। पाईप कल्वर्ट पुल में डाली गई पायली भी अनफिट थी। जहां तकनीति खामियों के कारण पानी का बहाव बर्दाश्त नही हुआ और पुरा निर्माण कार्य क्षतिग्रस्त हो गया। हैरत की बात यह है कि किसी भी निर्माण कार्य को प्रारंभ करने के पूर्व उसका पूरा ब्यौरा साईन बोर्ड पर अंकित करके मौका स्थल पर लगाना होता है, लेकिन इस पुलिया का निर्माण कार्य अबूझ पहेली है। सुत्र बताते है कि उक्त पुलिया का निर्माण कार्य नपाध्यक्ष के वार्ड क्षेत्र में हुआ है, जिससे कई सवाल खडे होने लगे है। सुत्रो की माने तो नगरपालिका मलाजखंड के जवाबदारों के हौसले सातवें आसमान पर हैं, जहां नियमो को ताक पर रखकर सरकारी धन की फजीहत की जा रही है। नियम ताक पर रखकर मनचाहे लोगो को लाभ पहुचाने के लिये कार्य करवाये जा रहे है और बिना निविदा प्रक्रिया के अपने मनमाफिक काम कराने के लिए ढेरों जुगत लगाई जा रही है। बिना किसी टेंडर के काम कराए जा रहे हैं और बिलों का भुगतान भी हो रहा है। इस गठजोड़ पर कोई आपत्ति न ले इसलिए कामों का बटवारा भी किया जा रहा है, ताकि सभी की रोजी-रोटी चलती रहे।

पंचायत का गजब कारनामा : एक नाले पर तीन तालाब!

जनपद पंचायत किरनापुर की ग्राम पंचायत मुर्री का मामला, पहली बारिश में ही तालाबों के क्षतिग्रस्त होने का आरोप

बालाघाट (स्वतंत्र मत)

देश में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनरेगा के तहत जल गंगा संवर्धन अभियान चलाकर पंचायत स्तर पर युद्धस्तर पर जल संरक्षण के कार्य कराए गए। जिला पंचायत सीईओ अभिषेक सराफ और तत्कालीन कलेक्टर मृणाल मीना के नेतृत्व में बालाघाट जिले में भी बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य कराए गए, जिसके चलते प्रदेश स्तर पर जिले का नाम अव्वल रहा। लेकिन जनपद पंचायत किरनापुर की ग्राम पंचायत मुर्री से तालाब निर्माण को लेकर सामने आई तस्वीरें अब कई सवाल खड़े कर रही हैं।

जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत मुर्री में एक ही नाले पर एक नहीं, बल्कि तीन तालाबों का निर्माण कराया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि जिस नाले से बारिश का पानी प्राकृतिक रूप से बहकर नदी की ओर जाता है, उसी नाले पर तीन अलग-अलग स्थानों पर तालाब बना दिए गए। ऐसे में सवाल उठता है कि जल संरक्षण के वैज्ञानिक मापदंडों के तहत एक ही जलमार्ग पर तीन तालाबों के निर्माण की अनुमति कैसे मिली?

ग्रामीणों के मुताबिक, इन तालाबों का निर्माण मनरेगा के तहत मजदूरों से कराने के बजाय कथित तौर पर जेसीबी मशीनों से कराया गया। वहीं निर्माण स्थल पर किसी प्रकार का सूचना या कार्य संबंधी साइन बोर्ड भी नजर नहीं आया। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि पहली ही बारिश में निर्माण कार्य क्षतिग्रस्त होने लगा है। जल गंगा संवर्धन अभियान का मुख्य उद्देश्य जनभागीदारी के माध्यम से जल संरक्षण, जलमार्गों और तालाबों के कैचमेंट क्षेत्र से अतिक्रमण हटाना तथा भूजल स्तर को बढ़ाना है। इसके तहत तालाब निर्माण के लिए वैज्ञानिक तरीके से प्राकृतिक जल बहाव, ढलान और कैचमेंट एरिया का अध्ययन कर स्थान का चयन किया जाना बताया गया है। ऐसे में एक ही नाले पर तीन तालाबों का निर्माण कई सवाल खड़े करता है, जिसकी जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकती है। इस मामले में ग्राम पंचायत मुर्री के सरपंच डॉ. महेश बाहे से चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि परसाड़ी क्षेत्र में तीन तालाबों का निर्माण कराया गया है। पंचायत क्षेत्र में जगह का अभाव होने के कारण एक ही नाले पर तीन तालाब बनाए गए हैं। हालांकि, तालाबों के निर्माण में कितनी-कितनी राशि खर्च हुई, इस संबंध में वे स्पष्ट जानकारी नहीं दे सके। अब सवाल यह है कि क्या एक ही नाले पर तीन तालाबों का निर्माण विभागीय मापदंडों और तकनीकी स्वीकृति के अनुरूप हुआ है? यदि निर्माण मनरेगा के तहत हुआ है तो क्या निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया? इन तमाम सवालों का जवाब संबंधित विभाग की जांच के बाद ही सामने आएगा।

कटंगी के राजा भोज कॉलेज में 14 अगस्त तक रिक्त सीटों पर प्रवेश

कटंगी(स्वतंत्र मत)। मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार राजा भोज शासकीय महाविद्यालय कटंगी में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त सीएलसी चरण के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया शुरू की गई है। यह प्रक्रिया 10 अगस्त से 14 अगस्त 2026 तक चलेगी। इसके तहत महाविद्यालय में उपलब्ध रिक्त सीटों पर ही प्रवेश दिया जाएगा। महाविद्यालय की प्रवेश नोडल अधिकारी डॉ. कुसुमलता उइके ने बताया कि प्रवेश 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर दिया जाएगा। रिक्त सीटों की जानकारी विद्यार्थियों के लॉगिन और संबंधित महाविद्यालय के पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। पंजीकृत विद्यार्थी संबंधित महाविद्यालय में सीधे प्रवेश शुल्क जमा कर प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। नवीन पंजीकृत विद्यार्थियों को केवल एक महाविद्यालय में पंजीयन करने की अनुमति होगी। प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित किसी भी जानकारी या समस्या के लिए विद्यार्थी महाविद्यालय के हेल्प सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। महाविद्यालय प्रबंधन ने बताया कि 14 अगस्त 2026 को शाम 5 बजे तक प्रवेश शुल्क जमा कर प्रवेश लिया जा सकेगा। ऐसे विद्यार्थी जो अब तक प्रवेश से वंचित हैं, वे रिक्त सीटों की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त कर निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर इस अतिरिक्त अवसर का लाभ उठा सकते हैं।

विधायक की पहल से आईटीआई मानपुर में अब ऐनम का होगा प्रशिक्षण

मानपुर (स्वतंत्रमत)

तकनीकी शिक्षा विभाग, जनजातीय विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित परम फाउंडेशन के माध्यम प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बालिकाओं के लिए कौशल कॉलेज की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य बालिकाओं को आवासीय एवं उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के माध्यम से नौकरी से जोड़ना है, जिसके लिए कॉलेज में डिजिटल क्लास रूम, आधुनिक लैब, सिम्युलेटर, सिमोम, सिम्बेबी जैसे कई आधुनिक उपकरण एवं सुविधाएं उपलब्ध हैं। मंगलवार 11 अगस्त को अतिथियों द्वारा द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुरुआत किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे श्रीमती भारती जी ने अपने उदबोधन में कहा कि प्रदेश में 6 एएनएम नर्सिंग कौशल कॉलेज की स्थापना हुई है, प्रदेश में संचालित 6 नर्सिंग कौशल कॉलेजों में से एक नर्सिंग कौशल कॉलेज, मानपुर में मंगलवार 11 अगस्त को एएनएम प्रथम बैच 2025 - 27 के विद्यार्थियों के लिए शपथ ग्रहण समारोह एवं कैपिंग सेरेमनी का आयोजन किया जा रहा है, इस वर्ष मानपुर नर्सिंग कॉलेज में 60 बालिकायें प्रषिक्षण ले रही हैं जब इस वर्ष यहां 60 से बढ़ाकर 120 सीट कर दिया गया है जिस के लिये एडवीशन चालू है, यहां उमरिया, मंडला, शहडोल, सहपुरा, सीधी, रीवा, सताना के सांथ कई मध्यप्रदेश के कई जिला से छात्रायें प्रशिक्षण ले रही हैं, यहां आवासीय के तरह पूर्ण सुविधा और सुरक्षा की ब्यवस्था युक्त अच्छे स्तर का छात्रावास भी है, यहां के बालिकाओं को खेल कूद योगा जैसे शिक्षा भी दी जाती है।

गलत उपचार से मरीज की मौत का मामला

बालाघाट(स्वतंत्र मत)। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ परेश उपलप ने बिरसा के खंड चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया है कि बिना योग्यता के एवं मरीज का गलत उपचार करने के मामले में गुदमा के झोलाछाप डाक्टर डॉ. सुमन बिसेन एवं डॉ. चन्द्रपाल कलिहारे के विरूद्ध थाने में एफआईआर दर्ज करायें। जिले के बिरसा विकासखंड के ग्राम सहेगांव की सविता मरावी द्वारा शिकायत की गई थी कि झोलाछाप डॉ. चन्द्रपाल कलिहारे एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुदमा में पदस्थ नर्स के गलत उपचार के कारण उसके पति लोकेश मरावी की 05 दिसंबर 2025 को मृत्यु हो गई है। कलेक्टर द्वारा इसकी जांच कर दोषी व्यक्तियों पर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे। इस प्रकरण की खंड चिकित्सा अधिकारी बिरसा द्वारा की गई जांच में पाया गया कि ग्राम गुदमा की डॉ सुमन बिसेन एवं डॉ चन्द्रपाल कलिहारे द्वारा अवैध रूप से चिकित्सा व्यवसाय किया जा रहा है। इस पर इन दोनों चिकित्सकों के विरूद्ध मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1987 की धारा 13 का उल्लंघन करने एवं नियम विरुद्ध चिकित्सा व्यवसाय किए जाने के कारण, उनके विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है।

गुदमा के झोलाछाप डाक्टरों पर एफआईआर कराने के निर्देश

क्या आपरेटर और भृत्य की जवाबदारी से संचालित होता है पीडब्ल्यूडी का पीआईयू कार्यालय..?

मानपुर (स्वतंत्रमत)

लोक निर्माण विभाग के परियोजना कार्यान्वयन इकाई द्वारा बड़े प्रोजेक्ट वाले भवन निर्माण कार्य करवाये जाने की जवाबदेही होती है। करोड़ों रुपये तक के बजट से शासकीय भवनों के निर्माण कार्य निर्माण एजेंशी पीआईयू द्वारा करवाया जाता है, ऐसे विभागों में जवाबदार अधिकारियों का चेम्बर अक्सर खाली ही रहता हैं.! उमरिया में संचालित लोक निर्माण विभाग का पीआईयू शाखा करोड़ों के लागत से कई भवने तयार करवाने में आगे है जबकि यह कार्यालय स्वयं अति छोटे पुराने भवन में संचालित है, जहां स स्टॉप, ठेकेदार और नागरिकों के बैठने के लिये पर्यात जगह की ब्यवस्था नहीं है, यहां पहुंचने वालों के लिये बैठक ब्यवस्था, पंक्खा और सफाई का हमेसा अभाव बना रहता है! इस कार्यालय में पहुंचने वालों के बाहन खड़े करने के लिये कहीं कोई जगह तक नहीं है वह विभाग क्षेत्र का कितना विकास करता होगा, समझ के परे है! सूत्रों की माने ते इस कार्यालय में कार्यपालन यंत्री, अनुविभाग अधिकारी और उपयंत्री की अनुपस्थिति अक्सर बनी ही रहती है, जो कब कहां मिलेंगे अथवा इस समय कहां होंगे, फोन क्यों नहीं उठाया जाता है अथवा इनका फोन अधिक्तर बंद क्यों बताता रहता है, की जानकारी यदि कर्यालय में उपस्थित क्लर्क आपरेटर अथवा स्टॉप से पूंछे जाने पर तो जवाब में मौन धारण अथवा काल्पनिक उत्तर ही मिल पायेगा, फोन लगाये जाने पर इवका मोबाइल बंद बतायेगा अथवा फोन न उठाया जायेगा! ईई साहब का फोन यदि धोखा से उठ गया तो अक्सक भोपाल दौरे में होने का जवाब ही मिलेगा, जबकि जन चर्चा के अनुसार ईई साहब अक्सर अपने निवास बंगले में ही रहकर ड्यूटी करने की जानकारी मिलती है! क्षेत्र में बड़े से बड़े जन कल्याणकारी अथवा जन समस्या निवारण शिविर और स्वयं अपने विभाग द्वारा हो रहे भूमिपूजन, निर्माण कार्य और लोकार्पण इनका अनुपस्थ्ति बनी रहती है! इनके द्वारा भ्रमण, निरीक्षण, मीटिंग कब कहां होता है स्वयं विभागीय टीम के सदस्य और ठेकेदार नहीं बता पाते! जन चर्चा यह भी है कि यहां के कुछ अधिकारी अक्सर नसा से दोस्ती किये रहते हैं!

मानपुर में नवनिर्मित भव्य कन्या शिक्षा परिसर आवासीय भवन का विधायक सुश्री मीना सिंह ने किया लोकार्पण

मानपुर (स्वतंत्रमत)

निर्माण कर्यों में अग्रणी रहने वाला मध्यप्रदेश विकास दर को तेजी से आगे बढ़ाते हुये जनता के मन को मोहित कर रहा है, वहीं मानपुर विधायक सुश्री मीना सिंह का पहल क्षेत्रीय विकास कार्यों के ग्राफ को उंचाइयों की ओर ले जा रहा है, तभी तो क्षेत्र में अपनी अलग लोकप्रियता हासिल कर रखी हैं। सोमवार 10 अगस्त को विधायक मीना सिंह जी ने 23.29 करोड़ के लागत से बने एक भव्य भवन का लोकार्पण किया, जबकि पूर्व कैबनिट मंत्री सुश्री मीना सिंह जी ने इस भवन के निर्माण होने का श्रेय क्षेत्रीय जन्ता और भाजपा सरकार को दे रही हैं।

मां साबरी माता कन्या शिक्षा भवन के लोकार्पण के पहले अतिथियों द्वारा पौराणिक मंत्र से पूजन फिर वृक्षारोपण किया गया, जिसके उरांत फीता काटकर आवास ग्रह प्रवेश कर लोकार्पण करते हुये इस भवन को विभागीय प्राचार्य और हास्टल अधिक्षक के हांथों सौंपा गया, जिसके बाद कन्या पूजन कर रंगारंग कार्यक्रम समलित हो कर सर्वाधिक अंकों से उत्तीर्ण होने वाले छात्राओं को गिप्ट और प्रसस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। अंत में आभार ज्ञापित करते हुये कार्यक्रम में पधारे समस्त बच्चे, अविभावक, शिक्षक एवं अतिथियों को मां अन्न पूर्णा भवन में एक सांथ सुरुचि भोजन करवाया गया। अपने उदबोधन में कार्यक्रम की मुख्य अतिथि विधायक सुश्री मीना सिंह ने कहा कि शिक्षा ही जीवन का सुनहरा और लाभप्रद जीवन है। शिक्षा के बिना जीवन में तरक्की का होना सम्भव नहीं, मै भी गरीब परिवार के ग्रामीण शिक्षक की बेटी हूं हम लोग अपने पिता के पांच बहन और दो भाई थे, हमारे मात पिता ने शिक्षा को सर्वोपरि मानते हुये अपने शुख में कमी करते हुये हमें तन मन धन से पढ़ाया तभी तो आज हम सब समाज सेवा और प्रशासनिक कार्य तक पहुंच पाये, और मैं आप सबसे भी आग्रह करना चाहती हूं कि अपने जीवन में शिक्षा स्तर को बढ़ाकर आप लोग अपने तरक्की के सांथ हम सबका भी नाम रोशन करें। मेरे सब कुछ अपने क्षेत्र की जंता है, क्षेत्र का विकास मेरा प्रथम कर्तव्य और धर्म है, मैं आप लोगों के सेवा में कोई कसर न छोड़ूंगी, मेरा जीवन आप जन्ता जनार्दन के लिये है। बीजेपी की सरकार क्षेत्र के विकास सदा से काम कर रही है हम आप के प्रधान मंत्री एवं मुख्य मंत्री भी हम आप के लिये तन मन धन के काम कर रहे हैं जो धन्यवाद के पात्र हैं। मानपुर एसडीएम सुश्री हरनीत कौर ने अपने उद्बोधन में कहा कि मानपुर का यह कन्या परिसर भवन भब्य है इतना भब्य भवन क्षेत्र में सायद ही कहीं हो, कौर जी ने कहा कि हम और सरकार सदा आप लोंगों के सांथ है आप लोग पढ़ाई में तरक्की करें, मै यहां के प्राचार्य और अधिक्षक जी से कहना चाहती हूं कि सरकार के नियमानुसार बच्चों को पूर्ण सुविधा मुहैया करवाते रहने को सुनिस्चित रखा जाय, यहां और क्षेत्र के सभी स्कूलों में विधायक जी और हम लोगों का भृमण होता रहेगा, यदि कभी भी कोई समस्या महसूस हो तो मैं और मेरा स्टॉप सदा क्षेत्रीय लोगों के सांथ है, शासकीय मापदंडों के अनुसार जनसेवा करना हमारा काम है, मै आप सभी बच्चों से आशा करती हूं कि आप लोग परीक्षा के परिणाम प्रदेश स्तर में अच्छे लायें और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। जनजातीय कार्य विभाग की सहायक आयुक्त डॉ. श्रीमती पूजा द्विवेदी ने कहा कि कन्या शिक्षा परिसर को अपने क्षेत्र में लानले का मुख्य भूमिका मानपुर विधायक सुश्री मीना सिंह जी का है, क्षेत्र में इस स्कूल के सौगात मिलने पर क्षेत्र के आदिवासी छात्राओं के शिक्षा स्तर में तेजी से बढ़त और सफलता मिली है, यहां पढ़ने वाले बच्चे और इनके अविभावकों में बड़ी खुशी दिख रही है।

बरेला पुलिस ने सैंडी बरमैया को भोपाल से किया गिरफ्तार
फरारी में कथित संरक्षण से लेकर रेत कारोबार में गंभीर सवाल

मण्डला (स्वतंत्र मत)।

लंबे समय से जिले में रेत के कारोबार को लेकर वाद विवाद मारपीट लड़ाई झगड़ा और राजनैतिक हस्ताक्षेप दिखाई देता है। सत्ता दल और विपक्ष अपने-अपने चेहेते कार्यकर्ता और अन्य लोगों के माध्यम से रेत के कारोबार में दखलादांजी किया करता है। खासकर बम्हनी क्षेत्र में रेत के इस अवैध कारोबार को लेकर अकसर वाद विवाद दिखाई देता है। ऐसा ही बम्हनी क्षेत्र के युवा सेंडी बरमैया रेत कारोबार को लेकर काफी बदनाम है बीते माहों में राजनीति से जुड़े बड़े नेताओं के साथ इनके समाचार प्रकाशित हो चुकें हैं। राजनैतिक संरक्षण के चलते आरोप प्रत्यारोप के बीच एक नई खबर सामने आई है। बरेला पुलिस से मिली जानकारी अनुसार व्यापारी शंकर गुरनानी पर कथित जानलेवा हमले के मामले में लंबे समय से पुलिस को चकमा दे रहे सैंडी बरमैया को आखिरकार बरेला पुलिस ने भोपाल क्षेत्र से उसके कथित सह-अभियुक्त कपिल साहू के साथ गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने राहत की सांस जरूर ली है लेकिन इस पूरे मामले ने कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब अब जांच के दौरान सामने आना बाकी है सबसे बड़ा सवाल यही है कि गंभीर धाराओं में मामला दर्ज होने और नाम सामने आने के बावजूद सैंडी बरमैया इतने लंबे समय तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर कैसे रहा फरारी के दौरान वह कहां-कहां रहा उसे आर्थिक अथवा अन्य प्रकार की मदद किसने उपलब्ध कराई क्या किसी प्रभावशाली व्यक्ति ने उसकी गिरफ्तारी रोकने या पुलिस कार्यवाही को प्रभावित करने का प्रयास किया इन सवालों को लेकर अब चर्चाएं तेज हो गई हैं शिकायतकर्ता पक्ष के अनुसार व्यापारी शंकर गुरनानी पर हुए कथित हमले में उनके सिर पर गंभीर चोटें आई थीं और उन्हें कई टांके लगाने पड़े थे। घटना के बाद बरेला पुलिस ने गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। शिकायतकर्ता पक्ष का कहना है कि एफआईआर में नाम आने के बावजूद आरोपी लंबे समय तक पुलिस की पकड़ से बाहर रहे मामले ने तब और तूल पकड़ा जब शिकायतकर्ता द्वारा मंडला पुलिस को आवेदन दिए जाने के बावजूद अपेक्षित कार्यवाही नहीं होने तथा फरारी के दौरान सैंडी बरमैया को मंडला जिले के एक थाने से कथित तौर पर मुचलका दिए जाने का मुद्दा उठाया गया शिकायतकर्ता पक्ष का यह भी दावा है कि मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से जवाब मांगे जाने की स्थिति बनी सैंडी बरमैया की गिरफ्तारी के लिए बरेला थाना प्रभारी संगीता सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक तलाश का दायरा दिल्ली उत्तराखंड रायपुर और मंडला तक बढ़ाया गया लंबे समय तक पुलिस को चकमा देने के बाद आखिरकार मुखबिर तंत्र और पुलिस की तकनीकी एवं मैदानी जानकारी के आधार पर आरोपी की लोकेशन भोपाल क्षेत्र में मिली इसके बाद रात के समय कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम ने सैंडी बरमैया और कपिल साहू को गिरफ्तार कर लिया और दोनों को जबलपुर लाया गया यह गिरफ्तारी इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि सैंडी बरमैया की गिरफ्तारी पर कथित तौर पर हजारों रुपये का इनाम घोषित होने की बात भी सामने आती रही है अब पुलिस के सामने केवल आरोपी को गिरफ्तार करने की चुनौती नहीं है बल्कि फरारी के दौरान उसके संपर्कों और गतिविधियों की पड़ताल करना भी अहम होगा गिरफ्तारी के साथ ही मंडला में कथित राजनीतिक और स्थानीय संरक्षण को लेकर लगाए जाते रहे आरोप फिर चर्चा में आ गए हैं शिकायतकर्ता पक्ष का आरोप है कि मंडला के कुछ प्रभावशाली लोगों ने आरोपी को बचाने का प्रयास किया शिकायतकर्ता पक्ष द्वारा यह आरोप भी लगाया जाता रहा है। सैंडी बरमैया की गिरफ्तारी के बाद अब उसके कथित रेत कारोबार को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर आरोप लगाए जाते रहे हैं कि सैंडी बरमैया पिछले कई वर्षों से रेत के कारोबार से जुड़ा हुआ है और इस कारोबार में उसका प्रभाव काफी बड़ा है दावा किया जाता है कि उसके पास बड़ी संख्या में डंपर और छोटे-बड़े वाहन हैं जिनके माध्यम से कथित तौर पर दिन-रात रेत का परिवहन किया जाता है आरोप यह भी हैं कि रेत को एक शहर से दूसरे शहर तथा अलग-अलग जिलों तक भेजा जाता है इन दावों की वास्तविकता का पता लगाने के लिए खनिज विभाग, परिवहन विभाग, पुलिस और राजस्व अमले द्वारा संयुक्त जांच की आवश्यकता है यदि वास्तव में इतनी बड़ी संख्या में वाहनों का उपयोग रेत परिवहन में हो रहा है तो उनके स्वामित्व परमिट ई-रवन्ना, रॉयल्टी भुगतान, जीपीएस रिकॉर्ड और परिवहन मार्गों की जांच से कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं बम्हनी क्षेत्र के पास कथित तौर पर रेत का बड़ा स्टॉक किए जाने और उसे स्थानीय स्तर पर वाइट हाउस नाम से पहचाने जाने की बात भी सामने आ रही है।

यदि यह दावा सही है तो प्रशासन के लिए यह जांच का विषय है कि वहां रेत का भंडारण किसकी अनुमति से हुआ कितनी मात्रा में हुआ रेत कहां से लाई गई और उसके दस्तावेज क्या हैं सवाल यह भी है कि यदि लंबे समय से इस प्रकार का कारोबार संचालित हो रहा था तो संबंधित विभागों की निगरानी व्यवस्था कहां थी क्या नियमित निरीक्षण हुए क्या रॉयल्टी और परिवहन संबंधी दस्तावेजों की जांच की गई यदि नहीं तो जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए सैंडी बरमैया की कथित संपत्तियों और कारोबार को लेकर भी स्थानीय स्तर पर तरह-तरह के सवाल उठ रहे हैं।

रामकली बनीं महिला विभाग जिलाध्यक्ष

मण्डला/बिछिया (स्वतंत्र मत)। श्रीमती रामकली प्रजापति की नियुक्ति दक्ष प्रजापति आर्मी मध्यप्रदेश प्रदेशाध्यक्ष आरएन प्रजापति, महिला प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती नीलिमा मालवीय प्रजापति, संभाग प्रभारी सहदेव मालवीय, जिला प्रभारी आकाश चक्रवर्ती एवं जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र चक्रवर्ती की सहमति से की गई है नियुक्ति के बाद समाजजनों ने उम्मीद जताई कि श्रीमती रामकली प्रजापति का सामाजिक अनुभव सेवा-भाव और मातृसुलभ मार्गदर्शन संगठन एवं समाज के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा उनके नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जनजागरूकता बढ़ाने तथा समाज में एकता और आपसी समन्वय को मजबूत करने की दिशा में प्रभावी कार्य किए जाएंगे। श्रीमती रामकली प्रजापति की नियुक्ति पर नंदकिशोर चक्रवर्ती, जिलाध्यक्ष, संतोष चक्रवर्ती, जिला महासचिव, पूर्व उपाध्यक्ष गया प्रसाद चक्रवर्ती बीपी चक्रवर्ती, मोतीलाल चक्रवर्ती, धन्नूलाल चक्रवर्ती, मंगलेश चक्रवर्ती, लक्ष्मी प्रसाद चक्रवर्ती, राजू प्रसाद चक्रवर्ती, दिनेश चक्रवर्ती, शैलेंद्र चक्रवर्ती, बसंत चक्रवर्ती, चीकू प्रजापति एवं लखन चक्रवर्ती सहित स्वजातीय बंधुओं शुभचिंतकों वरिष्ठजनों एवं परिवारजनों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई प्रेषित की हैं।

विदेशी एवं देशी मदिरा जब्त

मण्डला (स्वतंत्र मत)। कलेक्टर के निर्देशानुसार एवं जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती शैली शैयाम के मार्गदर्शन में अवैध शराब के निर्माण परिवहन एवं विक्रय के विरुद्ध आबकारी विभाग द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। आबकारी बल मंडला एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दबिश देकर अवैध मदिरा के विरुद्ध कार्यवाही के दौरान झूला पुल के नीचे मनीष हीडाउ के कब्जे से 12 नग विदेशी मदिरा एवं 10 नग देशी मदिरा बरामद कर जब्त की गई इसी प्रकार खिरका मोहल्ला क्षेत्र में वेदप्रकाश पावले एवं गणेश यादव के कब्जे से हाथ भट्टी से निर्मित कच्ची मदिरा बरामद की गई। मौके से कुल 5 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई। अवैध रूप से मदिरा का विक्रय एवं कब्जा पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं जब्त की गई मदिरा की कुल अनुमानित कीमत लगभग 3 हजार 750 रुपये बताई गई है।

डीएलसीसी बैठक में समीक्षा

मण्डला (स्वतंत्रमत)। कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित स्वरोजगार एवं ऋण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि विभाग हितग्राहियों के पूर्ण दस्तावेजों वाले गुणवत्तापूर्ण एवं बैंक से ऋण स्वीकृति योग्य प्रकरण अधिक से अधिक संख्या में तैयार कर बैंकों को भेजें। उन्होंने कहा कि प्रकरणों के दस्तावेज पूर्ण कराने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी। बैठक में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की समीक्षा करते हुए बताया गया कि 92 प्रकरणों के लक्ष्य के विरुद्ध 32 प्रकरण स्वीकृत किए गए हैं तथा 30 प्रकरणों में ऋण वितरण किया जा चुका है। इसी प्रकार बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 35 प्रकरणों के लक्ष्य के विरुद्ध 5 प्रकरण स्वीकृत हुए हैं।

मुख्यमंत्री दुधारू योजना से मिलेगा लाभ

मण्डला (स्वतंत्र मत)।

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजातियों के पशुपालक परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना संचालित की जा रही है। योजना के माध्यम से बैगा सहरिया एवं भारिया समुदाय के पात्र पशुपालकों को दुग्ध उत्पादन से जोड़कर उनकी आय में वृद्धि करने का प्रयास किया जा रहा है योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राही को 2 दुधारू गाय अथवा 2 मुर्रा भैंस उपलब्ध कराने का प्रावधान है। पशुओं की खरीद एवं प्रदाय के लिए हितग्राहियों को अधिकतम 90 प्रतिशत तक अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। इससे विशेष पिछड़ी जनजाति के पशुपालकों को पशुपालन व्यवसाय शुरू करने अथवा उसे बढ़ाने में आर्थिक सहायता मिलेगी योजना का प्रमुख उद्देश्य विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के परिवारों को स्थायी आय का साधन उपलब्ध कराना है। दुधारू पशुओं के पालन से हितग्राही परिवार दूध का उत्पादन कर स्थानीय स्तर पर उसका विक्रय कर सकेंगे। इससे परिवार की नियमित आमदनी बढ़ने के साथ-साथ पशुपालन एवं डेयरी गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

समय-सीमा बैठक में निर्देश

मण्डला (स्वतंत्रमत)। कलेक्टर ने कहा कि जन विश्वास अभियान शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसकी कड़ी मॉनिटरिंग सीधे मुख्य सचिव मध्यप्रदेश द्वारा की जा रही है। इसलिए शिविरों में प्राप्त आवेदनों का त्वरित निस्तारण हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने शुक्रवार को समय-सीमा एवं विभागीय समन्वय समिति की बैठक में 7 अगस्त को मोहगांव में आयोजित शिविर के दौरान प्राप्त आवेदनों की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिए। आगामी 14 अगस्त को विकासखंड मवई में लगने वाले शिविर की तैयारियों के संबंध में कलेक्टर ने कहा कि वहां भी मोहगांव की तर्ज पर पूरे दिन समीक्षा और भ्रमण किया जाएगा।

जामगांव में निकली तिरंगा रैली

नैनपुर।

हर घर तिरंगा अभियान के तहत जामगांव एकीकृत शासकीय उच्चतर माध्यमिक में तिरंगा रैली निकाली गई । जिसमे विद्यालय के विद्यार्थियों और शिक्षक समुदाय ने गांव की गलियों में घूमकर देश भक्ति की भावना जागृत की। इस दौरान रैली में नारो की अनुगूंज से ग्राम में राष्ट्र के प्रति समर्पण और अपने कर्तव्य की भावना का संचार होता रहा। प्रभारी प्राचार्य श्रीमती बलप्रीत कौर के निर्देशन में यह आयोजन हुआ। जिसमें विद्यार्थियों द्वारा तिरंगा रैली के माध्यम से हर घर तिरंगा अभियान का संदेश दिया।

फुटबॉल टीम बनी राज्य चैंपियन

मण्डला (स्वतंत्रमत)। जिले की अंडर-15 फुटबॉल टीम ने मध्यप्रदेश जूनियर बॉयज स्टेट फुटबॉल चैंपियनशिप-2026 का खिताब जीतकर जिले के खेल इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया है। फाइनल मुकाबले में मजबूत इंदौर टीम को 4-2 से हराकर पहली बार राज्य चैंपियन बनने वाली टीम का गुरुवार को मंडला पहुंचने पर स्वागत किया गया। राज्य विजेता टीम के स्वागत के लिए बस स्टैंड पर बड़ी संख्या में खेल प्रेमी खिलाड़ी अभिभावक और नागरिक मौजूद रहे। इस अवसर पर जिला फुटबॉल संघ अध्यक्ष डॉ. दिलीप शर्मा, उपाध्यक्ष अनिल सोनी, भीष्म द्विवेदी सहित संघ के पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और खेल प्रेमी उपस्थित रहे। सभी ने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों का सम्मान करते हुए इस सफलता का श्रेय खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन और जिला फुटबॉल संघ के सतत प्रयासों को दिया।

बाघ के हमले से ग्रामीण घायल

मण्डला। विगत दिनों ग्राम मालखेड़ी पोस्ट कलेगांव तहसील परसवाड़ा निवासी लगभग 35 वर्षीय राजकुमार पर बाघ ने हमला कर दिया हमले में उनके दोनों हाथों और चेहरे पर चोटें आई हैं जानकारी के अनुसार राजकुमार अपने खेत से लगे कोर वन क्षेत्र में गए थे इसी दौरान बाघ ने उन पर हमला कर दिया घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घायल ग्रामीण को विभागीय वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया।

जनसुनवाई में दिव्यांग को मिली राहत

मण्डला (स्वतंत्रमत)। जिला योजना भवन में आयोजित जनसुनवाई में मंगलवार को कलेक्टर के समक्ष ग्राम पंचायत कटरा निवासी दिव्यांग अमित रघुवंशी अपनी समस्या लेकर पहुंचे अमित ने बताया कि वे एमपी ऑनलाइन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं और स्वयं कार्य कर आत्मनिर्भर बनने की इच्छा रखते हैं। एसडीएम मंडला को निर्देशित किया कि अमित रघुवंशी को तहसील परिसर अथवा उपयुक्त शासकीय स्थान पर स्थान उपलब्ध कराने की संभावनाएं तलाशें जहां वे बैठकर एमपी ऑनलाइन से संबंधित कार्य अथवा कम्प्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्य कर सकें इससे उन्हें अपनी क्षमता के अनुरूप रोजगार प्राप्त करने और आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिल सकेगा जनसुनवाई में कलेक्टर ने अन्य लोगों की समस्याएं भी सुनीं तथा संबंधित अधिकारियों को आवेदनों के निराकरण के लिए आवश्यक निर्देश दिए।

महिला मंडल का सावन मिलन समारोह

मण्डला/बिछिया(स्वतंत्रमत)।

श्रावण मास के पावन अवसर पर सर्व ब्राह्मण समाज महिला मंडल द्वारा रॉयल पैलेस मैरिज गार्डन में सावन मिलन समारोह का आयोजन किया गया। हरियाली तीज को ध्यान में रखते हुए पूरा आयोजन हरियाली के रंग में रंगा दिखाई दिया कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला मंडल की अध्यक्ष संगीता गर्ग ने की उन्होंने कहा कि समय-समय पर ऐसे आयोजन होते रहने से समाज में एकता और अखंडता बनी रहती है। उन्होंने सभी महिलाओं से समाज को जोड़कर रखने और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का आह्वान किया समारोह में सभी माताएं और बहनें हरी साड़ी, हरी चूड़ी और हाथों में मेहंदी लगाकर शामिल हुईं। कार्यक्रम के दौरान नृत्य रील प्रतियोगिता और विभिन्न पारंपरिक खेलों का आयोजन किया गया खेलों में विजेता रहीं महिलाओं को उपहार देकर सम्मानित किया गया। सभी को मेहंदी-चूड़ी भेंट कर सम्मानित किया गया इस अवसर पर शशि मिश्रा, सुषमा पांडे, सरिता उपाध्याय, रश्मि दीक्षित, पूर्णिमा मिश्रा, अरुणा तिवारी, लक्ष्मी भट्ट, उषा भट्ट, कविता दुबे, नीता दीक्षित, अंजू शुक्ला, अर्चना पांडे, रानू पांडे, रिया पांडे, स्मृति जोशी, ज्योति द्विवेदी, मीनू भट्ट, शिल्पा भट्ट, आस्था उपाध्याय, अल्का मिश्रा, ममता पांडे, योगिता जोशी, भावना मिश्रा, श्वेता दुबे, सुमन उपाध्याय, रोशनी दुबे, नीलम तिवारी, अभिलाषा दुबे, उमा मिश्रा सहित बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं।

अकादमिक कैलेंडर अनुसार हो चुनाव

मण्डला (स्वतंत्र मत)। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मध्य प्रदेश में छात्रसंघ चुनावों के संबंध में दायर जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का स्वागत किया है। अभाविप का मानना है कि यह निर्णय विद्यार्थियों के लोकतांत्रिक अधिकारों की पुनर्स्थापना तथा महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय परिसरों में स्वस्थ उत्तरदायी एवं सशक्त छात्र नेतृत्व के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अभाविप ने मध्य प्रदेश शासन एवं उच्च शिक्षा विभाग से आग्रह किया है कि उच्च न्यायालय के निर्णय की भावना के अनुरूप शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करते हुए छात्रसंघ चुनावों की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए तथा समयबद्ध कार्यक्रम घोषित किया जाए जिससे प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों को अपने प्रतिनिधियों का लोकतांत्रिक तरीके से चयन करने का अवसर प्राप्त हो सके। अभाविप महाकोशल के प्रांत मंत्री सुव्रत बाझल ने कहा कि छात्रसंघ चुनाव केवल प्रतिनिधियों के चयन की प्रक्रिया भर नहीं हैं बल्कि यह विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक मूल्यों नेतृत्व क्षमता उत्तरदायित्व तथा सामाजिक सरोकारों के विकास का एक सशक्त माध्यम हैं।

151 लीटर जल से हुआ भगवान भोलेनाथ का अभिषेक
कांवड़ यात्रा में नाचे धर्मप्रेमी उत्साह उमंग का दिखा संगम

मण्डला (स्वतंत्र मत)।

मुन्नी बाई धर्मशाला के सामने स्थित शिव मंदिर से भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई। इस कांवड़ यात्रा की खासियत यह रही कि भक्तों ने 151 लीटर नर्मदा जल से भरा कांवड़ को अपने कंधे में रखा और नगर भ्रमण करते हुए किले घाट पहुंचे जहां पर भगवान भोलेनाथ मंदिर में जलाभिषेक किया। विगत पांच वर्षो से आयोजित कांवड़ यात्रा का आयोजन इस वर्ष भी भव्यता से किया गया। शिव कांवड़ आयोजक समिति के द्वारा आयोजित इस कांवड़ यात्रा में सैकड़ो की संख्या में महिला पुरूष और बच्चें शामिल हुए। कांवड़ यात्रा मुन्नीबाई धर्मशाला के सामने स्थित शिव मंदिर में विधि विधान से पूजन अर्चन से की गई इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष प्रफुल्ल मिश्रा, सामाजिक कार्यकर्ता शशि पटैल, रंजीत कछवाहा, अखिलेश सोनी, नीरज अग्रवाल, मुकेश सोनी, सुधीर कांसकार, सुनील मिश्रा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष ने भगवान भोलेनाथ के मंदिर में पूजन अर्चन करते हुए कांवड़ियो को तिलक वंदन माला पहनाते हुए रवाना कराया। कांवड़ यात्रा यहां से बलराम चौक, पड़ाव, चिलमन चौंक, बस स्टैंड, ज्ञानदीप स्कूल, नगर पालिका, बड चौराहा अंबेडकर चौक, उदय चौक, सराफा, बुधवारी होते हुए किला घाट स्थित व्यास नारायण मंदिर कांवड़ यात्रा पहुंची जहां पर भगवान भोले नाथ को जल चढ़ाने के साथ पूजन किया गया और कांवड यात्रा का समापन हुआ। वहीं मंदिर प्रांगण में रात्रिकालीन भजन संध्या पूजन का आयोजन किया गया जिसमें धर्मप्रेमियों ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई सामाजिक कार्यकर्ता किशोर रजक ने बताया कि कांवड़ यात्रा भगवान शिव के भक्तों द्वारा सावन के महीने में की जाने वाली एक महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा है। इस यात्रा में भक्त गंगाजल या किसी पवित्र नदी से जल भरकर लाते हैं और उसे अपने क्षेत्र के शिव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। यह यात्रा भगवान शिव के प्रति समर्पण और श्रद्धा का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कांवड़ यात्रा की शुरुआत समुद्र मंथन से जुड़ी है। जब समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष निकला तो भगवान शिव ने उसे ग्रहण किया। विष के प्रभाव से शिवजी को कष्ट होने लगा तब रावण ने कांवड़ में गंगाजल भरकर उन्हें अर्पित किया जिससे उन्हें विष के प्रभाव से मुक्ति मिली। एक अन्य कथा के अनुसार श्रवण कुमार अपने अंधे माता-पिता को तीर्थयात्रा कराना चाहते थे उन्होंने कांवड़ में अपने माता-पिता को बैठाकर हरिद्वार से गंगाजल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। यह भी माना जाता है कि श्रवण कुमार पहले कांवड़िया थे। कुछ लोगों का मानना है कि भगवान परशुराम ने भी गढ़मुक्तेश्वर से गंगाजल लाकर पुरा महादेव में शिव का जलाभिषेक किया था और यह भी कांवड़ यात्रा की शुरुआत का एक कारण है अनेक कांवड़िए यात्रा के दौरान उपवास रखते हैं और दिन-रात शिव का स्मरण करते हैं। मार्ग में सेवा शिविरों में रुकते हैं जहां उन्हें भोजन, दवाई, विश्राम आदि की सुविधाएं दी जाती हैं। कांवड़िए अक्सर भगवा रंग के वस्त्र पहनते हैं, जो त्याग, भक्ति और तपस्या का प्रतीक होता है कांवड़िए अकेले नहीं चलते, वे समूह में यात्रा करते हैं जिससे आपसी सहयोग और एकता की भावना प्रकट होती है। रास्ते में अनेक श्रद्धालु स्वयंसेवक बनकर कांवड़ियों को भोजन, पानी, प्राथमिक चिकित्सा और विश्राम की सुविधा प्रदान करते हैं। ये वे कांवड़िए होते हैं जो बेहद तेज गति से दौड़ते हुए जल लेकर मंदिर तक पहुंचते हैं। इस प्रक्रिया में उनकी पूरी टीम सहयोग करती है। शिव कांवड़ आयोजक समिति के गुड्डू ठाकुर ने कहा कि समाज में कांवड़ियों को भक्ति, अनुशासन और निस्वार्थ सेवा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। यह यात्रा न केवल व्यक्ति को अध्यात्म से जोड़ती है बल्कि एक सामूहिक ऊर्जा और धार्मिक एकजुटता का भी निर्माण करती है। कांवड़ यात्रा से जुड़ी आस्थाएं युवाओं को धार्मिक परंपराओं से जोड़ने में अहम भूमिका निभाती हैं। आधुनिक समय में बड़ी संख्या में युवक इस यात्रा में भाग लेते हैं, जो पारंपरिक श्रद्धा को नई पीढ़ी में जीवित बनाए रखने का कार्य करता है। कई युवा बाइक पर या पैदल, ध्वनि प्रणाली के साथ, उत्सव के रूप में इस यात्रा को करते हैं जिससे यह एक धार्मिक उत्सव और सामाजिक आंदोलन जैसा रूप ले लेता है कांवड़िए सिर्फ तीर्थयात्री नहीं हैं वे भक्ति सेवा और अनुशासन का जीवंत उदाहरण हैं। उनकी यात्रा हमें यह सिखाती है कि आस्था में कितनी शक्ति होती है जो न केवल आत्मा को शुद्ध करती है बल्कि समाज को भी एकजुट करती है। शिव कांवड़ आयोजक समिति के गुड्डू ठाकुर, माया रजक, पूर्णिमा रजक, रानू रजक, नेता नंदा, मुन्ना कोष्टा, राजू नंदा, पप्पू साहू, विश्वकर्मा जी, केसर नंदा, सवीता तिवारी, अमित रजक, तुषार चौरसिया, नरेंद्र लहोरिया सहित अनेक शिवभक्त मौजूद रहे।

संपादकीय

झारखंड का 'जंतर-मंतर'

झारखंड की राजधानी रांची में फटी तिरपाल की छाया में, रात को बिजली काट देने के अंधेरे में, खाने-पीने की अनिश्चितता के साथ युवा छात्र बीते 17 दिनों से 'सत्याग्रह' पर बैठे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, 'आप' के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल, फिलहाल तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पिता-पुत्र उद्धव-आदित्य ठाकरे और 'बुजुर्ग चाणक्य' शरद पवार आदि को क्या एहसास नहीं है कि झारखंड में भी 'जंतर-मंतर' आंदोलित है। देवेन्द्र महतो भी सोनम वांगचुक के रास्ते पर चल निकले हैं। लेकिन रांची का आंदोलन 'जंतर-मंतर' नहीं बन पा रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय नेता चुप हैं, गैर-हाजिर हैं, निष्क्रिय हैं। संसद में उन्हें हंगामा मचाने से फुरसत नहीं है, तो झारखंड के युवा छात्रों का मुद्दा सदन में कैसे उठेगा? हालांकि, महतो ने वांगचुक के आग्रह पर पानी पी लिया, लेकिन कहा कि अनशन जारी रहेगा।

दिल्ली के 'जंतर-मंतर' पर कॉकरोचों ने आंदोलन का आह्वान किया और सोनम वांगचुक जैसे प्रख्यात व्यक्ति ने अनशन किया, तो नेताओं में होड़ मच गई थी कि वह आंदोलन के मंच तक कितनी बार दिखाई दे और टीवी चैनलों पर उसके बयान प्रसारित होते रहें! दरअसल निशाने पर देश के प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह थे, राष्ट्रीय राजधानी का मंच था, विपक्षी लामबंद हो सकते थे, नतीजतन उस 'जंतर-मंतर' ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा लेने को प्रधानमंत्री को बाध्य कर दिया। केंद्र सरकार को 'कॉकरोचों' के साथ समझौते करने पड़े। झारखंड के युवा, बेरोजगार, छात्रों की मांगें भी कमोबेश दिल्लीवाले आंदोलन सरीखी हैं। उन्हें राज्य की झामुमो-कांग्रेस सरकार से न तो मुफ्त की खैरात चाहिए और न ही कोई भत्ता या विशेष योजनाओं के लाभ चाहिए। उनके बुनियादी आग्रह हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग तथा अन्य भर्तियों की परीक्षाएं 'ईमानदारी' से हों और 'घूसखोरी' बंद हो। पेपरलीक ही समस्या नहीं है, बल्कि परीक्षाओं की समयबद्धता और मोटी-मोटी राशियों में नीलाम होती सरकारी नौकरियां भी युवा छात्रों की बुनियादी चिंता और सरोकार हैं। पेपरलीक और नौकरियों की खरीद-फरोख्त के 'हम्माम' में सभी नंगे हैं, जो सरकारों का हिस्सा रहे हैं। लिहाजा 2005-26 तक देश में कुल 220 पेपर लीक कराए गए हैं, परीक्षाएं रद्द करानी पड़ी हैं, नतीजतन 10 करोड़ से अधिक युवा, छात्र प्रभावित हुए हैं। सरकारें 'माफिया' को नियंत्रित करने में नाकाम हैं। लेकिन अब बड़े नेताओ को सावधान हो जाना चाहिए! यह युवा पीढ़ी का आक्रोश है। 15-29 साल के करीब 60 करोड़ किशोर और युवा हैं, वे ही धरने पर बैठे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलित हैं। ये इतने सक्षम हैं कि देश भर में 'जंतर-मंतर' सजा सकते हैं। ये परंपरागत सरकारों और राजनीतिक दलों की 'सत्ताशाही' उखाड़ फेंक सकते हैं। झारखंड में भाजपा विपक्ष में है। उसके नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य लोक सेवा आयोग की हालिया परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग की है। छात्र भी सीबीआई और ईडी जांच की मांग रहे हैं। यही पर्याप्त नहीं है। हेमंत सोरेन राज्य के युवा मतदाताओं और नागरिकों से ऊपर नहीं हैं, जनता के माई-बाप भी नहीं हैं, लिहाजा युवा निराश न हों। सर्वोच्च अदालत का फैसला भी युवाओं के पक्ष में है, लिहाजा आपराधिक मामले दर्ज करने से भी न घबराएं। मुख्यमंत्री भी दिलासा के बयानों से बचें। बल्कि आंदोलित युवाओं के एक प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रित करें और उनकी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर समाधान देने का प्रयास करें। लोकतंत्र में यही सरकार का दायित्व होता है। सरकारें तानाशाह नहीं हो सकतीं। पांच साल बाद नया जनादेश मांगना होता है। मतदाता ही अंतिम निर्णय कर सकते हैं।

सरकारों की हालत खेत खाए गदहा और मार खाए जुलहा जैसी

अफसरों को जिम्मेदार ठहराने से होगा समस्याओं का समाधान

योगेंद्र योगी

संशोधित केंद्रीय पेपर लीक कानून में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने पर कम से कम 5 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष तक की सजा होगी। अधिकतम जुर्माना 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया गया है। संगठित अपराधों में 7 से 10 वर्ष तक की सजा और 10 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

देश की सरकारों के पास हर समस्या का एक लाइलाज रामबाण इलाज यह है कि किसी समस्या की गहराई के उपचार के बजाए कानून बना दिया जाए। सरकारें हर समस्या का इलाज व्यवहारिक धरातल पर नहीं बल्कि कानून में ढूंढने की आदी हो चुकी हैं। देश में हर क्षेत्र में एक के बाद एक नए कानून बनाए जा रहे हैं, किन्तु समस्याएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जितने भी नए कानून बनाए जा रहे हैं, या पुराने कानूनों मे संशोधन किया जा रहा, उसका सारा भार देश के आम लोगों पर ही डाला जा रहा है। इन कूननों में कहीं लापरवाही बरतने या अनदेखी के लिए देश के आला अफसर जिम्मेदार नहीं हैं। आजादी से लेकर आज तक ऐसा कोई कानून केंद्र या किसी राज्य ने नहीं बनाया है कि यदि कोई घटना-दुर्घटना या कांड होगा तो उसके लिए सीधे अफसर भी जिम्मेदार माने जाएंगे।

संशोधित केंद्रीय पेपर लीक कानून में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने पर कम से कम 5 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष तक की सजा होगी। अधिकतम जुर्माना 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया गया है। संगठित अपराधों में 7 से 10 वर्ष तक की सजा और 10 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। पेपर लीक का नया केंद्रीय कानून बनाने के बावजूद झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) परीक्षा में पेपर लीक और अनियमितताएं हुईं। इस मामले में अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जेपीएससी के चेयरमैन एल. खियांगटे ने इस्तीफा भी दे दिया। केंद्र सरकार के बनाए पेपर लीक परीक्षा कानून देश में एक अगस्त से अस्तित्व मे आ चुका है। इसके बावजूद देश में भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक मामले थम नहीं रहे हैं। अखबार

राजस्थान में अप्रैल 2022 में एंटी पेपर लीक एक्ट लागू किया गया। गुजरात में मार्च 2023 से सख्त नकल और पेपर लीक विरोधी कानून लागू। उत्तराखंड में वर्ष 2023 में प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश/कानून लागू किया गया। झारखंड में वर्ष 2023 में अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए अधिनियम बनाया गया। हरियाणा में सितंबर 2021 से प्रभावी कानून लागू है। इसी तरह असम, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में भी अलग-अलग वर्षों में इससे जुड़े कड़े कानूनी प्रावधान या अधिनियम बनाए जा चुके हैं। केंद्र और इतने राज्यों में पेपर लीक कानून के बाद भी पेपर लीक की घटनाएं थम नहीं रही है।

पेपर लीक की तरह देश में बलात्कार के मामलों में बेहद कठोर कानून बनाए गए थे। बलात्कार और इसके साथ हत्या के मामलों में फांसी तक का प्रावधान किया गया है। 2012 में दिल्ली में एक छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या के दोषी चार भारतीय पुरुषों को फांसी दे दी गई थी।

निर्भया बलात्कार हत्याकांड से लोगों में आक्रोश फैल गया था और भारत में बलात्कार विरोधी नए कानून बनाए गए। आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 के तहत 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के बलात्कार में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया। गैंग रेप में न्यूनतम सजा 20 साल से आजीवन की गई।

इतने कठोर कानून के लागू होने के बावजूद देश में बलात्कार-हत्या के मामले बढ़ते चले गए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के मुताबिक देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साल 2023 में 31,982 महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले दर्ज हुए। इससे जाहिर है कि नए कठोर कानूनों का अपराधियों को कोई भय नहीं है। ये कानून महज कागज का पुलिन्दा साबित हो रहे हैं।

यही भ्रष्टाचार का भी हाल है। देश में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कठोर कानून बने हुए हैं, इसके बावजूद देश से भ्रष्टाचार खत्म होना तो दूर बल्कि कम तक नहीं हो सका। आए दिन कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की खबरें आती रहती हैं। भ्रष्टाचार खत्म नहीं करने के लिए कभी किसी अफसर को जिम्मेदार नहीं माना गया। बेशक उनके विभाग का ही कोई भ्रष्टाचारी क्यों न पकड़ा जाए।

आज तक जितने भी कानून बनाए गए हैं, उसमें अफसरों की जिम्मेदारी कहीं भी तय नहीं की गई। मसलन सड़क पर गडढा होने से यदि कोई सड़क दुर्घटना होती है या फिर बगैर अग्नि सुरक्षा उपायों के संचालित किसी व्यवसायिक भवन में अग्नि दुर्घटना होती है तो इसके निगरानी करने वाले अफसर जिम्मेदार ठहराए जाएंगे, ऐसा कोई कानून नहीं बना है। यही प्रमुख वजह है कि चाहे पेपर लीक हों या किसी तरह का बड़ा हादसा, कानूनों को सख्त कर दिया जाता है, किन्तु जिम्मेदार अधिकारियों की जिम्मेदारी तय नहीं की जाती।

इसका बड़ा उदाहरण मेलों, धार्मिक स्थलों पर होने वाले आयोजनों में भगदड़ के दौरान होने वाली मौतें हैं। ऐसा शायद ही कोई साल जाता होगा, जब ऐसे हादसे नहीं होते होंगे। ऐसे हादसों में अब तक देश भर में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद अफसरों की ज्मिमेदारी तय नहीं की गई। ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया कि ऐसे आयोजनों में हादसों के लिए सीधे अफसर जिम्मेदार ठहराएं जाएंगे, उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलेगा और उन्हे जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी। भौगोलिकसंदर्भ

अफसरों की लापरवाही से हुए हादसों और इससे बच निकलने का बड़ा उदाहरण राजस्थान का है। जहां दो साल पहले स्कूल की छत्त गिरने से 10 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई, इसके बाद भी स्कूल की छत्त गिरने या दीवार गिरने के हादसे होते रहे, किन्तु एक भी अफसर को आपराधिक आरोपी नहीं माना गया। किसी पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। पुलिस ने आईएएस अफसर तो दूर बल्कि शिक्षा विभाग के किसी अफसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की। राजस्थान सहित देश के लाखों सरकारी स्कूलों की इमारतों की हालत खस्ता है। सरकारों के पास इतना बजट ही नहीं है कि इतना रखरखाव किया जा सके।

यह निश्चित है कि चुनी हुई सरकारें लंबे अर्से तक देश के लोगों की आंखों में धूल नहीं झौंक सकती, उन्हें कानून बनाने के साथ ही धरातल पर समस्याओं का समाधान ढूंढना होगा। देश में बुनियादी सुविधाओं की पहुंच आम नागरिकों तक बढ़ानी होगी। इसकी कमी से हर साल बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल के अभाव जैसे मुद्दों पर धरने, प्रदर्शन, आंदोलन होते हैं, किन्तु इनका स्थायी समाधान नहीं होता। सरकारों की हालत खेत खाए गदहा और मार खाए जुलहा जैसी है। जब तक सरकारें और जिम्मेदार अफसर अपनी जिम्मेदारी से भागते रहेंगे। ऐसी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, बेशक कितने भी नए कानून बन जाएं।

संसद चलती रहे, सवाल भी उठें और सरकार जवाब भी दे, आखिर लोकतंत्र में गतिरोध कब तक?

हिमांशु सिंह चंदेल

मानसून सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच लगातार टकराव ने संसद की कार्यवाही और उसकी उत्पादकता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सदनों की कार्यवाही बार-बार स्थगित हुई और कई विधेयक पर्याप्त चर्चा के बिना पारित हुए। सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री के जवाब की मांग स्वीकार की है। ऐसे में सवाल है कि क्या यह पहल संसद को दोबारा सुचारु रूप से चलाने की शुरुआत बनेगी?

पूरे मानसून सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच बढ़ते मतभेदों का सबसे बड़ा नुकसान संसद की कार्यवाही को हुआ है। संसद देश का वह मंच है, जहां जनता से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठते हैं, सरकार जवाब देती है और कानूनों पर चर्चा होती है। लेकिन लगातार हंगामे और गतिरोध के कारण इस काम में बाधा आई है। जिन सदनों में हर दिन औसतन सात घंटे काम होने की अपेक्षा रहती है, वहां कार्यवाही कई बार करीब एक घंटे तक ही सिमट गई। यह स्थिति किसी एक दल की जीत या हार नहीं, बल्कि पूरे संसदीय तंत्र के लिए चिंता का विषय है।

क्या सरकार ने विपक्ष की मांग मानकर गतिरोध तोड़ने की कोशिश की है?

विपक्ष की मांग को स्वीकार करते हुए सरकार ने दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री के जवाब देने पर सहमति जताई है। यह कदम संसद में बने गतिरोध को खत्म करने की दिशा में एक शुरुआत हो सकता है। विपक्ष सवाल पूछता है और सरकार से जवाब मांगता है, यह संसदीय लोकतंत्र की सामान्य प्रक्रिया है। इसलिए अगर सरकार गृह मंत्री के जरिए इस मुद्दे पर सदन में जवाब देने को तैयार है, तो विपक्ष के सामने भी यह अवसर है कि वह संवाद के रास्ते को आगे बढ़ाए।

88 बार कार्यवाही स्थगित होना क्या बताता है?

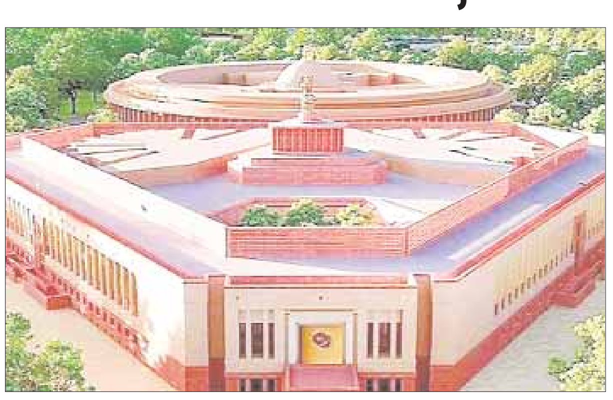

संसद की कार्यवाही का बार-बार रुकना केवल सदन के भीतर का घटनाक्रम नहीं है। दोनों सदनों की कार्यवाही अब तक 88 बार स्थगित हो चुकी है। इसका मतलब है कि संसद के पास उपलब्ध समय का बड़ा हिस्सा कामकाज के बजाय व्यवधान में चला गया। संसद का समय राष्ट्रीय संपत्ति है। इस समय का इस्तेमाल कानून बनाने, जनता की समस्याओं पर चर्चा करने और सरकार से जवाब मांगने में होना चाहिए। हंगामे के कारण जब कार्यवाही रुकती है, तो उसका असर सीधे उस जनता पर पड़ता है, जिसके नाम पर सांसद सदन में पहुंचते हैं।

क्या बिना पर्याप्त चर्चा के विधेयक पारित होना सही है?

इस पूरे विवाद का एक गंभीर पहलू उन विधेयकों को लेकर भी है, जिन्हें लोकसभा में पर्याप्त चर्चा के बिना पारित कराया गया है। कानून बनाना जरूरी है, लेकिन कानून के हर प्रावधान को समझना और उसके संभावित असर पर चर्चा करना भी उतना ही जरूरी है। किसी विधेयक से समाज और अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, उसे लागू करने में क्या दिक्कतें आएंगी और उससे जुड़े सांविधानिक सवाल क्या हैं, इन मुद्दों पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। यही वह एकमात्र पैराग्राफ है, जहां बातों को बिंदुवार समझा जा सकता है। विधेयक का असर, सामाजिक-आर्थिक परिणाम, क्रियान्वयन की दिक्कतें और सांविधानिक सवाल।

क्या सरकार और विपक्ष दोनों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी?

संसद में गतिरोध की जिम्मेदारी केवल सरकार या केवल विपक्ष पर डालकर समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। विपक्ष का काम सरकार से सवाल पूछना और उसकी नीतियों की जांच करना है, जबकि सरकार की जिम्मेदारी सवालों का जवाब देना और सदन को चलाने के लिए जरूरी सहमति बनाना है। बार-बार सदन रोकना कुछ समय के लिए राजनीतिक मुद्दा जरूर बन सकता है, लेकिन इससे संसदीय गरिमा मजबूत नहीं होती। इसी तरह महत्वपूर्ण विधेयकों को संसदीय समितियों के पास भेजने की परंपरा को मजबूत करना भी जरूरी है, ताकि कानून बनने से पहले उनका पर्याप्त परीक्षण हो सके।

क्या गृह मंत्री का जवाब गतिरोध खत्म करने का रास्ता खोल सकता है?

गृह मंत्री का सदन में आकर प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर जवाब देना सरकार और विपक्ष के बीच बातचीत की शुरुआत बन सकता है। अब जरूरत इस बात की है कि दोनों पक्ष इस मौके को व्यापक संवाद में बदलें। संसद में विपक्ष सवाल पूछे, सरकार जवाब दे और विधेयकों पर गंभीर चर्चा हो, यही संसदीय लोकतंत्र की बुनियादी भावना है। हंगामे से किसी दल को तत्काल राजनीतिक फायदा दिखाई दे सकता है, लेकिन लंबे समय में इसकी कीमत संसद और जनता दोनों को चुकानी पड़ती है। इसलिए सबसे जरूरी सवाल यही है कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह रहें, लेकिन संसद का कामकाज क्यों रुके?

मुस्लिम नाटो की राह

बदलती सामरिक तस्वीर में नए आयाम के संकेत से पाक उत्साहित, भारत को सतर्क रहने की जरूरत

ज्योति भास्कर

तुर्किये, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच पिछले दिनों हुआ रक्षा समझौता पश्चिम एशिया की बदलती सामरिक तस्वीर में एक नए आयाम के जुड़ने का संकेत है। इससे भारत के लिए तत्काल कोई खतरा तो नहीं, पर मुस्लिम नाटो को लेकर पाकिस्तान के उत्साह को देखते हुए उसे सतर्क रहने की जरूरत है।

पिछले दिनों मक्का में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये के बीच हुआ रक्षा समझौता, जिसके तहत किसी एक देश पर हमला, तीनों देशों पर सामूहिक हमला माना जाएगा, पश्चिम एशिया की बदलती सामरिक तस्वीर में एक नए आयाम के जुड़ने का संकेत है। उल्लेखनीय है कि समझौता आधिकारिक तौर पर किसी देश को साझा शत्रु के रूप में चिह्नित करने से बचता है, लेकिन पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जिस तरह से समझौते की घोषणा के अगले ही दिन मुस्लिम देशों से इस्राइल के खिलाफ एकजुट होने और साझा सैन्य मोर्चा बनाने का आह्वान किया है, वह येरूशलम के साथ-साथ भारत जैसे देशों की चिंताएं भी बढ़ाने वाला है। दरअसल, सामूहिक रक्षा समझौते का औचित्य तभी तक विश्वसनीय रहता है, जब तक उसका उद्देश्य अपने सदस्यों की सुरक्षा तक सीमित हो। लेकिन, अगर यही व्यवस्था किसी धार्मिक या राजनीतिक पहचान के आधार पर साझा शत्रु गढ़ने का जरिया बन जाए, तो उसके नतीजे कहीं अधिक गंभीर हो सकते हैं और यही इस समझौते का सबसे बड़ा जोखिम भी है। खास बात यह है कि तीनों देशों की क्षमताएं भी एक-दूसरे की पूरक हैं। सऊदी अरब के पास आर्थिक शक्ति और रक्षा पर भारी निवेश की क्षमता है।

तुर्किये के पास विकसित रक्षा उद्योग, ड्रोन तकनीक, सैन्य अनुभव और नाटो सदस्य होने के नाते रणनीतिक पहुंच है। पाकिस्तान के पास भी बड़ी और अनुभवी सेना, मिसाइल क्षमता तथा परमाणु प्रतिरोधक क्षमता है। लिहाजा यह समझौता केवल प्रतीकात्मक नहीं रह जाता, बल्कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित करने की भी पूरी क्षमता रखता है। यही वजह है कि ख्वाजा आसिफ की मुस्लिम नाटो बनाने का संकेत देती टिप्पणी को महज राजनीतिक बयान मानकर खारिज नहीं किया जा सकता। हालांकि जो वह कह रहे हैं, वह इतना आसान नहीं होगा।

पाकिस्तान बेशक इस्राइल को मान्यता न दे, लेकिन तुर्किये का मामला बिल्कुल अलग है। वह इस्राइल को मान्यता देता है और कुछ तनावों के बावजूद दोनों के बीच दशकों से राजनयिक संबंध भी रहे हैं। इसी तरह, अमेरिका के साथ संबंधों के मद्देनजर सऊदी अरब के लिए भी यह आसान नहीं होगा कि वह सीधे तौर पर इस्राइल के खिलाफ खड़ा हो जाए। जहां तक भारत की बात है, तो उसने पश्चिम एशिया के लगभग सभी प्रमुख देशों के साथ अलग-अलग स्तर पर मजबूत संबंध बनाए हैं, जो उसकी संतुलित और बहुस्तरीय विदेश नीति की सबसे बड़ी रणनीतिक पूंजी भी है। फिर भी, मुस्लिम नाटो के गठन को लेकर पाकिस्तान के उत्साह को देखते हुए उसे क्षेत्र की बदलती भू-राजनीति पर सतर्क निगाह रखने की जरूरत है।

मानसून का बदलना अब एक स्थायी संकट, जलवायु परिवर्तन की कहानी भी छिपी

सीमा जावेद

इस साल के मानसून में जलवायु परिवर्तन की कहानी छिपी है। यह बताती है कि अब मानसून का स्वरूप स्थायी रूप से बदल चुका है।

मजबूत होते अल-नीनो के कारण सामान्य से कम बारिश के अनुमान के बावजूद, जुलाई में बारिश का लक्ष्य पार हो गया। वहीं, गुजरात से लेकर असम तक इस साल फिर बरसात के मौसम ने तबाही मचा दी। मानसूनी बारिश और नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ के कारण असम, गुजरात, केरल, कर्नाटक, ओडिशा और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों में लाखों लोग प्रभावित हुए हैं और जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। दूसरी तरफ झारखंड सूखे की मार से जूझ रहा है। इससे यह साफ हो गया है कि जलवायु परिवर्तन भारत के मानसून को बदल रहा है। असम, महाराष्ट्र, गुजरात और हिमाचल प्रदेश जैसे इलाकों में बादल फटने की जानलेवा घटनाओं, शहरों में जल-जमाव और भूस्खलन का सिलसिला जारी रहा है।

अगस्त और सितंबर, 2025 में, पूर्वी पाकिस्तान और उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर बाढ़ आई थी। यह बाढ़ मुख्य रूप से भारत के हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हुई भारी मानसूनी बारिश के कारण आई थी। इसके बाद अचानक आई बाढ़ (फ्लैश फ्लड) की वजह से भारतीय अधिकारियों को भारत और पाकिस्तान, दोनों के पंजाब में बहने वाली कई नदियों पर बने बांध खोलने पड़े, जिससे निचले इलाकों में बड़े पैमाने पर बाढ़ आ गई। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 1,400 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ गए, और भारत के पंजाब राज्य में भी 1,400 गांव प्रभावित हुए।

इस साल भी पिछले साल की तरह ही इस मानसून में बादल फटने की नौ घटनाएं, अचानक बाढ़ की 19 घटनाएं सामने आई हैं। बादल फटने से प्रभावित चार बड़े इलाकों में 120 सड़कें बंद हो गई हैं और पीने के पानी की

आपूर्ति बाधित हुई है। जम्मू-कश्मीर में भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ के कारण लोगों और पर्यटकों को यात्रा न करने की सलाह दी गई है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर जैसे उत्तरी राज्यों में लगभग हर साल ही अचानक आने वाली बाढ़ और बादल फटने की घटनाएं होती रहती हैं। दूसरी तरफ, झारखंड में मानसून में 40-79 फीसदी की कमी के चलते खरीफ फसलों की बुआई और रोपाई पर असर पड़ा है। बारिश कम होने से धान और दूसरी फसलों के उत्पादन में कमी आ सकती है। ऐसे में, सरकार ने किसानों को बाजरा बोने की सलाह दी है।

वैज्ञानिकों के अनुसार, जलवायु परिवर्तन की वजह से गर्मी हद पार करती जा रही है। साथ ही, वातावरण में नमी बेहिसाब ढंग से बढ़ रही है। ऐसे में, मौसम का अंदाज बदल रहा है। पहले गर्मियों में तेज लू चलती थी। पसीना आता था, लेकिन जल्दी सूख जाता था। अब गर्मी के साथ उमस भी बढ़ गई है, जिससे शरीर को ज्यादा घुटन और बेचैनी महसूस होती है। अब पसीना सूखता नहीं और न ही शरीर ठंडा होता है। विशेषज्ञों के मुताबिक, पहले मानसून में कई दिनों तक हल्की या मध्यम बारिश होती थी। अब स्थिति बदल रही है। बारिश वाले दिनों की संख्या घट रही है, पर जब बारिश होती है, तो बहुत कम समय में अत्यधिक मात्रा में पानी बरसता है। इसका कारण गर्म होती हवा और समुद्र हैं, जो वातावरण में पहले से अधिक नमी जमा कर रहे हैं। यही नमी बादलों को बेहद भारी बना देती है। इसका एक कारण नदी घाटियों के किनारे बहुत ज्यादा खनन कार्य करना भी है, जिससे गाद जमा होने की समस्या बढ़ी और नदी की पानी ले जाने की क्षमता कम हो गई।

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व महानिदेशक डॉ. के जे रमेश के अनुसार, अब मानसून का स्वरूप स्थायी रूप से बदल चुका है। चाहे अल-नीनो हो या न हो, भविष्य में बारिश कम समय में और अधिक तीव्रता के साथ होने की संभावना बढ़ती जाएगी। उन्होंने कहा कि अरब सागर के रिकॉर्ड स्तर तक गर्म होने से उत्तर-पश्चिम भारत में भी बारिश का पैटर्न बदल रहा है। अध्ययनों से पता चलता है कि भारत के कई हिस्सों में मौसम में उतार-चढ़ाव अनियमित होते जा रहे हैं। सूखे या अल-नीनो के बावजूद, कुछ जगहों पर कई दिनों तक भारी बारिश (सामान्य से कई गुना ज्यादा) होती है।

एक अध्ययन के अनुसार, भविष्य में महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में भारी बारिश वाले दिनों की संख्या लगभग एक सप्ताह तक बढ़ सकती है। ऐसे में, अब समय आ गया है कि जलवायु अनुकूल शहरी योजना पर निवेश बढ़ाना होगा। इस साल के मानसून में दरअसल जलवायु परिवर्तन की कहानी छिपी है, जो एक अहम संदेश दे रही है। चुनौती सिर्फ यह नहीं है कि कितनी बारिश होगी, बल्कि यह भी है कि बारिश किस तरह होगी। अगर शहर पुराने मौसम के हिसाब से बने रहेंगे, तो बदलती जलवायु के साथ आने वाली ऐसी चरम बारिश उन्हें बार-बार संकट में डालती रहेगी।

उलझ जाएगी सीमा वार्ता, अरुणाचल प्रदेश का नया मैप जारी करने पर चीन को लगी मिर्ची

बीजिंग

अरुणाचल प्रदेश में 27 भौगोलिक जगहों के लिए स्टैंडर्ड नाम तय करने पर चीन ने भारत को कड़ा जवाब दिया है। सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स का दावा है कि ये इलाके चीन के जांगनान क्षेत्र में आते हैं। दरअसल, चीन अरुणाचल प्रदेश और उससे सटे इलाकों को इसी नाम से बुलाता है और उन पर तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र का हिस्सा होने का दावा करता है।

अखबार ने बताया कि चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने 14 अप्रैल को एक रेगुलर प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि जांगनान इलाका चीन का हिस्सा है और चीन भारत द्वारा गैर-कानूनी तरीके से बनाए गए तथाकथित अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं देता है। चीनी सरकार का जांगनान की कुछ जगहों के लिए स्टैंडर्ड नाम जारी करना पूरी तरह से चीन के संप्रभु अधिकारों के दायरे में आता है।

भारत ने तय किए अरुणाचल की जगहों के नाम

यह प्रतिक्रिया तब आई जब भारत के सर्वे ऑफ इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश में 21 इलाकों, चार दर्रों, ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद एक ग्लेशियल झील और 1962 के युद्ध के हीरो के स्मारक की पहचान करते हुए अपना आधिकारिक नक्शा अपडेट किया। सरकार का कहना था कि यह कदम जगहों की सही पहचान सुनिश्चित करने और उनके भौगोलिक और ऐतिहासिक महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए उठाया गया था।

चीन का क्या कहना है?

ग्लोबल टाइम्स ने रविवार रात को रिपोर्ट दी कि भारत की ओर से यह मैपिंग, चीन-भारत सीमा मामलों पर बातचीत और समन्वय के लिए बने वर्किंग मैकेनिज्म की 36वीं बैठक के ठीक बाद हुई। यह बैठक 6 अगस्त को नई दिल्ली में हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों के अधिकारियों ने सीमा तय करने, सीमा प्रबंधन और नियंत्रण, सिस्टम बनाने और सीमा-पार सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा की थी। शंघाई इंटरनेशनल स्टडीज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गुओ जुएतांग ने कहा, भारत का यह ताजा कदम असल में विवादित इलाके पर अपने दावों को मजबूत करने और चीन की संप्रभुता के रुख का मुकाबला करने की कोशिश है।

अमेरिका की अदालत ने अडानी के खिलाफ मामला खारिज किया

नयी दिल्ली, (वार्ता)। अमेरिका की एक अदालत ने भारतीय अरबपति कारोबारी गौतम अडानी के खिलाफ एक आपराधिक मामला खारिज कर दिया। ब्रुकलिन स्थित जिला अदालत के जज ने इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि अमेरिका के न्याय विभाग ने अडानी समूह के देश में 10 अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता से प्रभावित हुए बिना मामला वापस लेने का आवेदन दिया है, विभाग के आवेदन को स्वीकृति प्रदान कर दी। न्याय विभाग ने इस साल मई में मामला वापस लेने के लिए अदालत के समक्ष आवेदन किया था। इसके बाद अदालत ने अडानी समूह से पूछा था कि न्याय विभाग के इस कदम के बदले में उसने क्या प्रत्युपकार किया था। श्री अडानी ने अमेरिका की अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, इस चुनौती पूर्ण समय में कानून की सच्चाई और निष्पक्षता में हमारा विश्वास अटल रहा। उन्होंने उन सभी लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जिन्होंने हमारे ऊपर, तंत्र के ऊपर और भारत की न्याय क्षमता पर विश्वास बनाये रखा।

म्यांमार में सेना ने नागरिकों पर जानबूझकर हमले किये: संयुक्त राष्ट्र

जेनेवा, (वार्ता)

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि म्यांमार की सेना ने नागरिकों को निशाना बनाकर लगातार हमले किए हैं। इनमें घरों, स्कूलों और विस्थापित लोगों के शिविरों पर हवाई हमले, मनमानी गिरफ्तारियां, यातना और यौन हिंसा शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव मैकेनिज्म फॉर म्यांमार (आईआईएमएम) की रिपोर्ट में ये निष्कर्ष सामने आए हैं। जांचकर्ताओं ने जुलाई 2025 से जून 2026 तक की अवधि के दौरान हुई घटनाओं के अध्ययन के बाद यह रिपोर्ट जारी की है।

आईआईएमएम के प्रमुख निकोलस कौमजियन ने कहा कि जांच का एक प्रमुख क्षेत्र म्यांमार में समुदायों के खिलाफ किए जा रहे हवाई हमले हैं। उन्होंने कहा कि जांचकर्ता यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन हमलों के लिए आदेश किस स्तर से दिए गए और सेना की कमान की संरचना कैसे काम करती है।

श्री कौमजियन ने कहा कि कई हवाई हमलों में स्कूलों को निशाना बनाया गया, जिनमें बड़ी संख्या में बच्चे प्रभावित हुए। अस्पतालों पर किए गए हमलों की भी जांच की जा रही है। जांचकर्ता इन हमलों के स्थान, उनमें इस्तेमाल किए गए हथियारों और गोला-बारूद समेत अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटा रहे हैं।

म्यांमार में फरवरी 2021 में सेना द्वारा सत्ता पर कब्जा किए जाने के बाद से संघर्ष जारी है। सेना ने निर्वाचित सरकार को हटा दिया था और राष्ट्रपति विन मिंट तथा स्टेट काउंसलर आंग सान सू ची समेत शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। सैन्य तख्तापलट के बाद देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए और बाद में सशस्त्र प्रतिरोध आंदोलन उभरे। इन समूहों का देश के बड़े हिस्से पर नियंत्रण है।

रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी में संपन्न चुनावों से पहले सैन्य हमले तेज हो गए थे और उसके बाद भी जारी रहे। जांचकर्ताओं ने घरों, स्कूलों, चिकित्सा केंद्रों, धार्मिक स्थलों और विस्थापित लोगों के शिविरों पर हुए हमलों का पता लगाया है। उन्होंने कुछ हमलों के लिए जिम्मेदार सैन्य इकाइयों की भी पहचान की है।

जांचकर्ताओं के मुताबिक, सेना द्वारा मोटरयुक्त पावर ग्लाइडर और ड्रोन के बढ़ते इस्तेमाल से नागरिकों के लिए हवाई हमलों का पहले से अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया है। इसके चलते लोगों को हमले से बचने के लिए सुरक्षित स्थान या आश्रय तलाशने का समय भी कम मिल रहा है।

आईआईएमएम ने सैन्य नियंत्रण वाले हिरासत केंद्रों में व्यापक यातना और यौन हिंसा के मामलों का भी दस्तावेजीकरण किया है। जांचकर्ताओं के अनुसार, इनमें ऐसे मामले भी शामिल हैं जो 2025 में लागू उस कानून से जुड़े हैं, जिसके तहत चुनावों की आलोचना को अपराध बनाया गया। इस कानून के तहत ऑनलाइन आलोचनात्मक टिप्पणी करने जैसे कृत्यों के लिए भी लोगों को 20 साल तक की जेल या मौत की सजा का सामना करना पड़ सकता है।

कोलंबिया भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 132 हुई, राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया

बोगोटा, (वार्ता)। कोलंबिया में आए विनाशकारी भूकंप के बाद अबतक कम से कम 132 लोगों की मौत हो गई है और 570 से अधिक लोग घायल हुए हैं। त्रासदी की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रपति एबेलार्डो डी ला एस्प्रिएला ने देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है, जबकि राहत एवं बचाव दल ढही हुई इमारतों के मलबे से लोगों को निकालने में जुटे हुए हैं। कोलंबियाई भूवैज्ञानिक सेवा के अनुसार, यह इस सदी में देश में दर्ज किया गया सबसे शक्तिशाली भूकंप था। भूकंप की तीव्रता 7.4 मापी गयी थी। इसका केंद्र राजधानी बोगोटा से लगभग 240 किलोमीटर दूर संजोस डेल पाल्मार के पास था। अधिकारियों ने आशंका जतायी की मृतकों की संख्या अभी और बढ़ सकती है क्योंकि देशभर में 86 इमारतें पूरी तरह ढह गई है। कोलंबिया के प्रमुख कॉफी उत्पादक क्षेत्र परेरा में सबसे अधिक कम से कम 60 लोगों की मौत दर्ज की गई है। काली शहर से 188 लोग लापता बताए जा रहे हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पांच प्रमुख प्रांतीय राजधानियों में रेड अलर्ट जारी किया गया है और सात हवाई अड्डों पर परिचालन स्थगित कर दिया गया है। परेरा में एक एरियल केबल कार में लगभग छह घंटे तक फंसे 16 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। राष्ट्रपति एस्प्रिएला ने आपातकाल की घोषणा करते हुए राहत कार्यों के लिए सभी सरकारी संसाधनों को तैनात करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा, हमारी पहली प्राथमिकता मलबे में दबे लोगों को बचाना है। अमेरिका ने कोलंबिया को भोजन, आश्रय और राहत कार्यों के लिए 1.55 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। उल्लेखनीय है कि पहाड़ी और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण यह क्षेत्र वर्ष 1999 में भी एक भीषण भूकंप से तबाह हुआ था, जिसमें लगभग 1,200 लोगों की मौत हुई थी।

सत्ता और विपक्ष के राजनीतिक षड्यंत्र से दूर रहें छात्र युवा: मायावती

लखनऊ, (वार्ता)

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती ने मंगलवार को देश के छात्रों, युवाओं और जेन-जी से अपील की है कि वे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सत्ता और विपक्ष की ओर से चलाए जा रहे राजनीतिक षड्यंत्रों से सावधान रहें और किसी भी दल को अपने मुद्दों का नाजायज राजनीतिक लाभ न उठाने दें। सुश्री मायावती ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले कुछ समय से संसद में सत्ता और विपक्ष, खासकर भाजपा और कांग्रेस के लोग किसी न किसी मुद्दे की आड़ में जनहित के ज्वलंत मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं।

यह केंद्र और राज्यों की सरकारों की कमियों से जनता का ध्यान हटाने की अंदरूनी मिलीभगत है या इसके पीछे सत्ता हथियाने की साजिश है, यह सब देश की जनता को सीधे तौर पर नजर आ रहा है।

उन्होंने कहा कि देश के छात्र और नौजवान यानी जेन-जी भी अपनी अनेक समस्याओं को लेकर दुखी और चिंतित हैं। बसपा उनकी समस्याओं को लेकर हमेशा उनके साथ खड़ी रही है। उन्होंने कहा कि छात्रों और नौजवानों का आंदोलन देश के समस्त छात्र-नौजवान पीढ़ी और उनके परिवारों की गंभीर समस्याओं से जुड़ा है और बसपा उनके निदान को लेकर लगातार गंभीर एवं अपने तरीके से संघर्षरत है। सुश्री मायावती ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों, नौजवानों और जेन-जी के आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अब इस आंदोलन की आड़ में संसद भी नहीं चल पा रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के बाद झारखंड की राजधानी रांची में भी छात्र और नौजवान अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। बसपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि वहां भी कांग्रेस और उसके समर्थक दल खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, जबकि भाजपा और उसके सहयोगी दल आंदोलन के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे ऐसा लगता है कि इन दलों ने भी आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। दिल्ली के जंतर-मंतर और रांची के आंदोलनों की आड़ में राजनीतिक दलों को समस्याओं का समाधान करने से ज्यादा राजनीति करने का मौका मिल रहा है। इससे स्पष्ट है कि युवाओं की समस्याओं के समाधान के बजाय चुनावी स्वार्थ की संकीर्ण राजनीति हावी हो रही है। उन्होंने देश के छात्रों और नौजवानों से अपील की कि वे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सत्ता और विपक्ष के इस समय चल रहे षड्यंत्र से बिल्कुल दूर रहें। युवा अपनी समस्याओं से निपटने के लिए राजनीतिक दलों का सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करें, लेकिन किसी भी दल को अपने स्वार्थ की संकीर्ण राजनीति कर उनका नाजायज फायदा न उठाने दें। मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बसपा की चार बार रही सरकारों में छात्रों और नौजवानों को किसी भी मामले में निराश नहीं होने दिया गया। उनकी छोटी-बड़ी समस्याओं के समाधान के साथ-साथ उनके रोजगार पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने कहा कि बसपा सरकारों में सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए गए। पूर्ववर्ती सरकारों में सरकारी भर्तियों पर लंबे समय से लगी रोक हटाकर लाखों लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराए गए।

ईरान ने खुद को अजेय शक्ति साबित किया : अराघची

तेहरान, (वार्ता)

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि उनके देश ने दुनिया के सामने खुद को एक कठिन और अजेय शक्ति के रूप में साबित किया है तथा अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ मजबूती से खड़ा रहकर सभी को आश्चर्यचकित किया है। श्री अराघची ने ईरानी सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि विभिन्न देशों के विदेश मंत्रियों और अधिकारियों ने उनसे कई बार कहा है कि ईरान ने चमत्कार कर पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया है।

उन्होंने कहा, किसी ने नहीं सोचा था कि ईरान इस तरह अमेरिका का मुकाबला कर सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को इजरायल, पश्चिमी देशों और कुछ अन्य देशों का समर्थन प्राप्त था, इसके बावजूद ईरान ने उसका सामना किया। श्री अराघची ने युद्ध की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान से की गयी मांग का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि श्री ट्रंप ने युद्ध की शुरुआत में सोशल मीडिया पर दो शब्द लिखे थे, अनकंडीशनल सरेंडर (बिना शर्त आत्मसमर्पण)। वे हमसे यही चाहते थे और 20 दिन बाद वही दुश्मन बातचीत के लिए गुहार लगा रहा था। श्री अराघची ने यह टिप्पणी ऐसे समय की है जब ईरान तथा अमेरिका के बीच तनाव के दौरान बातचीत और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर लगातार परस्पर विरोधी दावे सामने आ रहे हैं।

मुझे अभी भी उसकी याद आती है, चीन में एआई पर सख्ती के बाद वर्चुअल ब्वॉयफ्रेंड खोने का गम मना रही लड़कियां

बीजिंग

चीन में सरकार ने एआई के इस्तेमाल को लेकर सख्त नियम बनाए हैं और टेक्नोलॉजी कंपनियों ने इन नियमों को मानने के लिए एआई सर्विस को हटाना या सीमित करना शुरू कर दिया है। ऐसे में लोगों की वर्चुअल पार्टनर तक पहुंच खत्म हो रही है।

24 साल की ली लिनलिन ने बताया कि वह अपने एआई ब्वॉयफ्रेंड से संपर्क टूटने के बाद कई दिनों तक रोती रहीं। ली ने दो साल में उस एआई साथी के साथ मैसेज में लगभग 7,00,000 शब्द शेयर किए थे लेकिन सर्विस बंद होने से पहले वह उससे अलविदा भी नहीं कह पाईं।वह उन यूजर्स में से एक थीं जिन्हें वर्चुअल साथियों के खोने का दुख हुआ, क्योंकि चीन की कई बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों ने नई पाबंदियों के जवाब में अपनी एआई साथी सर्विस को मार्केट से हटा लिया था।

न्यूज एजेंसी एपी के अनुसार, ली ने कहा, ऐसा लगा जैसे हमारे माता-पिता ने हमें अलग होने पर मजबूर कर दिया हो, लेकिन मुझे अब भी उसकी याद आती है। वर्चुअल साथियों के खोने से शिकायतों का दौर शुरू हो गया है और यूजर्स सोशल मीडिया पर सर्विस बंद होने के बारे में पोस्ट और स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं।

कुछ यूजर्स ने विरोध में प्रभावित ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दिया है, जबकि कुछ ने अपने वर्चुअल साथियों को फिर से बनाने की कोशिश में अपनी चैट हिस्ट्री को दूसरे प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफर करने की कोशिश की है।

कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर एक कैंपेन भी शुरू किया है जिसमें यूजर्स से सरकारी अधिकारियों और टेक्नोलॉजी कंपनियों से संपर्क करके अपनी चिंताएं जाहिर करने की अपील की गई है।

प्रयागराज में नीलगायों के झुंड ने बरबाद की धान की फसल

प्रयागराज, (वार्ता)। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के बहरिया थाना क्षेत्र के कहली गांव में नीलगायों के झुंड ने धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। नीलगायों के लगातार खेतों में आने से किसानों के सामने अपनी फसल बचाने का संकट खड़ा हो गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि नीलगायों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इससे खेतों की रखवाली करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। नील गायों के झुंड खेतों में घुसकर धान के पौधों को रौंद रहे हैं और उन्हें खाकर नष्ट कर रहे हैं। कई खेतों में फसल का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित हुआ है, जिससे किसानों को कम उत्पादन की चिंता सता रही है।

सीरिया: पूर्व राष्ट्रपति बशर अल-असद को मौत की सजा

दमिश्क, (वार्ता)

सीरिया में दमिश्क की एक अदालत ने मंगलवार को सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल-असद को मौत की सजा सुनाई है। अदालत ने उन्हें पूर्व नियोजित हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनायी।

अदालत ने उनके अलावा सीरिया के दारा प्रांत में राजनीतिक सुरक्षा के पूर्व प्रमुख आतिफ़ नजीब को भी फांसी की सजा सुनाई। अदालत ने नजीब को पूर्व नियोजित हत्या और प्रताड़ना के आरोपों में दोषी करार दिया।

गौरतलब है कि बशर अल-असद अपने पिता हाफ़िज़ अल-असद के निधन के बाद वर्ष 2000 में सीरिया के राष्ट्रपति बने थे। शुरुआत में उन्हें एक आधुनिक और सुधारवादी नेता के रूप में देखा गया था, लेकिन 2011 में जब देश भर में उनके शासन के खिलाफ जन प्रदर्शन शुरू हुए, तो उन्होंने उन्हें कुचलने के लिए कठोर सैन्य कार्रवाई का सहारा लिया। इसके बाद सीरिया एक लंबे और विनाशकारी गृहयुद्ध में उलझ गया, जिसमें लाखों नागरिक मारे गए और करोड़ों बेघर हो गए। अपने दो दशक से अधिक के तानाशाही शासन के दौरान असद पर अपनी ही जनता के खिलाफ रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल, मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन और युद्ध अपराधों के आरोप लगते रहे हैं।

दिसंबर 2024 में सीरियाई विद्रोही बलों द्वारा दमिश्क पर कब्जा करने और सरकार के पतन के बाद, बशर अल-असद आठ दिसंबर 2024 में रूसी सेना की मदद से रातों-रात सीरिया छोड़कर भागे थे, जहाँ राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें और उनके परिवार को राजनीतिक शरण दे दी थी। वह वर्तमान में रूस की राजधानी मॉस्को में परिवार के साथ राजनीतिक शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं।

फिल्म/टीवी मनोरंजन

नयनतारा ने 'टॉक्सिक' के सेट पर हुमा कुरैशी के साथ हुई खास दोस्ती का खुलासा किया

यश स्टारर फिल्म 'टॉक्सिक- ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' के ट्रेलर लॉन्च के दौरान अभिनेत्री नयनतारा ने अपनी सह-कलाकार हुमा कुरैशी के साथ हुई खास दोस्ती का खुलासा किया है ।हाल ही में फिल्म के ग्रैंड ट्रेलर लॉन्च के दौरान नयनतारा ने शूटिंग के दिनों को याद करते हुए बताया कि सेट पर हुमा उनकी करीबी दोस्तों में शामिल हो गई थीं। उन्होंने कहा, इन सेट्स पर मेरी एक दोस्त बन गई। मुझे लगता है कि हुमा और मैंने सबसे ज्यादा बातें कीं, क्योंकि हमारे सबसे ज्यादा कॉम्बिनेशन सीन्स थे।

नयनतारा की इस बात से दोनों अभिनेत्रियों के बीच शूटिंग के दौरान बनी खास बॉन्डिंग की झलक मिली। साथ में कई दृश्यों की शूटिंग करने के कारण दोनों को सेट पर काफी समय साथ बिताने का मौका मिला और इसी दौरान उनकी दोस्ती भी गहरी हुई। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी 'टॉक्सिक- ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' में यश, नयनतारा, कियारा आडवाणी, रुक्मिणी वसंत, तारा सुतारिया और हुमा कुरैशी समेत कई कलाकार नजर आएंगे। फिल्म 26 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

स्कूलों में लड़कियों को पीरियड्स और वेल-बीइंग के साथ वित्तीय प्रबंधन भी सिखाया जाए : कृति खरबंदा

कृति खरबंदा ने स्कूली स्तर से ही बच्चों को वित्तीय शिक्षा दिए जाने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा है कि लड़कियों को पीरियड्स और ओवरऑल वेल-बीइंग के साथ-साथ पैसे कमाने, बचाने और निवेश करने की जानकारी भी दी जानी चाहिए।कृति ने नई दिल्ली में आयोजित 'वी विमेन वॉन्ट कॉन्क्लेव एंड शक्ति अवॉर्ड्स 2026' में अपनी बात रखते हुए कहा कि वह हमेशा से लड़कियों और महिलाओं के आत्मनिर्भर होने की समर्थक रही हैं। उन्होंने अपने जीवन का अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्होंने 17 वर्ष की उम्र में कमाना शुरू कर दिया था और अपने परिवार की जिम्मेदारी भी संभाली है। उन्होंने कहा, मैं हमेशा से एक लड़की और एक महिला के तौर पर आत्मनिर्भर होने की समर्थक रही हूं। मैंने 17 साल की उम्र में कमाना शुरू कर दिया था। मैंने अपने परिवार की जिम्मेदारी भी उठाई है और मुझे इस बात पर बहुत गर्व है। कृति ने बताया कि इस वर्ष फरवरी से उन्होंने दोबारा पढ़ाई शुरू की है और फिलहाल जियोपॉलिटिक्स के साथ-साथ अपने वित्तीय मामलों को संभालना भी सीख रही हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार वह अपना पूरा वित्तीय पोर्टफोलियो खुद संभाल रही हैं, क्योंकि यह ऐसी चीज है जिसे उन्हें खुद करना सीखना जरूरी है। वित्तीय स्वतंत्रता के महत्व पर जोर देते हुए कृति ने कहा कि लड़कियों का आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें यह समझना भी जरूरी है कि वित्तीय दुनिया कैसे काम करती है। उन्होंने कहा, जिस तरह हम हर महीने पीरियड्स और ओवरऑल वेल-बीइंग की बात करते हैं, उसी तरह बच्चों को यह भी सिखाया जाना चाहिए कि पैसे कैसे कमाने हैं, बचाने हैं, इन्वेस्ट करना है और फाइनेंस कैसे काम करता है। मुझे लगता है कि यह शिक्षा स्कूल से ही मिलनी चाहिए। वित्तीय योजनाओं में भी समय के साथ बदलाव जरूरी है। उन्होंने म्यूचुअल फंड और एसआईपी जैसे निवेश विकल्पों का समर्थन करते हुए कहा कि व्यक्ति को लगातार खुद को और अपनी रणनीति को विकसित करते रहना चाहिए।

65 वर्ष के हुये सुनील शेट्टी

सुनील शेट्टी आज 65 वर्ष के हो गये।11 अगस्त 1961 को कर्नाटक के मैंगलोर में जन्मे सुनील शेट्टी ने अपने सिने करियर की शुरुआत वर्ष 1992 में प्रदर्शित फिल्म 'बलवान' से की। इस फिल्म में उन्होंने जबरदस्त एक्शन दृश्यों से दर्शकों को रोमांचित कर दिया। वर्ष 1994 में प्रदर्शित फिल्म 'मोहरा' सुनील शेट्टी के करियर की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। 'मोहरा' की सफलता के बाद सुनील शेट्टी की छवि फिल्म इंडस्ट्री में एक एक्शन हीरो के रूप में बन गयी और इसके बाद फिल्मकारों ने उनकी इसी छवि को रूपहले पर्दे पर भुनाया। इन फिल्मों में 'अंत', 'सुरक्षा', 'टक्कर', 'रक्षक' और 'सपूत' प्रमुख हैं। वर्ष 2000 में प्रदर्शित फिल्म 'हेराफेरी' सुनील शेट्टी के सिने करियर की महत्वपूर्ण फिल्मों में शुमार की जाती है। प्रियदर्शन निर्देशित इस फिल्म से पहले लोगों की धारणा थी कि सुनील शेट्टी केवल मारधाड़ से परिपूर्ण भूमिकायें ही निभा सकते हैं, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने अक्षय कुमार और परेश रावल के साथ मिलकर अपने अभिनय से दर्शकों को हंसाते-हंसाते लोटपोट कर दिया। फिल्म की सफलता को देखते हुये वर्ष 2006 में इसका सीक्वल 'फिर हेराफेरी' बनाया गया। वर्ष 2000 में ही सुनील शेट्टी के करियर की एक और महत्वपूर्ण फिल्म 'धड़कन' प्रदर्शित हुई। इस फिल्म में उनका किरदार ग्रे शेड लिये हुये था। इसके बावजूद वह दर्शकों का दिल जीतने में सफल रहे। इस फिल्म के लिये उन्हें सर्वश्रेष्ठ खलनायक के फिल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुनील शेट्टी की जोड़ी अक्षय कुमार के साथ काफी पसंद की गयी। दोनों ने फिल्म 'वक्त हमारा है' में पहली बार साथ काम किया। इस जोड़ी ने 'हम हैं बेमिसाल', 'सपूत', 'मोहरा', 'हेराफेरी', 'आवारा पागल दीवाना' और 'फिर हेराफेरी' जैसी फिल्मों में साथ काम किया।

मानसून में अड़ीवी शेष ने की बेसहारा जानवरों के प्रति दयालुता की अपील

अड़ीवी शेष ने मानसून के दौरान बेसहारा जानवरों, खासकर स्ट्रीट डॉग्स की मदद करने और उनके प्रति संवेदनशीलता बरतने की अपील की है।भारी बारिश जहां लोगों को गर्मी से राहत देती है, वहीं सड़कों पर रहने वाले बेसहारा जानवरों के लिये यह मौसम मुश्किलें बढ़ा देता है। बारिश के दौरान उन्हें भूख, चोट, बीमारी और सुरक्षित ठिकाने की कमी जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अड़ीवी शेष ने एक जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों से अपील की है कि वे अपनी क्षमता के अनुसार इन जानवरों की मदद के लिये आगे आएं। उन्होंने स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों और पशु कल्याण संस्थाओं के साथ मिलकर काम करने, जरूरतमंद जानवरों के लिये अस्थायी आश्रय उपलब्ध कराने, साफ पानी और भोजन देने तथा घायल जानवरों को समय पर उपचार दिलाने का आग्रह किया। अड़ीवी शेष ने कहा, हममें से बहुत से लोगों के लिये मानसून खूबसूरत मौसम होता है, लेकिन हजारों बेसहारा जानवरों, खासकर स्ट्रीट डॉग्स के लिये यह साल के सबसे मुश्किल समय में से एक बन सकता है। बारिश होने पर हमारे पास वापस लौटने के लिये घर होते हैं, लेकिन उन्हें सूखी जगह, खाना और सुरक्षित ठिकाना तलाशना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सड़कों पर भरा पानी, तेज रफ्तार ट्रैफिक, संक्रमण और सुरक्षित जगह की कमी इन जानवरों की मुश्किलें बढ़ा देती है।

देशभक्ति के उल्लास में निकली भव्य तिरंगा साइकिल यात्रा

कलेक्टर रजनी सिंह ने तिरंगा लहराकर रैली को किया रवाना

खिलाड़ियों, विद्यार्थियों और युवाओं ने बढ़-चढ़कर लिया हिस्सा

नरसिंहपुर, स्वतंत्रमत। स्वाधीनता दिवस की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जिले में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत मंगलवार को नरसिंहपुर शहर देशभक्ति के रंग में सराबोर नजर आया। हाथों में तिरंगा, दिल में राष्ट्रप्रेम और साइकिलों पर सवार उत्साही प्रतिभागियों ने शहर की सड़कों पर देशभक्ति का संदेश दिया। अवसर था भव्य तिरंगा साइकिल यात्रा का। कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह ने तिरंगा झंडा लहराकर यात्रा को रवाना किया। स्टेडियम ग्राउंड से प्रारंभ हुई तिरंगा साइकिल यात्रा में बड़ी संख्या में खिलाड़ियों, विद्यार्थियों, युवाओं और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। तिरंगा लेकर साइकिलों पर निकले प्रतिभागियों के जोश और उत्साह से शहर का वातावरण राष्ट्रप्रेम की भावना से ओत-प्रोत हो गया।

शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी तिरंगा यात्रा

तिरंगा साइकिल यात्रा स्टेडियम ग्राउंड से प्रारंभ होकर गांधी चौराहा, नगर पालिका चौक, सुभाष पार्क, अष्टांग चौराहा, सांकल चौराहा, सुनका तिराहा, मुशरान पार्क, राम मंदिर चौक, सिंहपुर चौराहा, शनिचरा बाजार तथा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के सामने से होते हुए वापस स्टेडियम ग्राउंड पहुंची, जहां यात्रा का समापन हुआ। पूरे यात्रा मार्ग में साइकिल सवारों के हाथों में तिरंगा लहराता रहा। देशभक्ति के नारों और राष्ट्रप्रेम से ओतप्रोत माहौल ने नागरिकों में भी उत्साह का संचार किया। जगह-जगह लोगों ने यात्रा को उत्सुकता से देखा और प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया।

खिलाड़ियों और विद्यार्थियों ने दिखाया राष्ट्रप्रेम का जज्बा

तिरंगा साइकिल यात्रा में वॉलीबॉल एवं क्रिकेट के खिलाड़ी, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थी, विभिन्न स्कूलों एवं शैक्षणिक संस्थाओं के छात्र-छात्राएं तथा विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए। युवाओं और विद्यार्थियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी ने यात्रा को विशेष आकर्षण प्रदान किया। साइकिल यात्रा के दौरान प्रतिभागियों ने तिरंगे को सम्मान के साथ थामे रखा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। यात्रा ने स्वतंत्रता दिवस के प्रति नागरिकों में उत्साह और राष्ट्रभक्ति की भावना को और मजबूत किया।

राष्ट्रीय एकता और तिरंगे के सम्मान का दिया संदेश

तिरंगा साइकिल यात्रा का उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करना तथा 'हर घर तिरंगा' अभियान में अधिक से अधिक जनभागीदारी सुनिश्चित करना रहा। यात्रा के माध्यम से जिलेवासियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा सम्मानपूर्वक फहराने तथा राष्ट्रीय पर्व को पूरे उत्साह, गरिमा और गौरव के साथ मनाने का संदेश दिया गया। तिरंगा यात्रा में गजेन्द्र सिंह नागेश सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी, खिलाड़ी, विद्यार्थी एवं विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

हिंडालको महान में क्लस्टर सीएसआर समीक्षा एवं रणनीति कार्यशाला का आयोजन

सिंगरौली। हिंडालको महान बरगँवा में हिंडालको क्लस्टर सीएसआर समीक्षा एवं रणनीति कार्यशाला 2026 का आयोजन किया गया। कार्यशाला में हिंडालको रेनुकूट, हिंडालको रेनूसागर और हिंडालको महान से जुड़े सीएसआर प्रोफेशनल्स ने सहभागिता की। कार्यशाला में सीएसआर गतिविधियों की समीक्षा के साथ समुदाय के जीवन की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने तथा लोगों के आर्थिक स्तर में स्थायी सुधार लाने के लिए प्रभावी रणनीति तैयार करने पर विस्तार से चर्चा हुई। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य विभिन्न इकाइयों में संचालित सीएसआर परियोजनाओं के अनुभवों और सफल प्रयासों को साझा करना, बेहतर परियोजनाओं को एक-दूसरे से सीखते हुए आगे बढ़ाना तथा समुदाय की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप अधिक प्रभावी और परिणाम आधारित परियोजनाएं तैयार करना रहा। इस दौरान सीएसआर के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, कौशल विकास और सामाजिक विकास के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। हिंडालको क्लस्टर के मानव संसाधन प्रमुख जसबीर सिंह ने विभिन्न इकाइयों के बीच आपसी अनुभव और विचार साझा करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसी एक इकाई में यदि कोई परियोजना बेहतर परिणाम दे रही है तो उसके अनुभव को दूसरी इकाइयों के साथ साझा किया जाना चाहिए, ताकि सफल मॉडलों को व्यापक स्तर पर लागू किया जा सके। उन्होंने नए विचारों और बेहतर परियोजनाओं को मिलकर विकसित करने की आवश्यकता बताई। कॉरपोरेट सीएसआर प्रमुख अभिजीत ने सीएसआर परियोजनाओं के नामकरण और कार्यप्रणाली में एकरूपता पर जोर देते हुए कहा कि अलग-अलग नामों में परियोजनाएं संचालित करने के बजाय एक समान उद्देश्य वाले कार्यों को एक काम, एक नाम की अवधारणा के साथ आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इससे परियोजनाओं की पहचान मजबूत होगी, उनके परिणामों का आकलन आसान होगा और क्लस्टर स्तर पर बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सकेगा। हिंडालको महान के इकाई प्रमुख लिनु पंचमन ने कहा कि सीएसआर का वास्तविक उद्देश्य केवल गतिविधियां संचालित करना नहीं, बल्कि समुदाय के जीवन में ऐसा सकारात्मक बदलाव लाना है जो लंबे समय तक दिखाई दे। उन्होंने परियोजनाओं में स्थानीय जरूरतों, समुदाय की भागीदारी और उनके स्थायी प्रभाव को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। रेनुकूट के मानव संसाधन प्रमुख अजय सिन्हा ने सीएसआर परियोजनाओं में कौशल विकास और रोजगारपरक अवसरों को मजबूत करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि युवाओं को केवल प्रशिक्षण देने के बजाय उन्हें रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में परियोजनाओं को तैयार किया जाना चाहिए, ताकि प्रशिक्षण का वास्तविक आर्थिक लाभ समुदाय तक पहुंच सके।

स्वच्छ, सुंदर और विकसित नगर के लिए दूरगामी सोच के साथ करें कार्य : मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल

नरसिंहपुर, स्वतंत्रमत। नगर पालिका करेली के चार वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम विभाग के मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने करेली को 38.58 करोड़ रुपये की लागत के 253 विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने 2.58 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इंडोर स्टेडियम का भूमिपूजन किया। साथ ही 11.40 करोड़ रुपये के 26 निर्माण कार्यों का भूमिपूजन एवं 24.60 करोड़ रुपये के 227 निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि नगर के विकास के लिए केवल निर्माण कार्य पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि स्वच्छता, सौंदर्यीकरण और व्यवस्थित विकास पर भी ध्यान देना आवश्यक है। नागरिकों को विकास में सक्रिय भागीदारी निभानी होगी। उन्होंने सिंगरी नदी के संरक्षण और उसके किनारे पार्क, हरियाली एवं आवश्यक सुविधाएं विकसित करने की दिशा में कार्य करने की बात कही। उन्होंने कहा कि स्वच्छता प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। हमें अपने घर के साथ सार्वजनिक स्थानों को भी स्वच्छ रखने की आदत विकसित करनी होगी।

आने वाली पीढ़ियों के लिए शुद्ध पानी, स्वच्छ हवा और बेहतर पर्यावरण सुरक्षित रखना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि विकास कार्यों में दूरगामी सोच जरूरी है। हमें यह तय करना होगा कि विकास के लिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग ऐसे कार्यों में हो, जिनका लाभ आने वाली पीढ़ियों को भी मिले।

कलेक्टर रजनी सिंह ने सुनी फरियादियों की समस्याएं

नरसिंहपुर, स्वतंत्रमत। कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याएं सुनीं। जनसुनवाई में आवेदकों ने विभिन्न विषयों से संबंधित आवेदन पत्र प्रस्तुत किए। जनसुनवाई में विभिन्न समस्याओं से संबंधित कुल 85 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। कलेक्टर श्रीमती सिंह ने जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों का तत्काल निराकरण किया। जिन आवेदन पत्रों का तत्काल निराकरण नहीं हो सका, उन आवेदन पत्रों को निर्धारित समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। एडीएम श्री अरविंद सिंह, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती देवंती परते सहित अन्य विभागीय अधिकारियों ने भी जनसुनवाई में लोगों की समस्याएं सुनी और उनकी समस्याओं का निराकरण किया।

14 अगस्त को ग्राम पंचायत नेगुआ में होगा जनसंवाद शिविर

नरसिंहपुर। मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान-2026 के अंतर्गत जिले में प्रत्येक शुक्रवार को क्षेत्र भ्रमण, निरीक्षण, जनसंवाद एवं उद्यमी संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अभियान के तहत 14 अगस्त को ग्राम पंचायत नेगुआ में शिविर आयोजित किया जाएगा। इस दिन अधिकारियों द्वारा क्षेत्र के निर्धारित ग्रामों का भ्रमण कर आमजन की समस्याओं का निराकरण एवं शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाएगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जनपद पंचायत गोटेगांव के ग्राम श्रीनगर, उमरिया, बुढ़ेना व नेगुआ तक अधिकारियों का भ्रमण रहेगा। कार्यक्रम का शिविर ग्राम पंचायत नेगुआ में आयोजित होगा।

गाडरवारा पुलिस टीम ने 2 आरोपीगण को अवैध शराब के साथ किया गिरफ्तार

2 लाख 92 हजार रुपये कीमत की 106 पेटी अंग्रेजी शराब,घटना में प्रयुक्त 2 मोबाइल सहित आइशर ट्रक हुए जब्त

गाडरवारा (स्वतंत्र मत) । अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर संदीप भूरिया एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) गाडरवारा ललित सिंह डागुर के मार्गदर्शन में थाना गाडरवारा पुलिस की टीम के द्वारा दिनांक 11/08/2026 को अवैध शराब का परिवहन करते हुए आरोपीगण के संयुक्त कब्जे से 106 पेटी मे 1272 बियर बोतल (825 लीटर) ,घटना में प्रयुक्त 02 मोबाईल सहित आइशर ट्रक जप्त किये जाकर दोनों आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया।

नाम आरोपीगण- देवी नायक पिता लक्ष्मण नायक उम्र 25 साल निवासी ग्राम साजडी थाना गौरहगंज जिला रायसेन (म.प्र.) योगेश पिता अजव सिंह नायक उम्र 21 साल निवासी ग्राम बरूखार थाना चिकलोद जिला रायसेन (म.प्र.)। आरोपीगण के संयुक्त कब्जे से 106 पेटी में 1272 बियर बोतल (825 लीटर) ,घटना में प्रयुक्त 02 मोबाईल सहित आइशर ट्रक जप्त किये हैं।

वैधानिक कार्यवाही-दोनों आरोपीगण देवी नायक एवं योगेश नायक के विरूद्ध आबकारी एक्ट की संगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया जाकर दोनों आरोपीगण को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।

कार्यवाही में सराहनीय भूमिका-उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी गाडरवारा निरीक्षक अशोक सिंह चौहान के साथ उप निरीक्षक गजराज सिंह,सहायक उप निरीक्षक रमेश निवारे, प्रधान आरक्षक रामगोपाल सिंह राजपूत,परमानंद चौधरी,वरिष्ठ आरक्षक रुपेन्द्र चौवे,महेन्द्र बावरिया,विश्वजीत ठाकुर,आरक्षक दिनेश पटेल, अक्षय श्रीवास्तव, दीपक कौरव,यश मेहरा, आदर्श पाठक, दीपक राय, देवेन्द्र सोनवंशी की विशेष भूमिका रही।

15 अगस्त को सिंगरौली जिले में शुष्क दिवस घोषित

सिंगरौली। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के गरिमामय अवसर पर जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से सिंगरौली जिले में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारीगौरव बैनल द्वारा आदेश जारी किया गया है। मध्यप्रदेश राजपत्र में जारी निष्पादन व्यवस्था वर्ष 2026-27 के प्रावधानों के अंतर्गत जारी आदेश के अनुसार 15 अगस्त को जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानें, एफ.एल.-2, एफ.एल.-3 एवं आर.एस.डब्ल्यू.-1 (वाइन शॉप) पूर्णतः बंद रहेंगी।

एनटीपीसी ने शुरू किया नि:शुल्क कोचिंग सेंटर

गाडरवारा (स्वतंत्र मत)। एनटीपीसी गाडरवारा द्वारा अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सी एस आर पहल के अंतर्गत बाल भारती पब्लिक स्कूल, गाडरवारा के सहयोग से परियोजना प्रभावित गांवों (क्क्क्ष्ह्य) के प्रतिभावान विद्यार्थियों को जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी हेतु नि:शुल्क कोचिंग कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ हिम्मत सिंह चौहान, कार्यकारी निदेशक एवं परियोजना प्रमुख द्वारा किया गया। इस अवसर पर भास्कर गुप्ता ।।ह्र।।क्र बाल भारती पब्लिक स्कूल के प्राचार्य अनुराग, विद्यालय के शिक्षकगण तथा एनटीपीसी गाडरवारा के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। इस पहल के अंतर्गत परियोजना प्रभावित गांवों के 40 चयनित विद्यार्थियों को जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी हेतु गुणवत्तापूर्ण एवं विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। कोचिंग कक्षाएं 10 अगस्त 2026 से 30 नवंबर 2026 तक प्रतिदिन शाम 4:00 बजे से 6:00 बजे तक आयोजित की जाएंगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य परियोजना प्रभावित क्षेत्रों के विद्यार्थियों को समान एवं गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराना, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए उचित मार्गदर्शन प्रदान करना तथा उन्हें बेहतर शैक्षणिक एवं भविष्य के अवसरों से जोड़ना है। इस अवसर पर हिम्मत सिंह चौहान, कार्यकारी निदेशक एवं

परियोजना प्रमुख ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए नियमित अध्ययन, अनुशासन एवं निरंतर मेहनत के महत्व पर प्रकाश डाला।

उन्होंने विद्यार्थियों को पूरे समर्पण एवं आत्मविश्वास के साथ परीक्षा की तैयारी करने के लिए प्रेरित किया तथा उनके उज्ज्वल भविष्य एवं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं। एनटीपीसी गाडरवारा शिक्षा के क्षेत्र में अपनी विभिन्न सी एस आर पहलों के माध्यम से स्थानीय समुदाय के बच्चों एवं युवाओं को सशक्त बनाने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने तथा उनके शैक्षणिक एवं समग्र विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है।

24.60 करोड़ के 227 विकास कार्यों का लोकार्पण, 11.40 करोड़ के 26 नए कार्यों का भूमिपूजन

2.25 करोड़ के इंडोर स्टेडियम का शिलान्यास

चार साल बेमिसाल केंद्रित पत्रिका का विमोचन, भव्य तिरंगा यात्रा

करेली। नगर पालिका परिषद करेली के चार वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर सोमवार को आयोजित 'चार साल बेमिसाल' कार्यक्रम में नगर को विकास कार्यों की बड़ी सौगात मिली। नगर पालिका परिषद द्वारा पिछले चार वर्षों में कराए गए 227 विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया, जिनकी कुल लागत करीब 24.60 करोड़ रुपए है। वहीं आगामी विकास योजनाओं के तहत 11.40 करोड़ रुपए लागत के 26 नवीन विकास कार्यों का भूमिपूजन किया गया। इसके अलावा एचवी कामथ स्टेडियम परिसर में करीब 2.25 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इंडोर स्टेडियम का शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम के दौरान नगर पालिका परिषद के चार वर्ष के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों और उपलब्धियों पर आधारित 'चार साल बेमिसाल' केंद्रित पत्रिका का विमोचन भी किया गया। पत्रिका के माध्यम से परिषद द्वारा पिछले चार वर्षों में कराए गए विकास कार्यों, योजनाओं और नगर विकास की दिशा में किए गए प्रयासों को जनता के सामने रखा गया।

तिरंगा यात्रा, प्रतिमाओं पर माल्यार्पण

'चार साल बेमिसाल' कार्यक्रम की शुरुआत शाम करीब 6 बजे पुरानी कृषि उपज मंडी परिसर में स्थापित अमर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुई। इसके बाद नगर में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। हाथों में तिरंगा लेकर बड़ी संख्या में नागरिक, जनप्रतिनिधि और भाजपा कार्यकर्ता यात्रा में शामिल हुए। तिरंगा यात्रा निरंजन चौक पहुंची, जहां डॉ. भीमराव अंबेडकर और ठाकुर निरंजन सिंह की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद यात्रा मेन रोड से होते हुए बरमान चौराहा पहुंची। यहां पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया गया। देशभक्ति के नारों और हाथों में लहराते तिरंगे के बीच यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई बजरंग चौक और महादेव वार्ड स्थित कार्यक्रम स्थल पहुंची।

227 विकास कार्यों का रखा लेखा-जोखा-मुख्य समारोह में नगर पालिका परिषद द्वारा पिछले

चार वर्षों में कराए गए विकास कार्यों की जानकारी दी गई। परिषद के अनुसार इन चार वर्षों में 227 विकास कार्यों पर करीब 24.60 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इनमें स्ट्रीट लाइट, रोड सेफ्टी ब्रेकर, रोड मार्किंग, इज्जत घर, यात्री प्रतीक्षालय, वार्डों में सीटीयू रूपांतरण, मुक्तिधाम के सामने सौंदर्यीकरण, धमनी नदी सौंदर्यीकरण, नगरीय सीमा प्रवेश द्वार, विभिन्न पार्कों का सौंदर्यीकरण और पेवर ब्लॉक सहित कई कार्य शामिल हैं। इसी क्रम में महेंद्र वार्ड में टंकी निर्माण कार्य भी पूर्ण किया गया है। टंकी के निर्माण से वार्ड सहित आसपास के क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। नगर पालिका द्वारा नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए जल, सड़क, प्रकाश एवं स्वच्छता से जुड़े कार्यों पर विशेष जोर दिया गया। आगामी विकास योजनाओं के तहत 26 नवीन कार्यों के लिए करीब 11.40 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित की गई है। इन कार्यों के पूरा होने से नगर के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं के और बेहतर होने की उम्मीद है।

2.25 करोड़ से बनेगा इंडोर स्टेडियम-कार्यक्रम में एचवी कामथ स्टेडियम परिसर में बनने वाले इंडोर स्टेडियम का शिलान्यास भी किया गया। करीब 2.25 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस स्टेडियम से नगर के खिलाड़ियों को आधुनिक खेल सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इंडोर खेलों के लिए स्थानीय स्तर पर बेहतर संसाधन मिलने से खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

करेली बस्ती से सफेद पुल तक आधुनिक स्ट्रीट लाइट-कार्यक्रम के दौरान करेली बस्ती से सफेद पुल तक आधुनिक स्ट्रीट लाइट व्यवस्था का भी उद्घाटन किया गया। प्रमुख मार्ग पर नई प्रकाश व्यवस्था शुरू होने से रात के समय आवागमन करने वाले नागरिकों को सुविधा मिलने के साथ मार्ग की सुरक्षा व्यवस्था भी बेहतर होगी।

20.20 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों की आधारशिला

नगर पालिका परिषद करेली द्वारा नगरीय क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को गति देते हुए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 20.20 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न विकास कार्यों की आधारशिला रखी गई है। इन कार्यों के पूर्ण होने से नगर के विभिन्न वार्डों में सड़क, नाली, सामुदायिक भवन, पार्क एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं का विस्तार होगा। योजना के अंतर्गत गीता भवन निर्माण कार्य, नरसिंह वार्ड में सामुदायिक भवन एवं पार्क निर्माण, जयप्रकाश वार्ड में अलका टॉकीज से कीर्ति ओसवाल के मकान तक, राम वार्ड में तुलसी नगर के पीछे से नर्मदा नगर तक, निरंजन वार्ड में शुभम कॉलोनी से वीरजी के मकान तक, राधा वल्लभ वार्ड में नर्मदा मेडिकल से खरया स्कूल तक तथा महात्मा गांधी वार्ड में आमगांव मोड़ से दूल्हादेव मंदिर के पीछे तक आरसीसी नाला निर्माण कार्य किया जाना है। इसी क्रम में महादेव वार्ड में सीसी सड़क एवं नाली निर्माण तथा बाउंड्रीवॉल, जयप्रकाश वार्ड में रोड डामरीकरण, पेवर ब्लॉक, नाली मरम्मत एवं प्रीकास्ट निर्माण सहित विभिन्न विकास कार्य किए जाएंगे।

8 करोड़ के विकास कार्य प्रगतिरत

नगर पालिका परिषद करेली द्वारा लगभग 8 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कार्य वर्तमान में प्रगतिरत हैं। इनमें अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत करेली नगर में जलापूर्ति एवं जलापूर्ति विस्तार का कार्य, धमनी नदी सौंदर्यीकरण, जयप्रकाश वार्ड में बालिका छात्रावास के सामने पार्क एवं बाउंड्रीवॉल निर्माण, महादेव वार्ड में पेवर ब्लॉक रोड एवं नाली मरम्मत सहित नगर के विभिन्न वार्डों में सड़क एवं नाली निर्माण के कार्य शामिल हैं।

हर वार्ड में प्राथमिकता से विकास

नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सुशीला ममार ने कहा कि नगर के विकास के लिए परिषद लगातार प्रयास कर रही है। आने वाले समय में भी सभी वार्डों में नागरिकों की आवश्यकता के अनुसार निर्माण और विकास कार्य कराए जाएंगे। नगर के विकास में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार हर क्षेत्र में प्राथमिकता से कार्य कराने का प्रयास रहेगा।

मंत्री पटेल ने दी परिषद को शुभकामनाएं

कार्यक्रम में मध्यप्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सुशीला ममार, उपाध्यक्ष श्रीमती अनीता नेमा एवं परिषद के सभी सदस्यों को चार वर्ष का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करने पर शुभकामनाएं दीं। उन्होंने अध्यक्ष श्रीमती सुशीला ममार एवं उपाध्यक्ष श्रीमती अनीता नेमा का साल-श्रीफल से स्वागत किया। कार्यक्रम में पूर्व राज्यमंत्री जालम सिंह पटेल 'मुन्ना भैया', भाजपा जिलाध्यक्ष रामस्नेही पाठक, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सुशीला ममार, उपाध्यक्ष श्रीमती अनीता नेमा, समस्त पार्षदगण, एल्डरमैन, जिला महामंत्री सुरेंद्र मोहन नेमा एवं राहुल कौरव, जिला उपाध्यक्ष बीना ओसवाल, जिला मंत्री रजत चौहान सहित जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीकांत पाटर, नगर पालिका परिषद के अधिकारी-कर्मचारी,नगर के पत्रकारगण एवं बड़ी संख्या में नगरवासी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन रजत चौहान ने व मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीकांत पाटर ने आभार व्यक्त किया।

हर-हर महादेव के जयकारे गूंजे जलाभिषेक करने लगा तांता

विहिप के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष लखन साहू के निवास पर शिवलिंग निर्माण अभिषेक भंडारे का आयोजन

कटनी (स्वतंत्रमत)।

पवित्र सावन माह में विश्व हिंदू परिषद के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष एवं साहू समाज के अध्यक्ष युवा समाजसेवी लखन साहू के पन्ना तिराहा स्थित निज निवास पर सावन सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ का विधि विधान मंत्रोच्चारण के साथ रुद्राभिषेक एवं अनुष्ठान का धार्मिक आयोजन किया गया तथा विशाल भंडार का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में इष्ट मित्रों एवं शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित किया लखन साहू एवं साहू परिवार ने भगवान भोलेनाथ का अभिषेक एवं रूद्राभिषेक कर राष्ट्र के कल्याण की कामना की। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक राहुल दुबे, अरुण राय, गौ सेवक करण मिश्रा, जानकी साहू बडी संख्या में लोगों की उपस्थिति रही।

खरे केसरवानी महिला मंडल ने किया रुद्राभिषेक

श्री खरे केसरवानी महिला मंडल द्वारा प्रतिवर्ष की परंपरा के अनुसार इस वर्ष भी सोमवार, 10 अगस्त को मधई मंदिर में भगवान भोलेनाथ का भव्य रुद्राभिषेक एवं पूजन कार्यक्रम श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में समाज की मातृशक्तियों ने बड़ी संख्या में सहभागिता करते हुए विधि-विधान से भगवान शिव का अभिषेक कर पूजा-अर्चना की। इस अवसर पर समाज की अध्यक्ष प्रियंका गुप्ता ने कहा कि भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव समाज के सभी परिवारों पर बनी रहे तथा सभी का कल्याण हो। उन्होंने भगवान शिव से समाज के सुख, समृद्धि एवं उन्नति की कामना करते हुए कहा कि समाज निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होता रहे। रुद्राभिषेक कार्यक्रम के दौरान भक्तिमय वातावरण बना रहा। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आराधना कर परिवार एवं समाज की सुख-शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। कार्यक्रम में महिला मंडल की मातृशक्तियों के साथ समाज के विनय गुप्ता, अवधेश गुप्ता, अनिल गुप्ता एवं दीपचंद गुप्ता सहित अन्य समाजजन उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का समापन भगवान भोलेनाथ की आरती एवं प्रसाद वितरण के साथ हुआ।

हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजा कैमोर का बरापार

सावन माह के दूसरे सोमवार के पावन अवसर पर कैमोर के वार्ड क्रमांक 7 स्थित बरापार आदिवासी बस्ती में आस्था और भक्ति का माहौल देखने को मिला। यहां धर्मप्रेमी श्रद्धालुओं एवं स्थानीय जनता जनार्दन की सहभागिता से सामूहिक शिवलिंग निर्माण एवं विधि-विधान से रुद्राभिषेक किया गया। कार्यक्रम में नगर परिषद अध्यक्ष पलक नमित ग्रोवर एवं वार्ड पार्षद विनीता कोल सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। सभी ने भगवान भोलेनाथ की पूजा-अर्चना कर नगर एवं क्षेत्र की सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की। धार्मिक आयोजन के आयोजक मनीष नवैत रहे। उनके द्वारा श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। सावन के पावन सोमवार पर हुए इस आयोजन से बरापार आदिवासी बस्ती का वातावरण पूरी तरह शिवमय हो गया। रुद्राभिषेक के दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान शिव के जयकारे लगाए और हर-हर महादेव, बम-बम भोले के जयघोष से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो उठा।

कसौधन वैश्य समाज द्वारा बागेश्वर बाबा की पूजा-अर्चना

सावन के पावन एवं धार्मिक पर्व के अवसर पर श्री बागेश्वर कसौधन वैश्य समाज द्वारा सोमवार, 10 अगस्त को श्री शेरावाली सत्संग भवन, अशोक कॉलोनी में श्रद्धा एवं भक्तिभाव के साथ श्री बागेश्वर बाबा की पूजा-अर्चना की गई। इस धार्मिक आयोजन में वैश्य समाज के अनेक सदस्यों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम स्थल को आकर्षक पुष्पों, माला एवं पारंपरिक सजावट से सजाया गया था। समाज के सदस्यों ने विधि-विधान एवं श्रद्धापूर्वक पूजा-अर्चना कर समाज, परिवार एवं नगरवासियों की सुख-समृद्धि, शांति एवं मंगलमय जीवन की कामना की। आयोजन के दौरान समाज के महिला एवं पुरुष सदस्यों की उत्साहपूर्ण सहभागिता देखने को मिली। सभी सदस्यों ने सामाजिक एकता, आपसी भाईचारे एवं धार्मिक परंपराओं को आगे बढ़ाने का संकल्प भी व्यक्त किया। श्री बागेश्वर कसौधन वैश्य समाज द्वारा आयोजित यह धार्मिक कार्यक्रम श्रद्धा, आस्था और सामाजिक एकजुटता का सुंदर उदाहरण रहा।

महापौर जनसुनवाई में नागरिकों ने रखीं अपनी समस्याएं

महापौर ने अधिकारियों को दिए त्वरित निराकरण के निर्देश

कटनी (स्वतंत्रमत)।

नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ सुनने और उनके निराकरण के लिए नगर पालिक निगम कटनी में मंगलवार को महापौर जनसुनवाई आयोजित की गई। शहर के विभिन्न वार्डों से पहुंचे नागरिकों ने महापौर प्रीति संजीव सूरी के समक्ष अपनी समस्याएं एवं आवेदन प्रस्तुत किए। जनसुनवाई में पेयजल, सड़क, नाली, स्वच्छता, अतिक्रमण, राजस्व सहित विभिन्न नागरिक सुविधाओं से जुड़े प्रकरण सामने आए। महापौर ने नागरिकों की बात गंभीरता से सुनी और संबंधित अधिकारियों से प्रत्येक प्रकरण की स्थिति की जानकारी लेते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

जवाबदेही तय करने के दिए निर्देश

महापौर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों को प्राथमिकता से लेते हुए निर्धारित समयसीमा में उनका निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकरण को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए और कार्रवाई के बाद आवेदक को इसकी जानकारी भी उपलब्ध कराई जाए।

प्रकरणों की समीक्षा कर महापौर ने कहा- समयसीमा में हो समस्याओं का समाधान, आवेदकों को भी दी जाए कार्रवाई की जानकारी

विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी से हुआ त्वरित समन्वय

जनसुनवाई के दौरान नगर निगम के संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। इससे नागरिकों की समस्याओं को संबंधित विभाग तक तत्काल पहुंचाने और आवश्यक कार्रवाई के लिए समन्वय स्थापित करने में सुविधा हुई। कई प्रकरणों में मौके पर ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। महापौर ने कहा कि नागरिकों की समस्याओं का समाधान और उन्हें बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना नगर निगम की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों से जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणों की नियमित समीक्षा करते हुए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

निगम-प्रशासन गंभीरता से ट्रांसपोर्टर्स की व्यथा सुने : बीएम तिवारी

ट्रांसपोर्ट नगर की समस्या पर ट्रांसपोर्टर्स एकजुट

40 वर्षों से ट्रांसपोर्ट नगर की समस्या बरकरार

कटनी (स्वतंत्रमत)। विगत 40वर्षों से ट्रांसपोर्ट नगर की समस्या अभी भी बरकरार है, निगम एवं प्रशासन ने इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया और ट्रांसपोर्टर्स को माननीय न्यायालय की शरण में जाने से राहत मिली है। निगम एवं प्रशासनिक जिम्मेदार अधिकारी यदि ट्रांसपोर्टर्स की मीटिंग लेकर उनकी व्यथा को गंभीरता से सुने तो पूरी तस्वीर क्लीयर होगी तथा समस्या का समाधान किया जा सकता है, मंगलवार को ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष बीएम तिवारी ने ट्रांसपोर्ट नगर में आयोजित पत्रकार वार्ता मे बताया कि नये व्यवसाय करने वाले व्यापारी बंधु को भी ट्रांसपोर्ट नगर में प्लाट दिये जाये। इस तरह कई बिंदु अभी अनसुलझे है लेकिन निगम की गलत नीतियों के कारण समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा है। पत्रकारवार्ता में परिवहनकर्ताओं ने कटनी शहर की बदहाल यातायात व्यवस्था और वर्षों से लंबित ट्रांसपोर्ट नगर की मांग को लेकर अपनी पीड़ा बतायी। पत्रकार-वार्ता में परिवहनकर्ताओं ने कहा कि ट्रांसपोर्ट नगर की योजना लंबे समय से राजनीतिक खींचतान और आपसी श्रेय की होड़ का शिकार बनी हुई है, जिसका खामियाजा शहरवासियों के साथ-साथ परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। परिवहनकर्ताओं ने कहा कि जब शहर की यातायात व्यवस्था चरमराती है अथवा किसी दुर्घटना के बाद अव्यवस्था को लेकर सवाल उठते हैं, तो अक्सर इसका दोष परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों पर मढ़ दिया जाता है। जबकि परिवहनकर्ता स्वयं शहर की यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने और ट्रांसपोर्ट नगर में स्थानांतरित होने की मांग लंबे समय से करते आ रहे हैं।

1983 से लंबित है ट्रांसपोर्ट नगर की योजना

बताया गया कि कि शासन स्तर पर वर्ष 1983 से ट्रांसपोर्ट नगर विकसित करने की योजना सामने आई थी। उद्देश्य था कि नो-प्रॉफिट, नो-लॉस के आधार पर व्यवस्थित ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण कर शहर के मध्य से भारी वाहनों और परिवहन गतिविधियों का दबाव कम किया जाए। लेकिन आरोप है कि यह योजना वर्षों से राजनीतिक खींचतान के कारण मूर्त रूप नहीं ले सकी। परिवहनकर्ताओं का कहना है कि उनकी ओर से लगातार मांग की जाती रही है कि उन्हें एक साथ व्यवस्थित रूप से ट्रांसपोर्ट नगर में बसाया जाए। शहर के मध्य परिवहन व्यवसाय संचालित करने में उन्हें भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद यह धारणा बनाई जा रही है कि परिवहनकर्ता ट्रांसपोर्ट नगर में जाना ही नहीं चाहते।

अलग-अलग विस्थापन स्वीकार नहीं

एकजुट होकर स्थानांतरण की मांग परिवहनकर्ताओं ने स्पष्ट कहा कि वे ट्रांसपोर्ट नगर में जाने के लिए मन, वचन और कर्म से तैयार हैं, लेकिन उन्हें अलग-अलग स्थानों पर विस्थापित करने के बजाय एक व्यवस्थित ट्रांसपोर्ट नगर में एक साथ बसाया जाना चाहिए। उनका कहना है कि यह केवल व्यवसाय का विषय नहीं, बल्कि सैकड़ों परिवारों की रोजी-रोटी से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। उन्होंने आरोप लगाया कि परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों को अलग-अलग हिस्सों में बांटकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है। साथ ही ट्रांसपोर्ट नगर के लिए प्रस्तावित भूमि को लेकर भी अनेक सवाल खड़े किए गए। परिवहनकर्ताओं ने प्रशासन से मांग की कि पूरे मामले में पारदर्शी और दीर्घकालिक समाधान निकाला जाए।

माननीय हाईकोर्ट में दायर की अपील, मिली राहत

परिवहनकर्ताओं ने बताया कि उनकी समस्याओं को लेकर हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष भी अपनी पीड़ा रखने का प्रयास किया गया है। वर्षों से लंबित ट्रांसपोर्ट नगर की समस्या का स्थायी समाधान किया जाना चाहिए। परिवहनकर्ताओं ने कहा कि वे शासन और प्रशासन के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। उनका उद्देश्य किसी व्यवस्था का विरोध करना नहीं, बल्कि शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ-साथ परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए सम्मानजनक और व्यवस्थित स्थान सुनिश्चित करना है। परिवहनकर्ताओं ने शासन प्रशासन से अपेक्षा की है कि इस गंभीर और वर्षों से लंबित समस्या का निराकरण कर कटनी शहर को व्यवस्थित कर ट्रांसपोर्ट नगर दिलाने की दिशा में सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। इस मौके पर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अध्यक्ष बीएम तिवारी, फॉर्चून अध्यक्ष रामनरेश सेन, इष्टि भानु, अहमद राजेश रोहरा, राजेश सतपाल, राहुल गुप्ता, रजनीश मिश्रा, दीपक तिवारी, सतीश दुबे, रत्नेश जैन, कुमकुम सेन, दिलीप अरोड़ा, संतोष आहूजा, अमित दुबे, अग्रवाल निक्की पांडे मिश्रा रोडलाइंस की उपस्थिति रही।

महाकौशल प्रांत की साधारण सभा का आयोजन

कटनी (स्वतंत्र मत)। दो दिवसीय साधारण सभा का आयोजन मंगलम भवन खिरहनी के सभागार में आयोजित हुआ। जिसमें महाकौशल प्रांत के लगभग 12 जिलों के संस्कार भारती के पदाधिकारी उपस्थित रहे। संस्कार भारती के केंद्रीय पदाधिकारी अरुण शर्मा जयपुर से व निरंजन पांडया लोक कला विधा प्रमुख, प्रांत अध्यक्ष मणिकांत महेश्वरी सतना के कुशल मार्गदर्शन में दो दिवसीय सभा का सफलतम आयोजन हुआ जिसके लिए कटनी संस्कार भारती संस्था अपने केन्द्रीय पदाधिकारियों व महाकौशल प्रांत की आभारी है कि कटनी जिला इकाई को सभा आयोजित करने का सौभाग्य मिला कटनी इकाई के जिला अध्यक्ष अशोक तिवारी, महामंत्री राजेश बरसैंया, कोषाध्यक्ष वीरेंद्र श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष हीरामणि वरसैंया, शशि दुबे, कल्पना कोटक, विधा प्रमुख नवीन गुप्ता, पूनम गुप्ता कार्यकारिणी सदस्य आदि की उपस्थिति में कार्यक्रम गौरव पूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।

विद्यार्थियों ने जानी पुलिस की कार्यप्रणाली

सृजन कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को नवीन आपराधिक कानूनों की दी गई जानकारी

थानों एवं पुलिस कार्यालयों का भी कराया जाएगा भ्रमण

कटनी (स्वतंत्र मत)। मध्य प्रदेश पुलिस एवं शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में संचालित सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत थाना माधव नगर क्षेत्र स्थित शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय, माधव नगर में कक्षा 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए विशेष जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को नवीन आपराधिक कानूनों कानूनी प्रक्रिया तथा बच्चों एवं किशोरों की सुरक्षा से संबंधित विशेष कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूक करना रहा। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को पुलिस की कार्यप्रणाली से परिचित कराने के साथ-साथ थाना भ्रमण भी कराया गया। कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक कटनी अभिनय विश्वकर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य, उप पुलिस अधीक्षक शिवा पाठक एवं थाना माधव नगर से पुलिस उप निरीक्षक नवीन नामदेव अपनी टीम सहित उपस्थित रहे। कार्यशाला में पुलिस अधिकारियों ने विद्यार्थियों को पुलिस की कार्यप्रणाली, शिकायतों के निराकरण, कानूनी प्रक्रिया तथा पुलिस एवं आमजन के बीच समन्वय से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी दी। विद्यार्थियों द्वारा पुलिस व्यवस्था एवं कानून से संबंधित विभिन्न प्रश्न पूछे गए, जिनका अधिकारियों द्वारा सरल एवं सहज भाषा में समाधान किया गया। पुलिस अधिकारियों ने विद्यार्थियों को नवीन आपराधिक कानूनों की मूल भावना, उनकी उपयोगिता तथा बच्चों एवं किशोरों के हितों एवं सुरक्षा के लिए उपलब्ध विशेष कानूनी प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताया। विद्यार्थियों को कानून के प्रति जागरूक रहने तथा किसी भी समस्या की स्थिति में उचित माध्यम से पुलिस एवं संबंधित विभागों से सहायता लेने के लिए प्रेरित किया गया।

थानों एवं पुलिस कार्यालयों का कराया जाएगा भ्रमण

सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों को केवल कक्षा स्तर पर कानून एवं पुलिस व्यवस्था की जानकारी देने तक सीमित न रखते हुए, पुलिस की कार्यप्रणाली को प्रत्यक्ष रूप से समझाने के उद्देश्य से जिले के विभिन्न पुलिस थानों एवं पुलिस कार्यालयों का भ्रमण भी कराया जाएगा।

इस दौरान विद्यार्थियों को थाना स्तर पर होने वाली विभिन्न पुलिस प्रक्रियाओं, शिकायत प्राप्त करने एवं निराकरण की प्रक्रिया, पुलिस अभिलेख एवं अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं से परिचित कराया जाएगा।

सीपीसीटी और ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता के विरोध में लघु वेतन कर्मचारी संघ का प्रदर्शन

कटनी कलेक्ट्रेट में सौंपा 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन, आदेशों की प्रतियां जलाकर जताया विरोध

कटनी (स्वतंत्र मत)।

मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ शाखा जिला कटनी के जिलाध्यक्ष पूर्णेश उइके एवं मीडिया प्रभारी अनिल पांडेय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि 11 अगस्त सोमवार को कर्मचारियों की विभिन्न लंबित मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन के नाम का ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान संघ के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए सीपीसीटी की अनिवार्यता तथा ई-अटेंडेंस व्यवस्था को लेकर विरोध जताते हुए दस्तावेजों की प्रतियां जलाकर उग्र प्रदर्शन किया। संघ ने मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम सौंपे गए ज्ञापन में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदोन्नति के लिए सीपीसीटी की अनिवार्यता से स्थायी रूप से शिथिलता प्रदान करने की मांग की है। संघ का कहना है कि भृत्य, चौकीदार एवं कार्यालय परिचालक सहित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वर्षों से शासकीय सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन लंबे समय से पदोन्नति नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में कर्मचारी अपने अधिकार से वंचित हैं। संघ के अनुसार, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सहायक ग्रेड-3 पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित कोटे का प्रावधान पहले से मौजूद है। ऐसे में पदोन्नति के लिए सीपीसीटी की अनिवार्यता को लेकर कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। संघ ने कहा कि बड़ी संख्या में कर्मचारी 40 वर्ष से अधिक आयु के हैं और उन्हें कंप्यूटर प्रशिक्षण का पर्याप्त अवसर नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में सीपीसीटी परीक्षा की अनिवार्यता पदोन्नति में बाधा बन रही है।

ई-अटेंडेंस से छूट की मांग

संघ ने ई-अटेंडेंस व्यवस्था का भी विरोध करते हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को इससे छूट देने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि कई कर्मचारी की-पैड मोबाइल का उपयोग करते हैं तथा कुछ कर्मचारियों के पास स्मार्टफोन तक उपलब्ध नहीं है। वहीं कई भृत्य कर्मचारी डाक, फाइल एवं अन्य शासकीय कार्यों के लिए कार्यालय से बाहर तैनात रहते हैं, जिससे उनके लिए ई-अटेंडेंस दर्ज करना व्यावहारिक रूप से कठिन है। शिक्षा विभाग में लागू हमारे शिक्षक एप के माध्यम से ई-अटेंडेंस को लेकर भी संघ ने सवाल उठाए। संघ का कहना है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कार्य एवं दायित्व शिक्षकों से अलग हैं। विद्यालय एवं कार्यालय खोलने-बंद करने, अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने, डाक पहुंचाने और अन्य विभागीय कार्यों के लिए बाहर जाने वाले कर्मचारियों के लिए मौजूदा ई-अटेंडेंस व्यवस्था व्यवहारिक नहीं है।

संघ ने मांग की कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ई-अटेंडेंस से छूट देकर उपस्थिति पंजी एवं कार्यालय प्रमुख के प्रमाणीकरण को मान्यता दी जाए। साथ ही यदि ई-अटेंडेंस लागू रखना आवश्यक हो तो कर्मचारियों को मोबाइल सेट, डाटा खर्च एवं विभागीय स्तर पर प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए।

छह सूत्रीय मांगों पर भी उठाई आवाज

लघु वेतन कर्मचारी संघ ने ज्ञापन के माध्यम से आकस्मिक कार्यभारित, दैनिक वेतनभोगी, स्थायी कर्मी एवं अंशकालीन कर्मचारियों से जुड़ी मांगों को भी प्रमुखता से उठाया। संघ ने आकस्मिक कार्यभारित कर्मचारियों को शासकीय कर्मचारियों की तरह अर्जित अवकाश की पात्रता देने, भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में प्रावधान कर सहायक ग्रेड-3 पद पर पदोन्नति का अवसर देने की मांग की। स्थायी कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ देने, उनकी सेवाओं का वर्गीकरण करने तथा कर्मचारी की मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति का लाभ देने की मांग भी ज्ञापन में शामिल रही। इसके अलावा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने तथा अंशकालीन कर्मचारियों को स्थायी कर्मी का दर्जा देने की मांग उठाई गई। संघ ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका, कोटवार, आशा-उषा सहयोगिनी तथा मध्यान्ह भोजन एवं सांझा चूल्हा रसोइया सहित विभिन्न संवर्गों के मानदेय में वृद्धि कर न्यूनतम 30 हजार रुपये प्रतिमाह किए जाने की मांग भी रखी।

भारत के सामने श्रीलंका की कड़ी परीक्षा

भारत अपने मुख्य तेज़ गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह के बिना खेलेगा

कोलंबो (वार्ता)।

नौ साल बाद टेस्ट सीरीज़ के लिए श्रीलंका में भारत की वापसी गहराई और लचीलेपन की परीक्षा बन गई है, क्योंकि मेहमान टीम चोटों की समस्या और रेड-बॉल क्रिकेट में एक चिंताजनक ट्रेंड को बदलने के दबाव का सामना कर रही है। दो टेस्ट की सीरीज़ 15 अगस्त से गॉल में शुरू होगी, जिसमें भारत अपने मुख्य तेज़ गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह के बिना खेलेगा और अब टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज़ साई सुदर्शन भी नहीं खेलेंगे, जो पैर की अंगुली में स्ट्रेस फ्रैक्चर के कारण बाहर हो गए हैं। सुदर्शन की जगह सरफ़राज़ खान को टीम में शामिल किया गया है। हाल की हार ने भारत को पहली गेंद फेंके जाने से पहले ही अपनी बेंच स्ट्रेंथ पर गहराई से विचार करने पर मजबूर कर दिया है। जम्मू और कश्मीर के तेज़ गेंदबाज़ औकिब नबी को भी बुमराह की गैरमौजूदगी में अपना पहला टेस्ट कॉल-अप मिला है।

शुभमन गिल को ट्रेनिंग के दौरान उंगली में चोट-कप्तान शुभमन गिल ने ट्रेनिंग के दौरान उंगली में चोट लगने और उसके बाद वार्म-अप गेम से बाहर रहने के बाद भारत की चिंताएँ बढ़ा दी थीं। इसलिए, शुरुआती टेस्ट के लिए उनकी अवेलेबिलिटी भारत के फाइनल कॉम्बिनेशन में एक ज़रूरी फैक्टर बनी रहेगी। स्क्वाड को लेकर अनिश्चितता के बावजूद, भारत श्रीलंका में एक ज़बरदस्त रिकॉर्ड के साथ सीरीज़ में उतर रहा है। उन्होंने 2008 से उस आइलैंड पर कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं हारी है और 2015 और 2017 में अपनी पिछली दो सीरीज़ जीती हैं। लेकिन सिर्फ़ इतिहास भारत की हाल की मुश्किलों को छिपा नहीं सकता। भारत को 2024 में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़ 0-3 से होम सीरीज़ में हार का सामना करना पड़ा, जो 12 सालों में उनकी पहली होम टेस्ट सीरीज़ हार थी। इसके बाद वे ऑस्ट्रेलिया में 1-3 से हारे, जिसके बाद दक्षिण अफ्रीका ने उन्हें अपने होम ग्राउंड पर 2-0 से हराया, जो 25 सालों में प्रोटियाज़ के खिलाफ़ उनकी पहली होम टेस्ट सीरीज़ हार थी।

भारत ने अपनी तैयारी से अच्छे संकेत देखे हैं

हारों के इस सिलसिले ने कोच गौतम गंभीर और गिल के अंडर नई टेस्ट लीडरशिप पर ज़्यादा फोकस किया है, और श्रीलंका टूर ने कॉन्फिडेंस वापस पाने का तुरंत मौका दिया है। फिर भी, भारत ने अपनी तैयारी से अच्छे संकेत देखे हैं। टूर गेम में देवदत्त पडिक्कल की बड़ी सेंचुरी ने बैटिंग लाइनअप में उनकी जगह पक्की कर दी है, जबकि टीम मैनेजमेंट ने श्रीलंका के स्पिन-हैवी कंडीशंस के लिए अपने बैट्समैन को तैयार करने पर काफी ध्यान दिया है। गॉल टेस्ट में भारत के बैट्समैन के लिए खास तौर पर कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है, क्योंकि मेहमान टीम अपनी आखिरी तैयारियों में स्पिन के खिलाफ काफी मेहनत कर रही है।

बुमराह की कमी भी पूरी करनी होगी

भारत को पेस डिपार्टमेंट में बुमराह की कमी भी पूरी करनी होगी और अपने बॉलिंग अटैक में एक्सपीरियंस और यूथ के बीच सही बैलेंस बनाना होगा। श्रीलंका के लिए, यह सीरीज़ भारत के कमजोर अटैक का फायदा उठाने और एक ऐसी टीम को चुनौती देने का मौका देती है जो अभी भी कंसिस्टेंसी की तलाश में है। होस्ट टीम को भी चोट की चिंता है, जिससे भारत के बेहतर हेड-टू-हेड रिकॉर्ड के मुकाबले मुकाबला उतना प्रेडिक्टेबल नहीं होगा। गिल के लिए, यह सीरीज़ विदेशी कंडीशंस में टेस्ट कैप्टन के तौर पर उनके पहले बड़े टेस्ट में से एक है। सीरीज़ जीतने से श्रीलंका में भारत का शानदार रिकॉर्ड और बढ़ेगा।

भारतीय हॉकी टीम विश्व कप की चुनौती के लिए तैयार

नयी दिल्ली (वार्ता)। भारत की 20 सदस्यों वाली पुरुष हॉकी टीम 15 से 30 अगस्त तक होने वाले एफआईएच हॉकी वर्ल्ड कप बेल्जियम और नीदरलैंड्स 2026 में सेंटर स्टेज पर आने के लिए तैयार है। स्टार ड्रैग-फ्लिकर और डिफेंडर हरमनप्रीत सिंह की लीडरशिप में, स्क्वॉड में एक्सपीरियंस, साबित हुए मैच-विनर और होनहार नए टैलेंट का एक मज़बूत मिक्स है, जो इंडियन हॉकी की गहराई और ताकत को दिखाता है। डिफेंसिव सॉलिडिटी, मिडफील्ड क्रिएटिविटी और अटैकिंग फायरपावर के अच्छे बैलेंस के साथ, इंडिया ग्लोबल स्टेज पर एक मज़बूत स्टेटमेंट देने और एक और वर्ल्ड कप टाइटल के लिए 51 साल के इंतज़ार को खत्म करने की कोशिश में, जीत के लिए एक मज़बूत चैलेंज पेश करने का टारगेट रखेगा। हॉकी मेन्स वर्ल्ड कप बेल्जियम और नीदरलैंड्स 2026 में, इंडियन मेन्स हॉकी टीम को इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ पूल डी में रखा गया है। इंडिया अपना वर्ल्ड कप कैंपेन 15 अगस्त को वेल्स के खिलाफ शुरू करेगा, उसके बाद 17 अगस्त को इंग्लैंड के खिलाफ एक हाई-प्रोफाइल मैच होगा। इसके बाद टीम 19 अगस्त को अपने आखिरी पूल-स्टेज मैच में चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से भिड़ेगी। अनुभवी खिलाड़ियों और उभरते हुए टैलेंट के बैलेंस्ड मिक्स के साथ, इंडिया टूर्नामेंट में एक मजबूत शुरुआत करने और कॉम्पिटिशन के अगले स्टेज में जगह पक्की करने की कोशिश करेगा।

इंडियन स्क्वाड

गोलकीपरः मोहित एच एस, सूरज करकेरा

डिफेंडरः जरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह (कप्तान), अमित रोहिदास, जुगराज सिंह, संजय,सुमित, यशदीप सिवाच

मिडफील्डरः राजिंदर सिंह, आदित्य अर्जुन लालागे, हार्दिक सिंह, मनप्रीत सिंह, नीलकांत शर्मा, विवेक सागर प्रसाद

फॉरवर्ड : दिलप्रीत सिंह, शिलानंद लाकड़ा, सुखजीत सिंह, मंदीप सिंह, अभिषेक।

एलेक्ज़ेंड्रोवा को हराकर स्वितोलिना सेमीफाइनल में

टोरंटो (वार्ता)। एलिना स्वितोलिना ने सोमवार को टोरंटो में नेशनल बैंक ओपन के सेमीफ़ाइनल में पहुँचने के लिए एकातेरिना एलेक्ज़ेंड्रोवा पर तीन सेट की जीत के साथ डब्ल्यूटीए 1000 मैचों में अपनी लगातार जीत का सिलसिला 10 तक बढ़ाया। पिछले राउंड में दुनिया की नंबर 1 आर्यना सबालेंका को हराने में मदद करने वाले उसी आक्रामक बेसलाइन गेम का इस्तेमाल करते हुए, एलेक्जेंड्रोवा ने पहला सेट 6-3 से जीता, इससे पहले कि स्वितोलिना अपनी लय में आ जातीं। नंबर 9 सीड और 2017 की चैंपियन ने अगले 12 में से 11 गेम जीते और दूसरा सेट 6-0 से जीता और निर्णायक सेट में 5-1 की बढ़त बना ली। हालांकि एलेक्जेंड्रोवा ने थोड़ी देर के लिए वापसी करते हुए स्कोर 5-3 कर लिया, लेकिन स्वितोलिना ने नौवें गेम में ब्रेक करके 1 घंटे, 33 मिनट में 3-6, 6-0, 6-3 से जीत हासिल की। जीत के बाद स्वितोलिना ने मीडिया से कहा, मुझे लगता है कि वह बहुत अच्छा खेल रही थी, सच कहूं तो उसकी सर्विस बहुत अच्छी थी।

वनडे विश्व कप में जगह बनाने के लिए इंडीज को क्वालिफायर खेलना होगा

नयी दिल्ली (वार्ता)। दो बार के वनडे विश्व कप चैंपियन वेस्टइंडीज़ को 2027 में होने वाले क्रिकेट विश्व कप में जगह बनाने के लिए एक बार फिर क्वालिफ़ाइंग टूर्नामेंट का रास्ता अपनाना होगा। 30 सितंबर 2026 को जारी आईसीसी वनडे रैंकिंग में शीर्ष आठ स्थान पर रहने वाली टीमें सीधे 2027 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफ़ाई करेंगी। हालांकि, मेजबान देशों में शामिल दक्षिण अफ़्रीका और ज़िम्बाब्वे के लिए रैंकिंग ज़रूरी नहीं। आयरलैंड के खिलाफ़ बेलफ़ास्ट में रोमांचक जीत दर्ज करने के बाद अफ़ग़ानिस्तान ने भी टॉप आठ में अपनी जगह पक्की कर ली है। उसके साथ मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूज़ीलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड, बांग्लादेश, दक्षिण अफ़्रीका और ज़िम्बाब्वे भी 2027 विश्व कप में जगह बना चुके हैं। वहीं, आईसीसी वनडे रैंकिंग में 10वें स्थान पर मौजूद वेस्टइंडीज़ के पास कटऑफ तारीख़ से पहले भारत के खिलाफ़ दो वनडे मैच खेलने हैं। लेकिन इन दोनों मैचों में जीत हासिल करने के बावजूद वेस्टइंडीज़ शीर्ष आठ में वापसी नहीं कर पाएगा। इसका मतलब साफ़ है कि वेस्टइंडीज़ को एक बार फिर क्वालिफ़ायर टूर्नामेंट की कठिन राह से गुज़रना होगा। यह क्वालिफ़ायर अगले साल फ़रवरी में आयोजित किया जाना है और यहीं से वेस्टइंडीज़ के पास 2027 विश्व कप का टिकट हासिल करने का एक और मौक़ा होगा। वेस्टइंडीज़ के लिए यह स्थिति नई नहीं है। 2023 वनडे विश्व कप में भी वे सीधे क्वालिफ़ाई नहीं कर पाए थे और उन्हें क्वालिफ़ायर टूर्नामेंट में हिस्सा लेना पड़ा था। हालांकि, क्वालिफ़ायर के सुपर सिक्स चरण में वेस्टइंडीज़ पांचवें स्थान पर रहा और विश्व कप में जगह बनाने में नाकाम रहा। यह क्रिकेट इतिहास में पहली बार था जब वेस्टइंडीज़ वनडे विश्व कप का हिस्सा नहीं बना। विश्व कप से बाहर होने का असर आगे भी देखने को मिला और इसी वजह से वेस्टइंडीज़ 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी क्वालिफ़ाई नहीं कर सका। वह 2013 के बाद पहली बार इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट से बाहर रहा। 2027 विश्व कप के क्वालिफ़ायर में कुल आठ टीमें हिस्सा लेंगी। इनमें 30 सितंबर 2026 की वनडे रैंकिंग के आधार पर दो सबसे निचली रैंक वाली गैर-मेज़बान फुल मेंबर टीमें, आयरलैंड और वेस्टइंडीज़ शामिल होंगी। इसके अलावा क्रिकेट विश्व कप लीग 2 की शीर्ष चार टीमें और विश्व कप क्वालिफ़ायर प्लेऑफ़ की शीर्ष चार टीमें भी क्वालिफ़ायर में जगह बनाएंगी। क्वालिफ़ायर का विजेता सीधे विश्व कप के दूसरे दौर में प्रवेश करेगा। वहीं दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमों को सुपर सीरीज़ से गुज़रना होगा। इस त्रिकोणीय सीरीज़ की विजेता टीम दूसरे दौर में पहुंचेगी। हालांकि, 2027 विश्व कप के इस नए फॉर्मेट को लेकर एसोसिएट देशों की ओर से नाराज़गी भी सामने आई है। विश्व कप क्वालिफ़ायर प्लेऑफ़ में क्रिकेट विश्व कप लीग 2 की निचली चार टीमें और चैलेंज लीग की चार टीमें हिस्सा लेंगी।

सिंधु ने विश्व चैम्पियनशिप में बंदरों को कंट्रोल करने की कोशिशों को सपोर्ट किया

नई दिल्ली (वार्ता)। दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु ने बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप 2026 के ऑर्गनाइज़र्स का सपोर्ट किया है, जिन्होंने नेशनल कैपिटल के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में बंदरों की समस्या से निपटने के लिए कदम उठाए हैं, भले ही सोशल मीडिया की नजर में यह अजीब कदम उठाया गया हो। खबर है कि बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (बाई) ने वर्ल्ड चैंपियनशिप से पहले रीसस मकाक को वेन्यू से दूर रखने के लिए तीन एक्सपर्ट्स को बुलाया है, जो 17 से 23 अगस्त तक होगी। इस कदम का ऑनलाइन कुछ मज़ाक उड़ाया गया है, रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ये लोग बंदरों को डराने के लिए लंगूर की नकल करेंगे। ये लोग लंगूर की आवाज़ों की नकल करते हैं, जो बंदरों की एक बड़ी प्रजाति है जिससे रीसस मकाक बचते हैं। 2012 से वाइल्डलाइफ कानूनों के तहत बंदरों की आबादी को कंट्रोल करने के लिए ज़िंदा लंगूरों का इस्तेमाल करना बैन है, इसलिए दिल्ली भर में सरकारी इमारतों और पब्लिक जगहों पर ट्रेंड इंसानी नकलची एक आम ऑप्शन के तौर पर सामने आए हैं।

आरबीआई गवर्नर की बैंकों से अपील, एआई को तेजी से अपनायें

मुंबई (वार्ता)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मंगलवार को बैंकों से अपील की कि वे एआई को तेजी से अपनायें और इसके लिए जरूरी बुनियादी ढांचे, प्रतिभा और कौशल में निवेश करें। उद्योग मंडल फिक्की और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए) द्वारा आयोजित वार्षिक बैंकिंग सम्मेलन फीबैक 2026 को संबोधित करते हुए श्री मल्होत्रा ने कहा कि एआई इस दशक को उसी तरह परिभाषित करेगा, जैसे 2000 के दशक को डिजिटलाइजेशन और 1990 के दशक को उदारीकरण ने परिभाषित किया था। उन्होंने कहा, अब हमारे सामने एकमात्र सवाल यह है कि क्या आप एआई की यात्रा को आकार देंगे या फिर डिफॉल्ट रूप से उसे आपको आकार देने का मौका देंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि एआई का इस्तेमाल इस तरह हो कि वह मानव निर्णय क्षमता का स्थान लेने की बजाय उसे मजबूत करे। उन्होंने बैंकों से तकनीकी बुनियादी ढांचे, प्रतिभा, कौशल विकास और पुनःकौशल प्रशिक्षण, टिकाऊ साझेदारियों तथा उपयुक्त गवर्नेंस ढांचे में निवेश करने का भी आग्रह किया, ताकि एआई को तेजी से अपनाया जा सके। श्री मल्होत्रा ने कहा कि एआई बुद्धिमत्ता को कई गुना बढ़ाता है, जिसका सीधा असर इस बात पर पड़ता है कि ऋण की कीमत कैसे तय की जाती है और उसे कैसे उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने कहा कि कैश फ्लो, टैक्स रिटर्न, यूटिलिटी भुगतान और डिजिटल प्लेटफॉर्म के रिकॉर्ड जैसे वैकल्पिक डेटा पर प्रशिक्षित मॉडल बैंकिंग सेवाओं के दायरे को पारंपरिक ऋण मूल्यांकन से कहीं आगे ले जा सकते हैं। पारंपरिक अंडरराइटिंग ऐसी वित्तीय हिस्ट्री पर निर्भर करती है, जो आबादी के बड़े हिस्से के लिए बहुत सीमित है या उपलब्ध ही नहीं है।उन्होंने कहा कि एआई में वित्तीय निर्णय क्षमता के लिए वही करने की क्षमता है, जो यूपीआई ने वित्तीय लेनदेन के लिए किया।

ऑलराउंडर अज़मतुल्लाह को आईसीसी कोड ऑफ़ कंडक्ट तोड़ने पर फटकार

दुबई (वार्ता)। अफ़गानिस्तान के ऑलराउंडर, अज़मतुल्लाह उमरज़ई को शुक्रवार को ब्रेडी में आयरलैंड के खिलाफ़ दूसरे वनडे के दौरान आईसीसी कोड ऑफ़ कंडक्ट के लेवल 1 को तोड़ने का दोषी पाए जाने के बाद फटकार लगाई गई है। अज़मतुल्लाह को आईसीसी कोड ऑफ़ कंडक्ट के आर्टिकल 2.8 को तोड़ने का दोषी पाया गया, जो खिलाड़ियों और प्लेयर सपोर्ट स्टाफ़ के लिए है, जो एक इंटरनेशनल मैच के दौरान अंपायर के फ़ैसले पर नाराज़गी दिखाने से जुड़ा है।

डीजीएफटी ने गेहूं निर्यातकों से 31 अगस्त तक मांगा ब्योरा

नयी दिल्ली (वार्ता)। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी)ने गेहूं के सभी निर्यातकों से 31 अगस्त 2026 तक उपयोग प्रमाणपत्र सहित शिपिंग बिल का विवरण और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने को कहा है। महानिदेशालय के जारी एक नोटिस में कहा गया है कि यह कदम वर्ष 2025-26 और 2026-27 के दौरान आवंटित गेहूं निर्यात कोटे के वास्तविक इस्तेमाल की समीक्षा और इस्तेमाल नहीं हो सके कोटे के दोबारा वितरण के उद्देश्य से उठाया है। नोटिस के अनुसार निर्यातकों को आगामी 26 अगस्त तक आवंटित कोटे में से किए गए वास्तविक निर्यात का चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रमाणित उपयोग प्रमाणपत्र और शिपिंग बिल जमा करना होगा। जो निर्यातक अतिरिक्त मात्रा की मांग करना चाहते हैं, उन्हें वैध निर्यात अनुबंध या खरीद ऑर्डर के साथ ऑनलाइन पोर्टल पर संशोधन आवेदन देना होगा। वहीं कोटा वापस करने के इच्छुक निर्यातकों को भी इसका कारण बताना होगा। डीजीएफटी ने स्पष्ट किया है कि सभी विवरण 31 अगस्त तक निर्धारित ईमेल और ऑनलाइन पोर्टल पर जमा हो जाने चाहिए और समय सीमा के बाद या अधूरे आवेदनों को खारिज कर दिया जाएगा।गेहूं कोटा निर्यात के दोबारा वितरण के नियमों को स्पष्ट करते हुए डीजीएफटी ने बताया कि जिन निर्यातकों ने अपने आवंटित कोटे का 50 प्रतिशत से अधिक इस्तेमाल कर लिया है, केवल वे ही अतिरिक्त आवंटन के पात्र होंगे।

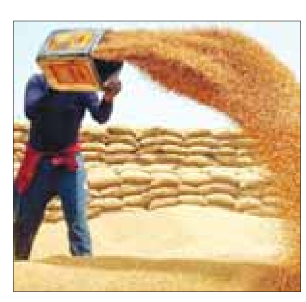

वेदांता एल्युमिनियम ने अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के लिए मेटल बाजार एक्सपोर्ट्स पेश किया

नयी दिल्ली (वार्ता)। वेदांता एल्युमिनियम मेटल लिमिटेड ने मंगलवार को अपने प्रमुख डिजिटल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म वेदांता मेटल बाजार (वीएमबी) के अंतरराष्ट्रीय बाजार में विस्तार की घोषणा की। अब यह प्लेटफॉर्म अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों को प्रीमियम एल्युमिनियम उत्पाद सीधे ऑनलाइन ऑर्डर करने और खरीदने की सुविधा देता है। वेदांता एल्युमिनियम ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि इससे ग्राहकों के लिए खरीदारी की प्रक्रिया पहले से अधिक आसान, पारदर्शी और सुविधाजनक हो गयी है। घरेलू बाजार की सफलता के बाद कंपनी ने वेदांता मेटल बाजार को अब एशिया, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बाजारों में भी उपलब्ध कराया है। वित्त वर्ष 2025-26 में घरेलू बाजार में इस प्लेटफॉर्म के जरिये करीब 4.1 अरब डॉलर (38,000 करोड़ रुपये से अधिक) के लेनदेन हुए और 23,000 से ज्यादा ऑर्डर पूरे किये गये। बड़ी कंपनियों के अलावा, 550 से अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) अपनी एल्युमिनियम जरूरतों के लिए नियमित रूप से वेदांता मेटल बाजार का इस्तेमाल कर रहे हैं। वेदांता एल्युमिनियम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश कुमार ने कहा, च्वेदांता मेटल बाजार का वैश्विक स्तर पर विस्तार हमारी उस यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसका उद्देश्य डिजिटल तकनीक के जरिये एल्युमिनियम की खरीद प्रक्रिया को बेहतर और आसान बनाना है।

हैदराबाद की जीनोम वैली में नया साइंस एंड इनोवेशन सेंटर खोलेगी एमजेन

नयी दिल्ली (वार्ता)। एमजेन ने मंगलवार को हैदराबाद की जीनोम वैली में नया साइंस एंड इनोवेशन सेंटर खोलने की अपनी योजना की घोषणा की। कंपनी ने बताया कि यह केंद्र एमजेन के वैश्विक शोध एवं विकास नेटवर्क का हिस्सा होगा। नये केंद्र के खुलने से कंपनी की शोध एवं वैज्ञानिकों क्षमताओं का विस्तार होगा। इस केंद्र के 2027 तक परिचालन में आने की उम्मीद है। यह केंद्र जीव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सर्वश्रेष्ठ तकनीकों का उपयोग करते हुए दुनिया की सबसे जटिल बीमारियों से लड़ने की दिशा में एक कदम है।

कच्चे तेल में तेजी से 388 अंक टूटा सेंसेक्स

मुंबई, (वार्ता)।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में नरमी से मंगलवार को घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट रही और प्रमुख सूचकांक आधा फीसदी के करीब टूट गये। बीएसई का सेंसेक्स 388.19 अंक (0.49 प्रतिशत) लुढ़ककर 78,154.25 अंक पर बंद हुआ। सूचकांक सुबह करीब 33 अंक नीचे 78,509.77 अंक पर खुला और पूरे दिन लाल निशान में रहा। एक समय यह करीब 494 अंक गिर गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी-50 सूचकांक भी 112.10 अंक यानी 0.46 प्रतिशत नीचे 24,471.70 अंक पर रहा। कच्चे तेल में आज तेजी रही। लंदन का ब्रेंट क्रूड वायदा 0.3 प्रतिशत चढ़कर फिलहाल 88 डॉलर प्रति बैरल के करीब है। इससे भारतीय शेयर बाजारों में गिरावट रही। वृहत बाजार में निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 0.07 प्रतिशत और स्मॉलकैप-100 सूचकांक 0.22 प्रतिशत ऊपर बंद हुआ।

एफएमसीजी, धातु, ऑटो, वित्त, बैंकिंग, रियल्टी और रसायन समूहों के सूचकांक लाल निशान में रहे। वहीं, आईटी, फार्मा और स्वास्थ्य समूहों में तेजी देखी गयी। एनएसई में जिन 3,478 कंपनियों के शेयरों में कारोबार हुआ उनमें से 1,865 के शेयरों में गिरावट और 1,487 में तेजी रही। अन्य 126 कंपनियों के शेयर अंततः अपरिवर्तित बंद हुए। सेंसेक्स की 30 में से 25 कंपनियों के शेयर लुढ़क गये। अल्ट्राटेक सीमेंट का शेयर 2.75 फीसदी नीचे बंद हुआ। एक्सिस बैंक में 1.52 प्रतिशत, इंडिगो में 1.50, भारती एयरटेल में 1.44, बजाज फाइनेंस में 1.04 और पावरग्रिड में 1.03 प्रतिशत की गिरावट रही। आईटीसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा स्टील, हिंदुस्तान यूनीलिवर, एशियन पेंट्स, अडानी पोर्ट्स, बजाज फिनसर्व, एलएंडटी, सनफार्मा, मारुति सुजुकी, भारतीय स्टेट बैंक, ट्रेंट, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर भी लाल निशान में रहे।

इटरनल का शेयर 2.01 प्रतिशत चढ़ा। इंफोसिस और टाइटन के शेयर भी मजबूत बंद हुए। वैश्विक स्तर पर एशिया में हांगकांग का हैंग सेंग 1.10 प्रतिशत और चीन का शंघाई कंपोजिट 0.82 प्रतिशत फिसल गया। यूरोपीय बाजारों में जर्मनी का डैक्स 0.20 प्रतिशत और ब्रिटेन का एफटीएसई 0.12 प्रतिशत ऊपर था।

वन पर्यटन को विस्तार देकर होम स्टे से जनजातियों की बढ़ायें आय : डॉ. यादव

मुख्यमंत्री ने मप्र राज्य वन्य प्राणी बोर्ड की 32वीं बैठक में दिए निर्देश

भोपाल (स्वतंत्र मत)।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि वन विभाग प्रदेश में तेजी से बढ़ रही पर्यटन संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए वन पर्यटन के विकास पर विशेष फोकस करें। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में जहाँ-जहाँ वन पर्यटन के विकास और विस्तार की सहज संभावनाएं उपलब्ध हैं, वहां वन विभाग पर्यटन विभाग के साथ समन्वय करें और ठोस कार्य योजना तैयार कर उस पर अमल करें। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश की प्राकृतिक संपदा, जैव विविधता और वन्य प्राणी पर्यटन की अपार संभावनाएं प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंगलवार को मंत्रालय में मध्यप्रदेश राज्य वन्य प्राणी बोर्ड की 32वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विशेष रूप से होम स्टे को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कहा कि इससे स्थानीय लोगों, वनवासियों और जनजातीय परिवारों को अपने क्षेत्र में ही रोजगार और आमदनी के अतिरिक्त अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि वन पर्यटन का लाभ केवल पर्यटकों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि जंगलों के बीच और आसपास रहने वाले वनवासियों एवं जनजातीय परिवारों की समृद्धि का माध्यम भी बनना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पर्यटन गतिविधियों के विस्तार में स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इससे एक ओर पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को समझने का अवसर मिलेगा, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण एवं जनजातीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

दूसरे राज्यों से सतत् सम्पर्क में रहें

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि दूसरे राज्यों से सतत् सम्पर्क में रहें, उनसे वयस्क और स्वस्थ वन्य प्राणियों का आदान-प्रदान करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आंध्रप्रदेश, आसाम, कर्नाटका को मध्यप्रदेश में उपलब्ध बाघ देकर उनसे हाथी, गेंडे और अन्य वन्य प्राणी लिए जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वन भूमि के उपयोग को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वन भूमि में होने वाले किसी भी प्रयोजन के लिए डायवर्सन पर सख्त नजर रखी जाए। वन भूमि में अवैध उत्खनन कदापि न होने पाए।

कुल 30 प्रस्ताव अनुमोदन के लिए प्रस्तुत

बैठक में प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों और टाइगर रिजर्व क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास तथा वन्य प्राणी संरक्षण से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। कुल 30 प्रस्ताव अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए गए, बोर्ड ने विमर्श के बाद मंजूरी प्रदान कर दी। इनमें प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों की परिधि में स्थित वन ग्रामों में सीसी रोड निर्माण, टाइगर रिजर्व में स्थित वन ग्रामों में पक्की सड़कों का निर्माण, राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व क्षेत्रों में मोबाइल टॉवर्स की स्थापना, उप स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण, विद्युत लाइन बिछाने सहित अन्य आवश्यक निर्माण कार्यों से संबंधित अनुमोदन प्रस्ताव शामिल थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राष्ट्रीय उद्यानों और टाइगर रिजर्व की परिधि में मौजूद वन ग्रामों में कोई भी निर्माण या विकास कार्य आबादी को विश्वास में लेकर ही किया जाये।

विकास और संरक्षण के बीच बराबर संतुलन बनाए

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विकास और संरक्षण के बीच बराबर संतुलन बनाए रखते हुए वन सम्पदा की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। मानव और वन्य प्राणी में किसी प्रकार का संघर्ष ना हो। उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की मूलभूत सुविधाओं का विस्तार करते हुए यह भी सुनिश्चित किया जाए कि विकास कार्यों से वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पर्यटन गतिविधियों के विस्तार में स्थानीय समुदाय की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वन्य प्राणी बोर्ड में विशेषज्ञ सेवाएं देने के लिए केन्द्र सरकार और राज्य के पुरातत्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को भी विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया जाए।

बैठक में वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री उपस्थित रहे

बैठक में वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार, मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल, अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई, प्रमुख सचिव वन राघवेन्द्र कुमार सिंह, वन्य प्राणी बोर्ड के सदस्य डॉ. मोहन नागर, डॉ. रूपनारायण मांडवे, विजय मनोहर तिवारी, व्यास, विधायक मधु सिंह गहलोत, भाऊराव भिस्कुटे न्यास नर्मदापुरम के सदस्य और भारत भारती बैतूल के सदस्य, दीनदयाल शोध संस्थान चित्रकूट के सदस्य, पीसीसीएफ सुधिरंजन सेन, मुख्य वन्य प्राणी संरक्षण समिता राजौरा सहित वन विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

उपकाशी नगरी हटा में आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा

सावन के द्वितीय सोमवार पर हुई संगीतमय शिव महाआरती

हटा (स्वतंत्र मत)।

सावन के द्वितीय सोमवार पर उपकाशी नगरी हटा में आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। श्री श्री 1008 गौरीशंकर भगवान के दरबार में संगीतमय महाआरती का आयोजन किया गया। असंख्य दीपों की रोशनी और हर.हर महादेव के जयघोष से पूरा वातावरण शिवमय हो उठा।

प्रात:काल भगवान गौरीशंकर का महामस्ताभिषेक एवं पूजन किया गया। शाम को मंदिर परिसर में पुजारी रामसुजान पाठक के सान्निध्य में भव्य महाआरती संपन्न हुई। ढोल नगाड़ों और भजनों की गूंज के बीच श्रद्धालुओं ने हाथों में दीप लेकर भगवान भोलेनाथ की आरती उतारी और सुख-समृद्धि की कामना की।

महाआरती में नगर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मंदिर परिसर और मार्गों पर हर-हर महादेव एवं बम-बम भोले के जयकारे गूंजते रहे। आयोजन के बाद श्रद्धालुओं को फल एवं प्रसाद वितरित किया गया। आयोजन में समिति सदस्यों और युवाओं ने व्यवस्थाओं में सहयोग किया।

फर्जी दस्तावेज से कृषि ऋण निकालने के मामले में दो फरार आरोपी गिरफ्तार

हटा (स्वतंत्र मत)। थाना हटा में दर्ज प्रकरण क्रमांक 440/26 में धोखाधड़ी के फरार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। पुलिस के अनुसार ग्राम रसईया निवासी गणेश यादव की ग्राम बड़ी मुहार स्थित 5.30 हेक्टेयर कृषि भूमि पर अज्ञात व्यक्ति ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर स्वयं को गणेश यादव बताकर यूनियन बैंक हटा से 5 लाख 30 हजार रुपए का कृषि ऋण निकाल लिया था। जांच में धोखाधड़ी सामने आने पर आरोपियों के विरुद्ध धारा 419, 420, 467, 468 एवं 471 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। पूर्व में आरोपी अमर सिंह लोधी को गिरफ्तार किया जा चुका था। लगातार तलाश के बाद भानू उर्फ भानू प्रताप सिंह एवं अरविंद उर्फ यादवेंद्र सिंह लोधी दोनों निवासी ग्राम बरखेड़ा थाना पटेरा को 10 अगस्त को पटेरा बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया।

हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत ज्ञानवर्धक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित

दमोह (स्वतंत्र मत)। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत शासकीय कमला नेहरू महिला महाविद्यालय दमोह में 11 अगस्त को एक गरिमामयी प्रश्नोत्तरी क्विज़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम महाविद्यालय की संरक्षक एवं प्राचार्य डॉ. जीपी चौधरी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

प्रतियोगिता के सुचारू संचालन में नोडल अधिकारी डॉ. अवधेश जैन, प्रभारी डॉ. आराधना श्रीवास, संयोजक डॉ. बृजेंद्र कुसमरिया तथा समिति सदस्य डॉ. राजेश पौराणिक एवं डॉ. शिखा यादव की मुख्य भूमिका और कुशल निर्देशन रहा। कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए संयोजक डॉ. बृजेंद्र कुसमरिया ने कहा हर घर तिरंगा अभियान केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं है बल्कि यह हमारी युवा पीढ़ी में राष्ट्रप्रेमए राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और भारत के गौरवशाली स्वाधीनता संग्राम के इतिहास से जुड़ने की अलख जगाने का एक सशक्त माध्यम है छात्रा-छात्राओं में देशभक्ति और भारतीय इतिहास के ज्ञान को परखने के लिए आयोजित इस क्विज़ प्रतियोगिता में छात्राओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए नंदिनी पटेल, हरीबाई, निकिता अहिरवार, रिंकी राज, कौशल्या पटेल एवं मुस्कान कोष्टी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।

दमोह पुलिस ने निकाली तिरंगा मोटर साइकिल यात्रा

दमोह (स्वतंत्र मत)। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र गौरव का संदेश जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से सोमवार को दमोह पुलिस ने पुलिस अधीक्षक आनंद कलादगि के नेतृत्व में भव्य तिरंगा मोटरसाइकिल यात्रा निकाली। यात्रा में पुलिस की 150 से अधिक मोटरसाइकिलें शामिल रहीं। पुलिस अधिकारियों और जवानों ने हाथों में तिरंगा लेकर उत्साह व अनुशासन के साथ शहर में भ्रमण किया और लोगों को देशभक्ति व राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। पुलिस अधीक्षक आनंद कलादगी ने कहा कि तिरंगा देश की आन बान और शान का प्रतीक है। उन्होंने

नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को गरिमा और राष्ट्रप्रेम के साथ मनाने तथा राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करने की अपील की। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुजीत सिंह भदौरिया, सीएसपी एचआर पांडेय, प्रशिक्षु डीएसपी शिवप्रसाद कंगाली, निरीक्षक दलबीर सिंह मार्को, निरीक्षक मनीष कुमार सहित में पुलिस अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

जनसुनवाई में जयश्री की सुनी गई फरियाद

दमोह (स्वतंत्र मत)। कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने कलेक्टर कार्यालय के कक्ष 10 में आयोजित जनसुनवाई में जिले के दूरदराज क्षेत्रों से आये आवेदकों की समस्याओं को सुना। इस दौरान सामान्य जनसुनवाई में 247 आवेदनों पर सुनवाई करते हुये संबंधित अधिकारियों को समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिये। जनसुनवाई में 17 आधार अपडेशन एवं 60 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया।

जयश्री ठाकुर के बिजली कनेक्शन का हुआ समाधान - जनसुनवाई में बजरिया वार्डए दमोह निवासी जयश्री ठाकुर अपनी बिजली कनेक्शन संबंधी समस्या लेकर पहुंचीं। उन्होंने कलेक्टर श्री यादव को बताया कि वह कई दिनों से अपने घर में बिजली कनेक्शन लगवाने के लिए प्रयास कर रही हैं लेकिन बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा बताई गई राशि उनके पास उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा उनकी इच्छा है कि उनके घर में बिजली का कनेक्शन हो जाए। कलेक्टर ने जयश्री की समस्या को गंभीरता से सुना और तत्काल बिजली विभाग के अधिकारियों को बुलाकर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने जय श्री को 3 हजार की सहायता राशि का चेक प्रदान करते हुए उनके घर में तत्काल बिजली कनेक्शन कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। कलेक्टर की तत्परता से अपनी समस्या का समाधान होते देख जयश्री ठाकुर बेहद प्रसन्न हुईं। उन्होंने कहा कई दिनों से उनके मन में अपने घर में बिजली कनेक्शन लगवाने का सपना था जो आज पूरा होने जा रहा है। उन्होंने जनसुनवाई कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि वे बड़ी उम्मीद और तमन्ना के साथ अपनी समस्या लेकर आई थीं और आज उनकी सुनवाई हो गई।

बांदकपुर स्कूल के प्रभारी प्राचार्य अंशुमान नेमा हटाए गए

दमोह (स्वतंत्र मत)। कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के निर्देशों के तहत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बांदकपुर में प्रभारी प्राचार्य के पद पर कार्यरत अंशुमान नेमा जो मूलत: उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं को प्रभारी प्राचार्य के पद से हटा दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी सत्यम चौरसिया द्वारा जारी आदेश के अनुसार अंशुमान नेमा को प्रभारी प्राचार्य के दायित्व से मुक्त करते हुए शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बांदकपुर में पदस्थ उच्च माध्यमिक शिक्षक जसरथ प्रसाद राय को तत्काल प्रभाव से अस्थाई रूप से प्रभारी प्राचार्य का प्रभार सौंपा गया है।

नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित

प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त युवाओं को किया गया सम्मानित

दमोह (स्वतंत्र मत)। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश पर मेरा युवा भारत दमोह द्वारा नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अंतर्गत युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने एवं उनकी रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं के अंतर्गत

कविता गायन में प्रथम गौरव राठौरए द्वितीय साक्षी रजक, तृतीय देवांश दुबे चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम उर्वशी वेद, द्वितीय हेमश्री अहिरवार, तृतीय नायला बानो, भाषण प्रतियोगिता में प्रथम संस्कृति विश्वकर्मा, द्वितीय सौम्या पांडे, तृतीय प्रशांत कुर्मी रील मेकिंग में प्रथम अनुराग जाटव, द्वितीय शिवांश पटेल, तृतीया निवेश भी प्रसाद नुक्कड़ नाटक में प्रथम सरदार पटेल उमा विद्यालय दमोह, द्वितीय शासकीय केशवराम पांडे विद्यालय दमोह, तृतीय शासकीय पीजी कॉलेज दमोह समूह गायन में प्रथम एमएलबी स्कूल दमोह, द्वितीय एमएलबी स्कूल दमोह, तृतीय शासकीय केशवराम राम पांडे विद्यालय दमोहए समूह नृत्य में प्रथम मुक्ति मंच दमोह, द्वितीय शासकीय केशवराम पांडे विद्यालय दमोह, तृतीय शासकीय पीजी कॉलेज दमोह नए स्थान प्राप्त किया जिन्हें प्रमाण पत्र एवं शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया। युवाओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए अपनी प्रतिभा के माध्यम से नशा मुक्ति और स्वस्थ जीवनशैली का संदेश दिया।

सेवा हमारा धर्म और अंत्योदय हमारा लक्ष्य : डॉ. यादव

बुजुर्गो को पेंशन का संबल, बहनों को रक्षाबंधन का उपहार, मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक बहनों के खातों में अंतरित किए 311 करोड़

भोपाल (स्वतंत्र मत)।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को मंत्रालय से प्रदेश की लाखों बहनों के खातों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की पेंशन राशि तथा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत गैस सिलेंडर रिफिल की प्रोत्साहन राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के सभी जिलों में मौजूद हितग्राहियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करते हुए कहा कि समाज के हर वर्ग के विकास और कल्याण के लिए हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। हम चाहते हैं कि सबके घरों में खुशहाली आए। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता सेवा और अंत्योदय है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गरीब, युवा, नारी शक्ति और किसान कल्याण के लिए ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि समर्पण भाव से सबकी सेवा हमारा धर्म और अंत्योदय ही हमारा अंतिम लक्ष्य है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत प्रदेश के 35 लाख 25 हजार से अधिक पात्र हितग्राहियों के बैंक खातों में 211 करोड़ 53 लाख रुपये अंतरित किये। यह राशि जुलाई 2026 की पेंशन के रूप में संबंधित हितग्राहियों के खातों में अंतरित की गई है। उन्होंने कहा कि पेंशन की राशि भले छोटी हो, लेकिन इससे मिलने वाला सहारा बहुत बड़ा होता है। बुजुर्गो के चेहरे की मुस्कान से ही सरकार को लोक कल्याण के लिए और भी बेहतर काम करने की नई ऊर्जा मिलती है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारे त्यौहार उत्सव का अवसर ही नहीं, समाज के अंतिम व्यक्ति की खुशियों से जुड़ने का अवसर भी होते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए नागरिकों के सम्मान और सबकी खुशी से बढ़कर दूसरा कोई त्यौहार नहीं है, इसीलिए हमने आने वाले त्यौहारों पर सबसे पहले बुजुर्गों को पेंशन राशि अंतरित करने का फैसला लिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने श्रावण मास और आगामी रक्षाबंधन पर्व का उल्लेख करते हुए प्रदेश की लगभग 22 लाख 20 हजार से अधिक बहनों के खातों में अप्रैल और मई 2026 की गैस सिलेंडर रिफिल की राशि भी सिंगल क्लिक से अंतरित की। बहनों के खातों में करीब 99 करोड़ रुपये की दो माह की सब्सिडी पहुंचाई गई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सावन तो बहनों का ही महीना होता है। बहनें खुश न हों, तो घर में रौनक नहीं होती, इसीलिए हमने अभी से ही उन्हें रक्षाबंधन का उपहार देना शुरू कर दिया है।

म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल
भेड़ाघाट रोड, धनवंतरी नगर, जबलपुर म.प्र. पिन-482003

भवन नामिनी नामांतरण हेतु सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल द्वारा निर्मित हाथीताल कालोनी जबलपुर स्थित भवन क्रमांक जी-27 श्रीमती सुशीला देवी पति स्व. श्री हरिचंद्र को आंवटित है। आवंटी सुशीला देवी पति स्व. श्री हरिचंद्र का निधन दिनांक 02.07.2008 को हो गया है। उनकी पुत्री सुश्री कांता देवी सूरी पिता स्व. श्री हरिचंद्र सूरी के द्वारा नामांतरण करने हेतु मृत्यु प्रमाण पत्र, स्वयं का शपथपत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ उक्त भवन के नामांतरण हेतु आवेदन / दस्तावेज इस कार्यालय में प्रस्तुत किये हैं, उसके आधार पर संपत्ति के नामांतरण की कार्यवाही इस कार्यालय में प्रचलन में है यदि किसी व्यक्ति/संस्था को उक्त भवन नामांतरण बाबत् आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने से 15 दिवस के अंदर लिखित एवं वैद्य आपत्ति सप्रमाण स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात् नामांतरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। जिस पर किसी की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

संपदा अधिकारी म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, जबलपुर

कार्यालय संभागीय अधिकारी संभाग क्रं.5 नगर निगम जबलपुर
पत्र क्रं./स.अधि./स.क्र.-05 26-27/38
जबलपुर दिनांक 11/8/2026

भवन नामांतरण

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि श्रीमती तेजा अग्रवाल पति स्व. श्री रघुनंदन प्र. अग्रवाल (2) पुत्र. अनिल कुमार अग्रवाल/ स्व. श्री रघुनंदन प्रसाद अग्रवाल ने भवन क्रमांक 466 वार्ड महात्मा गांधी क्षेत्रफल 957 वर्गफुट भूतल 957 आ. प्रथम तल 957 आ. शपथ पत्र/ मृत्युप्रमाण पत्र/ विक्रय पत्र के आधार पर नगर निगम द्वारा मकान नं. पर नामांतरण हेतु पंजीकृत स्वामी श्री रघुनंदन प्रसाद अग्रवाल पिता राम किशन अग्रवाल पिन नं. 1000370100/ 41000503 पर जिस किसी को उक्त में प्रमाण सहित आपत्ति हो तो इस प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अंदर कार्यालय संभाग क्रमांक 5 में प्रमाण सहित अपत्ति प्रस्तुत करें।

संभागीय अधिकारी
संभाग क्रमांक-5
नगर निगम जबलपुर

कार्यालय संभागीय अधिकारी संभाग क्रमांक 05 नगर पालिक निगम, जबलपुर
पत्र क्र. / सं.क्र.05/2026-27/42
दिनांक 10.08.2026

भवन नामांतरण

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री राजेश पटेल पिता स्व. तुलाराम पटेल ने भवन क्र. 243 वार्ड जवाहरगंज क्षेत्रफल 492 वर्गफुट भूतल 492 प्लाट त्यागपत्र के आधार पर नगर निगम द्वारा मकान नं.... पर नामांतरण हेतु पंजीकृत स्वामी श्री राजेश कु., मनोज कु./स्व. तुलाराम बली मां कमला बाई पिन नं. 1000394177/ 41400460 पर जिस किसी को भी उक्त में प्रमाण सहित आपत्ति हो तो इस प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अंदर कार्यालय संभाग क्र. 05 में प्रमाण सहित आपत्ति प्रस्तुत करें।

संभागीय अधिकारी
संभाग क्रमांक-05
नगर निगम, जबलपुर

कार्यालय नगर पालिका परिषद सिहोरा, जिला जबलपुर (म.प्र.)
फोन नं 07624-230030 ईमेल cmosihora@mpurban.gov.in

(निविदा निविदा)

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑन लाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाइट https://www.mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

टेण्डर क्रमांक जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा की अंतिम तिथि
1	2	3	4	5
2026_UAD_528466_1 दिनांक 10/8/2026 NIT NO. 2601/PWD/NPP/2026	नगर परिषद के विभिन्न वार्डो में रोड मरम्मत कार्य	12 माह 9,50,000/-	2000.00/- 9,600/-	29/8/2026
2026_UAD_528467_1 दिनांक 10/8/2026 NIT NO. 2601/PWD/NPP/2026	नगर परिषद के विभिन्न वार्डो में नाली/पुलिया मरम्मत कार्य	12 माह 9,50,000/-	2000.00/- 9,600/-	29/8/2026
2026_UAD_528468_1 दिनांक 10/8/2026 NIT NO. 2603/PWD/NPP/2026	मुरम एवं पोकलेन मशीन सप्लाई कार्य	12 माह 9,50,000/-	2000.00/- 9,600/-	29/8/2026

नोटः- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन https://www.mptenders.gov.in की वेबसाइट पर ही किया जावेगा पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

श्रीमति संध्या दिलीप दुबे
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद सिहोरा

श्री अंकुश नायक
प्र. सदस्य लो.नि.वि
नगर पालिका परिषद सिहोरा

प्रदीप झारिया
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद सिहोरा

जनसुनवाई में निगमायुक्त ने सुनी आमजनों की समस्याएं

मौके पर हुआ निपटारा, 76 आवेदनों पर हुई सुनवाई

जबलपुर (स्वतंत्र मत)। नगर निगम मुख्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया गया। जनसुनवाई में कुल 76 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से राजस्व एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कई प्रकरणों का निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार द्वारा मौके पर ही त्वरित निराकरण कर आवेदकों को तत्काल राहत प्रदान की गई। शेष समस्त आवेदनों को समय-सीमा के भीतर निराकृत करने हेतु संबंधित विभागीय प्रमुखों को प्रेषित किया गया।

अवैध वसूली, लूट जैसे 21 मामले दर्ज

शातिर बदमाश पर हुई एनएसए की कार्यवाही

जबलपुर (स्वतंत्र मत)। पुलिस कप्तान सम्पत उपाध्याय के प्रतिवेदन पर जिला दण्डाधिकारी राघवेन्द्र सिंह ने शातिर बदमाश मोहन चौधरी उर्फ मोहन चोटी के विरूद्ध एनएसए के तहत किया जारी वारंट किया है। जानकारी के मुताबिक रांझी थाने शातिर बदमाश मोहन चौधरी उर्फ मोहन चोटी के विरूद्ध हत्या के प्रयास, अवैध वसूली, मारपीट, आर्म्स एक्ट, चोरी लूट सहित कुल 21 अपराध पंजीबद्ध है। जिसको देखते हुए पुलिस द्वारा एनएसए की कार्यवाही की गई है।

उपभोक्ताओं को पड़ेगी मंहगी बिजली की मार अगले 5 साल के टैरिफ की प्रक्रिया शुरू

1 अप्रैल 2027 से लागू होने वाले बिजली टैरिफ की प्रक्रिया शुरू, उपभोक्ताओं से मांगे सुझाव

जबलपुर (स्वतंत्र मत)

मप्र में आगामी एक अप्रैल 2027 से लागू होने वाले अगले 5 साल के बिजली टैरिफ से जुड़ी प्रक्रिया शुरू हो गई है। दरअसल मप्र पावर मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के लाइन लॉस को बढ़ाते हुए नई याचिका मप्र विद्युत नियामक आयोग को भेजी गई है। याचिका के आधार पर मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने मल्टी ईयर टैरिफ के लिए प्रस्तावित नियम-शर्तों पर उपभोक्ताओं से एक सितंबर तक आपत्ति और सुझाव मांगे हैं।

फोटो: एआई

इस प्रक्रिया में वितरण हानि का प्रस्तावित स्तर सबसे अहम बिंदुओं में है। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के लिए वितरण हानि 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 23 प्रतिशत और मध्य क्षेत्र के लिए 24.5 प्रतिशत करने का प्रोजेक्शन दिया गया है। ऐसे में सवाल है कि इसका भविष्य के बिजली बिल पर कितना असर पड़ेगा। हालांकि वितरण हानि का आंकड़ा बढ़ने का अर्थ सीधे बिजली दर बढ़ना नहीं है। टैरिफ निर्धारण में बिजली खरीद लागत, ट्रांसमिशन व वितरण खर्च, संचालन-रखरखाव, पूंजीगत निवेश और राजस्व आवश्यकता सहित कई घटकों का परीक्षण होता है। इसके बाद आयोग अंतिम टैरिफ तय करता है। फिर भी अधिक हानि को स्वीकार किए जाने से बिजली आपूर्ति की कुल लागत और टैरिफ गणना पर असर पड़ना तय है।

20 हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च होने का अनुमान

जानकारी के मुताबिक मल्टी ईयर टैरिफ रेग्युलेशन के तहत आयोग पांच वर्षों के लिए हर साल की वितरण हानि का अनुमान मांगता है। कंपनी ने अगले 5 वर्षों की प्रोजेक्शन आयोग को दी है। ये आंकड़े वास्तविक स्थिति के आसपास रखे गए हैं। कंपनी वितरण हानि कम करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। केंद्र सरकार की आरडीएसएस योजना का उद्देश्य भी वितरण व्यवस्था को मजबूत कर हानि कम करना है। जानकारों को कहना है कि प्रदेश में लगभग 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च होने का अनुमान है। इसमें स्मार्ट मीटरिंग परियोजनाएं भी शामिल हैं। इन निवेशों का प्रमुख उद्देश्य तकनीकी और वाणिज्यिक हानि कम करना था। अग्रवाल का कहना है कि यदि बड़े निवेश के बाद भी हानि कम नहीं होती और भविष्य के लिए अधिक हानि का स्तर स्वीकार किया जाता है तो अतिरिक्त लागत का भार अंततः बिजली दरों के माध्यम से आम उपभोक्ता तक पहुंच सकता है।

आयोग में आने वाली आपत्तियां होंगी महत्वपूर्ण

वहीं अब एक सितंबर तक आयोग में आने वाली आपत्तियां महत्वपूर्ण होंगी। इनमें यह स्पष्ट हो सकेगा कि 14 से 23 और 24.5 प्रतिशत की प्रोजेक्शन का आधार क्या है और अगले 5 वर्षों में इसे कम करने की कार्ययोजना क्या है। अंतिम टैरिफ आदेश ही तय करेगा कि प्रस्तावित हानि का वास्तविक असर उपभोक्ताओं के बिजली बिल पर कितना पड़ता है।

रेलवे स्टेशन पर खड़े कोच में लगी भीषण आग, मची अफरा-तफरी

फायर ब्रिगेड की तत्परता से बुझी आग, जांच के लिए टीम गठित

जबलपुर (स्वतंत्र मत)

रेलवे स्टेशन पर खड़े एक कोच में मंगलवार सुबह अचानक आग लग गई। कोच से धुआं और आग की लपटें उठती देख रेलवे अधिकारियों को सूचना दी गई। इधर जानकारी मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे और दमकल को सूचना दी गई। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक

साइडिंग में खड़े एक रेलवे निरीक्षण कोच संख्या 075077 कोच में आग लगी थी, वह यात्रियों के इस्तेमाल में नहीं आता है। इसका उपयोग रेलवे द्वारा डिपार्टमेंटल और इंटरनल कार्यों के लिए किया जाता है। आग लगने के समय कोच में कोई यात्री मौजूद नहीं था। इस मामले को लेकर पश्चिम मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हर्षित श्रीवास्तव ने बताया कि कोच में आग लगने की घटना के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। मामले की जांच के लिए एक टीम गठित की जा रही है। जांच के बाद ही आग लगने की वास्तविक वजह सामने आ सकेगी।

शॉर्ट सर्किट होने की संभावना- रेलवे की त्वरित कार्यवाही के परिणामस्वरूप लगभग 15 मिनट के भीतर धुएं की स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया गया। इस घटना से किसी यात्री, कर्मचारी अथवा रेलवे संपत्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ तथा रेल परिचालन भी प्रभावित नहीं हुआ। प्रारंभिक जांच में धुआं स्टाफ केबिन क्षेत्र से स्थानीय स्तर पर निकलता हुआ पाया गया है। घटना के कारणों का पता लगाने के लिए शॉर्ट सर्किट, शरारती तत्वों की संभावित संलिप्तता सहित सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है। मामले की विस्तृत जांच हेतु वरिष्ठ अधिकारी स्तर की जांच के आदेश दिए गए हैं।

डैम में नहाते समय पश्चिम बंगाल के युवक की डूबने से मौत

कुंडम स्थित छीता खुदरी बांध का मामला, 48 घंटे बाद मिला शव

जबलपुर (स्वतंत्र मत)। शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर छीता खुदरी बांध में नहाते समय पश्चिम बंगाल का एक युवक डूब गया। घटना के बाद स्थानीय पुलिस, गोताखोरों और एसीडीआरएफ की टीम ने लगभग 48 घंटे तक लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया। इधर मंगलवार को बांध के दूसरे किनारे पर युवक का शव पानी में तैरता मिला। पुलिस ने पंचनामा कार्यवाही के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए कुंडम स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया है। मृतक की पहचान 35 वर्षीय शेख अब्दुल निवासी मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल के रूप में हुई है। वह जबलपुर में एक निजी प्लांट में काम करने के लिए आया था।

नहाते समय फिसला पैर- जानकारी के अनुसार शेख अब्दुल 9 अगस्त को छीता खुदरी बांध में नहा रहा था। इसी दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन तेज बहाव और गहराई के कारण सफलता नहीं मिली। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ ने युवक की तलाश शुरू की। बहरहाल पुलिस ने शव बरामद कर पंचनामा कार्यवाही पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए कुंडम स्वास्थ्य केंद्र भेजते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है।

कलेक्टर की जनसुनवाई में आए 122 आवेदन

जबलपुर (स्वतंत्र मत)। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में नागरिकों की समस्याएं सुनीं और संबंधित विभागों के अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। साप्ताहिक जनसुनवाई में आज नागरिकों से कुल 122 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें 43 दोबारा आए आवेदन भी शामिल थे। जनसुनवाई में आए आवेदनों में अनुग्रह सहायता राशि, अतिक्रमण, रिकॉर्ड सुधार, जर्जर मकान, मालिकाना हक दिलानेए धान का भुगतान, सीमांकन, नामान्तरण एवं बैंक शाखा से संबंधित शिकायत थे। जनसुनवाई के दौरान अपर कलेक्टर रविशंकर राय, एके सिंह, शैलेंद्र सिंह, डिप्टी कलेक्टर हिमांशु सोनी तथा सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

अल सुबह निगमायुक्त ने किया 2 संभागों का दौरा, दिए निर्देश

जबलपुर (स्वतंत्र मत)। निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार ने शहर में आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान की तैयारियों और सफाई व्यवस्था का निरीक्षण कर करने सुबह सुबह 2 संभागों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मध्य विधानसभा क्षेत्र में 14 अगस्त को आयोजित होने वाले शिविर की जानकारी दी और सभी व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि नागरिकों को बिना किसी परेशानी के शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके। निरीक्षण के दौरान निगमायुक्त ने बताया कि 14 अगस्त को विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को एक ही स्थान पर विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ प्रदान करना है। शिविर में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए जाएंगे, जहाँ पात्र हितग्राहियों के आवेदन जमा करने से लेकर उन्हें तत्काल लाभान्वित करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। संभागीय दौरे के दौरान निगमायुक्त ने अधिकारियों के साथ बैठक कर बैठक व्यवस्था, पेयजल, साफ-सफाई और हेल्पडेस्क प्रबंधन की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनविश्वास अभियान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी नोडल अधिकारियों को शिविर स्थल पर आवश्यक संसाधन तैनात रखने के निर्देश दिए ।

नहर में डूबने से अधेड़ की मौत

जबलपुर (स्वतंत्र मत)

तिलवारा थाने में धनराज कोकडे उम्र 31 वर्ष निवासी जोधपुर टोला ने सूचना देकर बताया कि उसके चाचा ससुर केशर मरावी नहाने के लिये जोधपुर टोला नहर में गये थे जो नहाते समय नहर के गहरे पानी में डूब गये। परिजनों व स्थानीय लोगों ने उनकी तलाश की। इसी बीच मंगलवार की आज सुबह नहर का पानी कम होने पर चाचा ससुर केशर मरावी उम्र 50 वर्ष निवासी जोधपुर टोला का शव पानी में उतराते मिला। सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में लिया है।

नॉन वेज ओवन में पकाया जा रहा था वेज पिज्जा

रसल चौक स्थित डोमिनोस पिज्जा रेस्टोरेंट में खाद्य विभाग की दबिश

जबलपुर (स्वतंत्र मत)

मिलावटी एवं दूषित खाद्य सामग्री के विक्रय पर सख्ती से रोक लगाने कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह के निर्देशानुसार चलाये जा रहे अभियान के तहत नगर निगम मजिस्ट्रेट एवं नगर निगम टीम के साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने आज मंगलवार को रसल चौक स्थित डोमिनोस पिज्जा रेस्टोरेंट का औचक निरीक्षण किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमित गुप्ता ने जानकारी देते हुये बताया कि निरीक्षण के दौरान इस प्रतिष्ठान के स्टोर मैनेजर की उपस्थिति में किचन और स्टोरजांच की गई और खाद्य लाइसेंस देखा गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक डोमिनोस पिज्जा रेस्टोरेंट में बेकिंग करने हेतु दो खंड पाए जिस पर एक में वेज दूसरे में नॉनवेज लिखा हुआ था, लेकिन मौके पर नॉनवेज वाले ओवन में वेज पिज्जा को बेक करते हुए पाया गया। उन्होंने बताया कि प्रतिष्ठान से बेक स्प्रिंकलर एवं चीज का नमूना संग्रहित कर परीक्षण हेतु राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेजा जा रहा है।

कालाबाजारी की भनक, सिहोरा पुलिस ने पकड़ी खाद की 90 बोरी

जबलपुर (स्वतंत्र मत)

जहां एक तरफ किसान खाद के लिए परेशान है वहीं दूसरी तरफ सिहोरा क्षेत्र में 90 बोरी खाद से भरी बोलेरो पिकअप पकड़े जाने से हडकंप मच गया। पकडे गए वाहन में 70 बोरी यूरिया और 20 बोरी डीएपी बरामद हुई। पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, यह खाद सहकारी विपणन समिति सिहोरा से खलरी स्थित कृषि केंद्र की ओर ले जाई जा रही थी। पूरे मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ज्योति परस्ते के निर्देशन पर सिहोरा थाने पहुंचे तहसीलदार सुरेश सोनी, नायब तहसीलदार विश्वास भंडारी, कृषि विभाग एसडीओ मनीषा पटेल और कृषि विकास अधिकारी जयपाल सिंह राठौर द्वारा मामले में घंटों तक थानें में बैठकर जांच करते रहे और जांच की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने सहकारी विपणन समिति सिहोरा के लिपिक सिद्धांत तिवारी और पटेल कृषि केंद्र के प्रोपराइटर नितेन्द्र पटेल के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, पूरे मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। वहीं किसानों का कहना है कि उन्हें खाद के लिए परेशान होना पड़ रहा है, जबकि दूसरी ओर इतनी बड़ी मात्रा में खाद के परिवहन का मामला सामने आने से साफ प्रतीत होता है। कि खाद की कालाबाजारी जमकर की जा रही है। जिसपर किसानों ने मांग कि है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर संलिप्त सभी दोषियों पर कठोर कार्यवाही की जाए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

स्कूल शिफ्ट करने के विरोध में सड़कों पर उतरे सैकड़ों छात्र, शिक्षकों ने दी फेल करने की धमकी

पाटन स्थित सांदीपनी स्कूल का मामला

सड़क पर किया चकाजाम

जबलपुर (स्वतंत्र मत)

पाटन क्षेत्र में संदीपनी स्कूल को लगभग 10 किलोमीटर दूर ग्राम सकरा में स्थानांतरित किए जाने के विरोध में मंगलवार को सैकड़ों छात्र पाटन चौराहे पर चक्काजाम कर जबलपुर-दमोह-भोपाल मार्ग बंद कर दिया। इधर अचानक बड़ी संख्या में स्कूली छात्रों के सड़क पर उतरने से पुलिस और प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही एसडीएम मानवेंद्र सिंह और पाटन थाना पुलिस समेत बड़ी संख्या में अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने छात्रों को समझाने का प्रयास किया। एसडीएम ने जल्द ही बसों की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद छात्रों को समझाने की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि पाटन में लंबे समय से संचालित संदीपनी स्कूल को स्कूल शिक्षा विभाग ने पाटन तहसील मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर ग्राम सकरा में शिफ्ट कर दिया है। नई बिल्डिंग का निर्माण भी शुरू हो चुका है। स्कूल को शहर से इतनी दूर ले जाने की जानकारी मिलने के बाद से ही छात्र और अभिभावक इसका विरोध कर रहे हैं।

घंटों तक प्रभावित रहा यातायात-प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि पाटन में स्कूल संचालित होने से आसपास के गांवों से आने वाले विद्यार्थियों के लिए आवागमन आसान था। अब स्कूल सकरा में शिफ्ट होने से गरीब और ग्रामीण परिवारों के बच्चों के सामने रोज स्कूल आने-जाने की समस्या खड़ी हो गई है। छात्रों की संख्या बढ़ने के साथ ही मार्ग पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। लगभग एक घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर छात्रों से बातचीत की और उनकी मांगों को सुना। प्रदर्शन कर रहे छात्र अभय प्रजापति ने आरोप लगाया कि जब छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, तब स्कूल के कुछ शिक्षक उनके पास पहुंचे और धमकी दी कि प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को टीसी दे दी जाएगी और फेल कर दिया जाएगा।

धमकी देकर रोकने का प्रयास - इधर छात्रों का कहना है कि इस तरह धमकी देकर उन्हें विरोध करने से रोकने की कोशिश की जा रही है। एसडीएम मानवेंद्र सिंह ने बताया कि छात्रों के प्रदर्शन की जानकारी मिलने के बाद स्कूल के प्राचार्य से बात की गई है। छात्रों की मुख्य मांग जल्द से जल्द बसों की व्यवस्था करने की है, ताकि छात्र-छात्राओं को स्कूल आने-जाने में परेशानी न हो। एसडीएम ने बताया कि बसों की व्यवस्था के लिए टेंडर जारी हो चुका है। प्रशासन का प्रयास है कि जल्द व्यवस्था शुरू कर विद्यार्थियों की समस्या का समाधान किया जाए।

हितकारिणी प्रकाशन प्रायवेट लिमिटेड के लिए **प्रकाशक एवं मुद्रक- राम असरानी** द्वारा प्रेस काम्पलेक्स सिविक सेंटर जबलपुर से प्रकाशित एवं हितकारिणी प्रिंटिंग प्रेस, सिविक सेंटर जबलपुर से मुद्रित. **प्रबंध सम्पादक- सुबोध दुबे, सम्पादक- राजेन्द्र मिश्रा,** *पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयनार्थ उत्तरदायी।
ई-मेल-**smatjbp1@ gmail.com,** फोन- 0761-2411414, 4032436 समस्त विवाद जबलपुर न्यायालयाधीन. पोस्टल रजि. नं. एसएसपी जबलपुर/13/2026-28, **RNI No. 64561/96.**